



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 2018/वैशाख 3, 1940

No. 146]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 2018/VAISAKHA 3, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटन-रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

अंतिम जांच परिणाम

विषय : इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क की जांच।

फा.सं. 14/51/2016-डीजीएडी.—यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड (जिन्हें आगे "याचिकादाता" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत करने और पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी द्वारा अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की गई, ताकि उपरोक्त देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

3. याचिकादाता ने जांच अवधि के लिए अप्रैल, 2015 से जून, 2016 तक की अवधि का प्रस्ताव किया था। इस अवधि के दौरान सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का अंशदान 3 प्रतिशत से भी अधिक था। तथापि, प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक (12 माह) की अवधि को जांच अवधि माना है, तकि हाल ही के आंकड़ों के आधार पर पाटन और क्षति का विश्लेषण किया जा सके। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक की अवधि ऐसी अवधि है, जब कंपनी एक डीटीए यूनिट थी और वह याचिकादाता के प्रयोजनार्थ लेखाकरण का वित्तीय वर्ष है। जांच शुरू करने के बाद और जांच की कार्यवाही के दौरान सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा को प्राधिकारी द्वारा मानी गई जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों के तीन प्रतिशत से कम पाया गया था। तदनुसार नियमावली के नियम 14 (घ) के अनुसार संबद्ध देशों में से सऊदी अरब को बाहर निकाल दिया गया है तथा केवल इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की है।

क. क्रिया-विधि

4. प्राधिकारी द्वारा इस जांच में निम्नोक्त क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (क) निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से याचिकादाता से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स” के पाटन होने का आरोप लगाया गया था।
- (ख) आवेदन-पत्र की प्रारंभिक जांच करने से कुछ कमियों का पता चला था जिन्हें बाद में याचिकादाता द्वारा आशोधित कर दिया गया था और याचिकादाता द्वारा संशोधित और अद्यतन याचिका प्रस्तुत की गई थी। इसलिए जांच शुरू करते समय आवेदन-पत्र को दस्तावेजों सहित विधिवत् प्रस्तुत की गई याचिका माना गया था।
- (ग) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार जांच की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व वर्तमान पाटन-रोधी आवेदन-पत्र के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया था।
- (घ) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के बारे में पाटन-रोधी जांच शुरू करने की दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई थी।
- (ङ) प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ याचिकादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को भी प्रेषित की गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे जांच शुरू करने की अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्राधिकारी को लिखित रूप से अपने विचारों से अवगत करा दें।
- (च) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध दूतावासों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की एक प्रति प्रदान की थी।
- (छ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे अपने देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत कर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए

पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों की प्रति के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों भी भेजी गई थी।

(ज) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक (12 महीने) मानी गई है। क्षति अवधि में वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 तथा जांच की अवधि भी शामिल है।

(झ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

1. मेसर्ज म्यूजिम मेस. इंडोनेशिया
2. मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स, इंडोनेशिया
3. मेसर्ज एमर्जी ओलियोकेमिकल्स, मलेशिया
4. मेसर्ज केएलके ओलियो, मलेशिया
5. मेसर्ज एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
6. मेसर्ज थाई ओलियोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
7. मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
8. मेसर्ज एसएबीआईसी एशिया पसिफिक प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
9. मेसर्ज सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब
10. मेसर्ज सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (सेबिक), सऊदी अरब

(ञ) प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की समय अवधि को पहले 26 जून, 2017 तक बढ़ाया था और बाद में दिनांक 23 जून, 2017 के पत्र द्वारा उसे 3 जुलाई, 2017 तक बढ़ा दिया था।

(ट) निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड, इंडोनेशिया
2. मेसर्ज इंटर-कोटिनेंटल ऑयल्य एंड फैट प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
3. मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स, इंडोनेशिया
4. मेसर्ज इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर.
5. मेसर्ज केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
6. मेसर्ज एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी
7. मेसर्ज प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर
8. मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
9. मेसर्ज एसएबीआईसी एशिया पसिफिक प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर
10. मेसर्ज सऊदी कयान पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब
11. मेसर्ज सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (सेबिक), सऊदी अरब
12. मेसर्ज विल्मार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, सिंगापुर
13. मेसर्ज पीटी विल्मार नवाटी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया

पाटन-रोधी नियमावली के नियम 14 (घ) के प्रावधानों के अनुसार सऊदी अरब को इस जांच में से निकाल दिया गया है। प्राधिकारी ने सऊदी अरब से निर्यातकों से प्राप्त हुए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों पर विचार नहीं किया है।

(ठ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

1. मेसर्ज गेलेक्सी सफकिन्ट्स लिमिटेड, नवी मुंबई
2. मेसर्ज विश्वात केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई
3. मेसर्ज रोहडिया स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, मुंबई
4. मेसर्ज इंडियन ग्लायकोल्स लिमिटेड, नोएडा
5. मेसर्ज स्टर्लिंग ऑक्सिलियरीज प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई
6. मेसर्ज मटांगी इंडट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद
7. मेसर्ज वीनस ऐथोक्सीलेट्स प्राईवेट लिमिटेड, गोवा
8. मेसर्ज गुजरात केमिकल्स, सूरत
9. मेसर्ज आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
10. मेसर्ज कुसा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई
11. मेसर्ज कृष्णा ऑटोलोक्सीडिएन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई
12. मेसर्ज मजोरहब ओलियोकेमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई
13. मेसर्ज हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (एचयूएल), मुंबई
14. मेसर्ज पान ओलियो इंटरप्राईज प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई
15. मेसर्ज केविनकरे प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई
16. मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई

(ड) निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्धारित प्रपत्र में आयातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. मेसर्ज इंडियन ग्लायकोल्स लिमिटेड, नोएडा
2. मेसर्ज एटर्निस फाईन केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई
3. मेसर्ज गेलेक्सी सफकिन्ट्स लिमिटेड, नवी मुंबई

(ढ) प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध कराया है।

(ण) क्षति अवधि के दौरान डीजीसीआईएंडएस से कारोबार-वार आंकड़ों को प्राप्त किया गया है और वर्तमान जांच में उन पर विश्वास किया गया है।

(त) जितना आवश्यक समझा गया था, याचिकादाता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी द्वारा जितना आवश्यक समझा गया था, घरेलू उद्योग और निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना का

- सत्यापन किया गया था। केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर जहां कहीं भी लागू होता है, आवश्यक संशोधन सहित वर्तमान जांच के परिणाम के प्रयोजनार्थ विश्वास किया गया है।
- (थ) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (द) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए 11 जनवरी, 2018 को एक मौखिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई के समय जिन सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के उत्तर देने का भी अवसर प्रदान किया गया था।
- (ध) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया गया है और जहां कहीं भी प्रासंगिक हुआ है, प्राधिकारी द्वारा इस परिणाम में उनका निदान किया गया है।
- (न) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।
- (प) भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और उनको निर्मित करने और बेचने के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और आकलन किया गया है, ताकि क्षति मार्जिन का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा क्षति रहित कीमत का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।
- (फ) 26.3.2018 को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्य निहित थे और जिसमें प्रकटन विवरण पर यदि कोई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी हैं तो उसके लिए 04.04.2018 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात विवरण पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर उचित ढंग से विचार किया है।
- (ब) इस प्रकटन विवरण में हितबद्ध पक्षकार द्वारा *** सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर उसी प्रकार से विचार किया गया है।
- (भ) इस जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 67.95 रूपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु"

5. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 'सभी प्रकार के सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स हैं, जिनमें केप्रियल अल्कोहल (सी8), और डेजिल अल्कोहल (सी10), और सी-8 और सी-10 शामिल हैं।

ख.1 घरेलू उद्योग के निवेदन

6. विचाराधीन उत्पाद और "समान वस्तु" के कार्य-क्षेत्र के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) फैटी अल्कोहल्स एलीफैटिक अल्कोहल्स हैं और ये सेच्युरेटिड और गैर- सेच्युरेटिड रूप में होते हैं। इस उत्पाद के लिए सामान्य रसायनिक नुस्खा सीएनएच(2एन+1)सीएच2ओ एच है, जिसमें "एन" की सीमा 7 से 17 तक होती है। फैटी अल्कोहल्स के बनावट की सामग्री डिकेन-1ओएल, एन-डोडिकेनोल, टेट्रा-डिकेनोल, हेक्साडिकेन-1-ओएल,

- ओक्टाडिकेनोल, एल्कोसेन-1-ओएएल होती है। इन अल्कोहल्स को कार्बन एटम्स की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है और अत्यंत सामान्य लंबाई सी 12, सी 14 और उनके ब्लैंड्स होते हैं।
- (ख) फैटी अल्कोहल्स हाई बॉयलिंग द्रव अथवा सॉफ्ट रंगहीन ठोस रूप में होते हैं, जो कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर करते हैं। इनका उपयोग मुख्यतया मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में फैटी अल्कोहल्स सल्फेट्स, फैटी अल्कोहल एथोक्सिलेट्स और फैटी अल्कोहल ईथर सल्फेट्स जिसे सर्फैक्टेंट्स भी कहा जाता है, में और संसाधित किए जाने के लिए किया जाता है।
- (ग) फैटी अल्कोहल्स को मिश्रित अथवा गैर-मिश्रित किया जा सकता है। गैर-मिश्रित फैटी अल्कोहल्स को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 2905.17 अथवा 2905.19 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जब कि मिश्रित फैटी अल्कोहल्स को शीर्ष 3823.70 में शामिल किया जाता है।
- (घ) फैटी अल्कोहल्स को फ्लेक्स, पेस्टाईल्स और द्रव के रूप में बेचा जाता है। जैसा ऊपर बताया गया है, इन अल्कोहल्स को विभिन्न कार्बन श्रृंखला लंबाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- (ङ) चूंकि इस उत्पाद को विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित किया जा सकता है, जो कि कार्बन श्रृंखला लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए कार्बन श्रृंखला किस्म के आधार पर उसका पृथक्करण करने और 4 अंकों की उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया गया था ताकि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बीच उचित तुलना करने के साथ-साथ सामान्य और निर्यात कीमत की तुलना की जा सके।
- (च) पाटित उत्पाद याचिकादाता द्वारा उत्पादित सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स के समान है तथा पाटित उत्पाद और याचिकादाता द्वारा विनिर्मित समान उत्पाद के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। संबद्ध वस्तुएं वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से याचिकादाता द्वारा उत्पादित समान उत्पादों के प्रतिस्थापनीय हैं। पाटित उत्पाद और याचिकादाता द्वारा उत्पादित समान वस्तु को सर्फैक्टेंट्स और अन्य उत्पादों के समान उपभोक्ताओं/ विनिर्माताओं द्वारा समान अथवा सदृश अनुप्रयोगों के लिए खरीदा और बेचा जाता है।
- (छ) जब कि याचिकादाता के पास फैटी अल्कोहल्स के शुद्ध सी8 और सी10 रूप के उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है, उसे इन ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि भारत में इन वस्तुओं की मांग बहुत कम है।
- (ज) तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस आशय के तर्कों के संबंध में कि फैटी अल्कोहल्स के शुद्ध सी12 और सी14 रूप के उत्पादों को भी बाहर रखा जाना चाहिए, यह निवेदन किया गया था कि ऐसे ग्रेडों को इस कारणवश बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि सी12सी14 रूप के उत्पादों की भारत में अत्यधिक मांग है। यदि इन ग्रेडों को बाहर रखा जाता है, तो आयातक सी12 और सी14 रूप के उत्पादों का आयात करेंगे और उन्हें भारत में एक सरल रसायनिक प्रक्रिया से सी12सी14 में मिश्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त ये ग्रेड उत्पादित अन्य ग्रेडों के साथ वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार इन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ख.2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन

7. विचाराधीन उत्पाद और “समान वस्तु” के कार्य-क्षेत्र के बारे में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) फैटी अल्कोहल्स के शुद्ध रूप जैसे कि केप्रियल अल्कोहल (सी8), डेजिल अल्कोहल (सी10), लोरिल अल्कोहल (सी12) और मेरीस्टाईल अल्कोहल (सी-14) जिनका याचिकादाता द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है और वाणिज्यिक आपूर्ति नहीं की जाती है, को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

- (ख) इसी प्रकार याचिकादाता द्वारा विशेष रूप से उत्पादित नहीं की जाने वाली कार्बन श्रृंखलाओं के मिश्रणों को भी बाहर रखा जाना चाहिए।
- (ग) घरेलू उद्योग न तो प्योर कट्स का उत्पादन करता है और न ही उसके पास उनका उत्पादन करने की क्षमता है। याचिकादाता द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्योर कट्स के बीच वाणिज्यिक और प्रोद्योगिकीय प्रतिस्थापन क्षमता की कमी है।
- (घ) उत्पाद श्रृंखला, क्षमता और वास्तविक उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का प्रकटन सभी पक्षकारों के समक्ष किया जाना चाहिए।
- (ङ) उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली के उत्तरों में प्रयुक्त पीसीएन कार्य-प्रणाली के आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि प्राधिकारी द्वारा पीसीएन कार्य-प्रणाली अपनाई गई है, तो यह सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे उन पर सार्थक टिप्पणियां दे सकें।

3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तु के दायरे के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को नोट कर लिया है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी निम्नोक्त अनुसार नोट करते हैं:-

- (क) घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए फैटी अल्कोहल्स सी8 और सी10 के शुद्ध रूपों के उत्पादों और सी8सी10 अल्कोहल को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को "सी12, सी14, सी16 और सी18 की कार्बन श्रृंखला सहित सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स में संशोधित कर दिया गया है, जिसमें एकल, मिश्रित और गैर-मिश्रित (ब्रांच्ड इसोमेर्स रहित), सी12-सी14, सी12-सी16, सी-12-सी-18, सी-16-सी-18 और सी14-सी16 की कार्बन श्रृंखला के मिश्रण के सम्मिश्रण शामिल हैं"।
- (ख) अत्यधिक सावधानी के साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि अन-सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स को वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- (ग) उपरोक्त संबद्ध वस्तुएं एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं और ये सेच्युरेटिड और अन-सेच्युरेटिड रूप में होती हैं। इस उत्पाद के लिए सामान्य रसायनिक नुस्खा सीएनएच(2एन+1)सीएच2ओएच है, जिसमें "एन" की सीमा 7 से 17 तक होती है। फैटी अल्कोहल्स के बनावट की सामग्री डिकेन-1ओएल, एन-डोडिकेनोल, टेट्रा-डिकेनोल, हेक्साडिकेन-1-ओएल, ओक्टाडिकेनोल, एल्कोसेन-1-ओएल होती है। इन अल्कोहल्स को कार्बन एटम्स की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है और अत्यंत सामान्य लंबाई सी 12, सी 14 और उनके ब्लैंड्स होते हैं।
- (घ) संबद्ध वस्तुओं को फैटी अल्कोहल्स को फ्लेक्स, पेस्टाईल्स और द्रव के रूप में बेचा जाता है। इनका मुख्यतया उपयोग सर्फैक्टेंट्स विनिर्मित करने, निजी देख-भाल, गृह की देख-भाल, फार्मस्युटिकल और कृषि संबंधित अंतः अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। साथ ही इनका उपयोग चमड़े की वस्तुओं, टेक्सटाईल, फर, पल्प, कागज, पेट्रोलियम उत्पादों, परिष्कृत रसायनों, रबड़ उत्पादों, प्लास्टिक्स और फैब्रिकेटिड धात्विक उत्पादों के लिए भी किया जाता है। इसके अन्य अनुप्रयोगों में खनन, समुद्री प्रचालन, निर्माण कार्य आदि शामिल हैं, जिनमें इन्हें विलय और डिग्रीसिंग करने के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाता है। सी12-सी16 फैटी अल्कोहल्स के मिश्रण का अतिरिक्त उपयोग सिंथेटिक मध्यवर्ती पदार्थों अथवा एंटी-फ्रीज और एम्युल्सीफाईंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पैंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स, खाद्य तैयार करने आदि में भी किया जाता है।

- (ड) गैर-मिश्रित फैटी अल्कोहल्स को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के शीर्ष 2905.17 अथवा 2905.19 के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जब कि मिश्रित फैटी अल्कोहल्स को शीर्ष 3823.70 में शामिल किया जाता है। शीर्ष 3823.70 के अंतर्गत इनका आयात निम्नोक्त टैरिफ प्रविष्टियों में किया जाता है:-

(1) 3823.70.10

(2) 3823.70.20

(3) 3823.70.40

(4) 3823.70.90

सीमा-शुल्क का उपरोक्त वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

- (च) फैटी अल्कोहल्स के सी8 और सी10 के रूप के उत्पाद का बहिष्करण इसलिए आवश्यक है क्योंकि घरेलू उद्योग ने फैटी अल्कोहल्स अथवा ऐसे उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है, जिसे इन ग्रेडों के समान वस्तु माना जा सकता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सी8/सी10 और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीय क्षमता की कमी के बारे में निवेदन किए हैं। घरेलू उद्योग ने इन निवेदनों का खंडन नहीं किया है। वस्तुतः घरेलू उद्योग द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इन्हें बाहर रखा जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकारी विभिन्न पक्षकारों के निवेदनों को नोट करते हैं और इन ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना उचित समझते हैं।
- (छ) सी12 और सी14 अल्कोहल्स को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को प्रबल समझते हैं कि उसने सी12/सी14 अल्कोहल्स का उत्पादन किया है और उसे बेचा है। वास्तव में सी12/सी14 की भारत में अत्यधिक मांग है। जब घरेलू उद्योग ने इन अल्कोहल्स के मिश्रित रूप को बेचा है, तो उसके शुद्ध रूप को बाहर नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार ऐसा बहिष्करण शुल्क के प्रयोजन को पूरा नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी महानिदेशक, सुरक्षा के अंतिम जांच परिणाम को भी नोट करते हैं कि ये मर्दे प्रतिस्थापनीय हैं और एक समान विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा समान कच्चे माल से मूल रूप से विनिर्मित होती हैं। इस प्रकार फैटी अल्कोहल्स के सी12 और सी14 ग्रेडों को बहिष्कृत करने का कोई औचित्य नहीं है।
- (ज) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी ने प्रत्येक ग्रेड के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) निर्धारित की है। यह नोट किया गया था कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने याचिका के चरण में घरेलू उद्योग द्वारा सुझाई गई पीसीएन कार्य-प्रणाली के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की थी। इस प्रकार प्राधिकारी ने याचिका में सुझाई गई कार्य-प्रणाली को प्रयुक्त करने का विकल्प अपनाया है।
- (झ) इस तर्क के संबंध में कि टिप्पणियों के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन की कार्य-प्रणाली उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, यह नोट किया जाता है कि याचिकादाता द्वारा स्वतः याचिका में कार्य-प्रणाली को वर्णित किया गया है। इस प्रकार हितबद्ध पक्षकारों के पास इस संबंध में टिप्पणी देने का पर्याप्त अवसर था।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का विचाराधीन उत्पाद के बारे में निष्कर्ष निम्नानुसार है :

‘सभी प्रकार के सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स जिनमें केप्रियल अल्कोहल (सी8), और डेजिल अल्कोहल (सी10), और सी-8 और सी-10 शामिल हैं’ ।

10. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग के उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात वस्तुपरक अंतर नहीं है। संबद्ध वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से याचिकादाता द्वारा उत्पादित उत्पादों के प्रतिस्थापनीय हैं तथा उन्हें सर्फेकेटेन्ट्स और अन्य उत्पादों के समान उपभोक्ताओं/ विनिर्माताओं द्वारा समान अनुप्रयोगों के लिए उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं को “समान वस्तु” के रूप में माना है।

ग. घरेलू उद्योग और उसका आधार

11. वर्तमान याचिका मेसर्ज वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक घरेलू उत्पादक है।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

12. घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में इस जांच की कार्यवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) याचिकादाता के अतिरिक्त मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। तथापि, मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इसलिए नियम 2 (ख) के अनुसार उसे घरेलू उद्योग के अधिकार-क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाना चाहिए और याचिकादाता को समान उत्पाद के 100% उत्पादन करने वाला उत्पादक माना जाना चाहिए।
- (ख) फिर भी यदि मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बहिष्कृत नहीं किया जाता है, तो भी कुल घरेलू उत्पादन में याचिकादाता का उत्पादन प्रमुख अंश बनेगा, जो कि 65% है और इसलिए वह नियमावली के नियम 2 (ख) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में पात्र होगा।

ग.2 निर्यातकों/, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

13. हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि इसका विश्लेषण करने के लिए कि क्या मेसर्ज गोदरेज द्वारा आयात की गई मात्रा उसके बहिष्करण के लिए यथोचित है, मेसर्ज गोदरेज के लिए आयात आंकड़े प्राप्त किए जाने चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. घरेलू उद्योग के दायरे और वर्तमान याचिका को प्रस्तुत करने के लिए याचिकादाता के आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान निम्नानुसार किया गया है:-

- (क) नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार प्राधिकारी ऐसे उत्पादकों को बहिष्कृत कर सकते हैं, जो कि आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। याचिकादाता का यह आरोप है कि जांच अवधि के दौरान मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और इसलिए उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसे घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया है। मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्राधिकारी के साथ हुए एक पत्राचार में स्वतः इसे स्वीकार किया है कि वे सर्फेकेन्ट्स के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए सी-12 और सी-14 के नियमित आयातक हैं और चूंकि कुल घरेलू उत्पादन में याचिकादाता का 60% भाग बनता है, इसलिए उन्हें पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया है।
- (ख) फिर भी इस तर्क के संबंध में कि क्या मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बहिष्कृत किया जाना यथोचित है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि उत्पादक को एक पात्र घरेलू उद्योग माना जाता है, तो भी याचिकादाता का उत्पादन, कुल घरेलू उत्पादन का 60% भाग बनेगा। इस प्रकार मेसर्ज गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पात्रता से संबंधित मुद्दे का याचिका को बनाए रखने की याचिकादाता की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ग) चूंकि कुल घरेलू उत्पादन में याचिकादाता का प्रमुख अंश होता है, जो कि अंशदान पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 (3) में उल्लिखित अनुसार 25% के निर्धारित मानक से भी अधिक है, वह नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित आधार के मानदंड को संतोषजनक ढंग से पूरा करता है।

घ. गोपनीयता**घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

15. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) निर्यातकों और उत्पादकों ने गोपनीयता के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है और वे मूलभूत सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं। उदाहरणतः उत्पादन विनिर्देशन, उत्पाद संहिता प्रणाली, शेयरधारिता का ढांचा, संबंधित पक्षकारों के व्यौरे, वितरण के माध्यम और अन्य ऐसे विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
 - (ख) अधिकतर मामलों में प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उदाहरणतः निर्यातकों और उत्पादकों ने प्रस्तुत किए गए प्रतिदर्श दस्तावेजों के नामों का प्रकटन नहीं किया है, बिक्रियों और उत्पादन की लागत से संबंधित सूचीबद्ध सूचना तथा घरेलू और विदेशी बाजारों में कीमत के ढांचों के व्यौरे प्रदान नहीं किए हैं।
 - (ग) यदि प्रदान की गई सूचना, व्यवसाय के प्रति संवेदी प्रकृति की नहीं होती है, जैसे कि उसके प्रकटन करने से प्रतिवादी पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में संबद्ध सूचना के प्रकटन पर बल दिया जाना चाहिए।
 - (घ) घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के आरोपों का खंडन करते हुए यह निवेदन किया गया था कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सूचना का अगोपनीय संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है।

घ. 2 निर्यातकों/ आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

16. निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि याचिकादाता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और वह सामान्य मूल्य की संरचना के लिए प्रयुक्त खपत के कारकों, सामान्य मूल्य के परिकलन, ग्रेड-वार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, मालसूचियों, क्षति-रहित कीमत और लागत के फोर्मेट्स के संबंध में अगोपनीय संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है। विशेषकर याचिकादाता प्रपत्र “ख” से “ड” में निहित आंकड़ों का अगोपनीय संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त निम्नोक्त तर्क भी दिए गए हैं:
- (क) यह प्राधिकारी का दायित्व है न कि घरेलू उद्योग का कि वह निर्यातकों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों की जांच करें।
 - (ख) किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया दावा अस्पष्ट और गलत है।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. गोपनीयता के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जितना प्रासंगिक समझा गया था, प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उनका निदान कर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने कारोबार से संबंधित सूचना को गोपनीय माना है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

ड. विविध मुद्दे**ड. 1 निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन**

18. निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) प्राधिकारी को जांच शुरू करने से पहले जांच अवधि के लिए पाटन और क्षति के विद्यमान होने की जांच करनी आवश्यक होती है। चूंकि जांच की शुरुआत जांच की भिन्न अवधि के लिए आंकड़ों के आधार पर की गई थी, जो कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 और पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत प्राधिकारी के दायित्वों का उल्लंघन है।
- (ख) जांच शुरू करने को यथोचित ठहराने के लिए याचिकादाता द्वारा उद्धृत न्यायशास्त्र नामतः गुआटेमाला का मामला अप्रासंगिक था क्योंकि उस मामले में क्षति की जांच अवधि को बढ़ा दिया गया था, जबकि वर्तमान मामले में जांच की अवधि को इस कारणवश पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया गया था कि यह बहुत पुरानी थी और याचिकादाता एक 100% निर्यातोन्मुख एकक (ईओयू) था।
- (ग) चूंकि याचिकादाता पहले एक 100% निर्यातोन्मुख एकक (ईओयू) था, इसलिए जांच अवधि परिवर्तित कर दी गई थी। ऐसी अवधि के दौरान याचिकादाता एक घरेलू उद्योग के रूप में योग्य होने का पात्र नहीं था।
- (घ) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने निर्यात कीमत के परिकलन के लिए किए गए समायोजनों को प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार याचिकादाता ने संबद्ध वस्तुओं के पाटन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए उसने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है।
- (ङ) चूंकि सऊदी अरब से आयात, समान वस्तु के कुल आयातों के 3% से कम हैं, इसलिए पाटन-रोधी नियमावली के नियम 14 (घ) के अनुसार सऊदी अरब के खिलाफ जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (च) पाटन-रोधी विधि के अनुसार पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत जांच शुरू करने के समय संबद्ध देशों को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- (छ) यह तथ्य कि सऊदी अरब से आयातों की मात्रा, 3% से कम है, याचिका की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है और क्या जांच शुरू करने से पहले पर्याप्तता और परिशुद्धता की जांच की गई थी।
- (ज) याचिका में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि महानिदेशक, सुरक्षा के समक्ष पुनरीक्षा के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था। जब महानिदेशक, सुरक्षा ने उचित जांच के बाद पुनरीक्षा के आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया था, तब प्राधिकारी के लिए आर्थिक क्षति के समनुरूप दावे को स्वीकार करना असंगत है।
- (झ) याचिकादाता ने सुरक्षा शुल्क की समाप्ति से ठीक पहले पाटन-रोधी शुल्कों को लागू करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है। ऐसी कार्रवाई का प्रयोजन निर्यातक के व्यापार को विकृत करने के लिए याचिकादाता की अप्रतिस्पर्धात्मकता में परिवर्तन नहीं कर सकता है।
- (ञ) घरेलू उद्योग निचले स्तर के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त शुल्क लागू किए जाने के परिणाम स्वरूप निचले स्तर के उद्योग अप्रतिसपर्धी हो जायेंगे। यदि एक आपूर्तिकर्ता के संरक्षण के लिए शुल्क लगाया जाता है, तो इससे निचले स्तर के सैंकड़ों मूल्य संवर्धित आपूर्तिकर्ता प्रभावित होंगे।
- (ट) शुल्क लगाना निचले स्तर के व्युत्पन्नों के आयातों को आमंत्रित करना है, जैसा कि सुरक्षा शुल्क लगाने की अवधि के दौरान देखा गया है।
- (ठ) फैटी अल्कोहल्स की आपूर्ति में कटौती होने से वर्ष 2018 में कीमतों में तेजी से अत्यधिक वृद्धि होने ऐसी संभावना होगी।

- (ड) कच्चे माल की कमी होने के कारण याचिकादाता का प्रदानगी का समय अत्यधिक लंबा है। तथापि, जैसे कि चिंता की जा रही है, याचिकादाता की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होता है। पाटन-रोधी शुल्कों को लागू करने से निचले स्तर के उद्योगों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (ढ) घरेलू उद्योग निकृष्ट वित्तीय स्थिति और उच्च लागत की प्रौद्योगिकी के कारण निचले स्तर के प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है।
- (ण) जन हित के संबंध में महानिदेशक, सुरक्षा के अंतिम जांच परिणाम वर्तमान जांच से संबद्ध नहीं हैं।
- (त) प्रत्येक ग्रेड अथवा उत्पाद संहिता के लिए पृथक रूप से शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए और न कि भारित औसत के आधार पर।
- (थ) इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या याचिकादाता ने निकटस्थ दूरी पर स्थित इंडोनेशिया में अपने संयंत्र से कच्चे माल की खरीददारी की है।
- (द) घरेलू और निर्यातक विक्रियों के लिए विक्रियों की लागत में बहुत अंतर व्याप्त है, जिससे प्रदत्त आंकड़ों में असंगति होने का पता चलता है।
- (ध) याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में असंगतियां व्याप्त हैं। उदाहरणतः जबकि कुल मूल्यहास और घरेलू मूल्यहास समान बना हुआ है, कुल ब्याज और घरेलू प्रचालनों को देय ब्याज में व्यापक अंतर था।
- (न) याचिका में असंगति होने का विशेष रूप से उल्लेखनीय एक मामला यह है कि जबकि निबल अचल परिसम्पत्तियों में 62% तक की वृद्धि हुई है, मूल्यहास 81% तक घट गया है।
- (प) जबकि क्षति अवधि के दौरान कुल ब्याज में कमी हुई है, घरेलू प्रचालनों के लिए ब्याज में वृद्धि हुई है, जिससे आंकड़ों में असंगति होने का पता चलता है।
- (फ) लागत में 36% तक की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप बिक्री कीमत में 41% तक की वृद्धि होने से याचिकादाता के प्रति यूनिट घाटे में 5% तक की वृद्धि नहीं हो सकती है।
- (ब) जांच अवधि के दौरान उपयोगिता की कमी के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है। इसके बावजूद जांच अवधि के दौरान समायोजित लाभ/हानि में परिवर्तन हुआ है।
- (भ) समायोजित लाभ वास्तविक लाभ से अधिक है, जबकि समायोजित नकदी लाभ वास्तविक लाभ से कम है। इन आंकड़ों की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- (म) मलेशिया के लिए याचिकादाता द्वारा किया गया पहुंच मूल्य का दावा, मूल्यांकन करने योग्य मूल्य से कम है, जो कि संभव नहीं है।
- (य) याचिका में दिए गए आयात के आंकड़े सही नहीं थे। प्राधिकारी को याचिकादाता के मूल्य को उसकी परिशुद्धता की बराबर जांच किए बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- (र) चूंकि याचिकादाता की उत्पादन प्रक्रिया में दो चरण निहित हैं, अर्थात्, इंडोनेशिया और भारत में, इसलिए व्ययों के आबंटन की जांच ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए।
- (ल) बिक्री कीमत, विक्रियों की लागत, लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर लाभप्रदता सही प्रतीत नहीं होती है।

इ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) पक्षकारों के लिखित निवेदनों को जो कि प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए किए गए हैं, रिकार्ड में नहीं लिया जाना चाहिए।

- (ख) गुआटेमाला से स्टील पाईप्स और ट्यूब्स पर मेक्सिको-पाटन-रोधी शुल्कों के मामले में पेनल ने यह पाया था कि जांच प्राधिकारियों के लिए यह उचित नहीं था कि वे जांच शुरू किए जाने से पूर्व आठ महीनों के समाप्त होने पर आंकड़ों के सेट पर विश्वास करें। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने अनेक मामलों में जांच शुरू करने के समय जांच की अवधि में परिवर्तन किया है।
- (ग) नियम 2 (ख) एक 100% निर्यातोन्मुख एकक (ईओयू) को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस प्रकार याचिकादाता याचिका प्रस्तुत करने के लिए पात्र था। यह प्राधिकारी की विगत पद्धति के भी समनुरूप है।
- (घ) याचिकादाता ने ऐसे समस्त आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो कि याचिका प्रस्तुत करने समय उसके पास उपलब्ध थे। जैसा कि माननीय सेस्टेट ने टायर विनिर्माता एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी {2011 (270) ई.एल.टी. 727 (टी)} के मामले में निर्णय दिया था कि संरचित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के संबंध में याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य को दोष युक्त नहीं माना जा सकता है और जांच शुरू करना नियम 5 का उल्लंघन नहीं था।
- (ङ) यदि सत्यापन सहित उचित जांच करने और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा निर्यातों के समाधान किए जाने के बाद यह पाया जाता है कि उनसे आयात 3% से कम हैं, तो सऊदी अरब के खिलाफ जांच को समाप्त करने पर घरेलू उद्योग को कोई आपत्ति नहीं है।
- (च) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था निहित है कि जांच शुरू करने के बाद किसी भी देश के खिलाफ जांच को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह गलत है कि जांच शुरू करने के चरण में संबद्ध देशों के अंश को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विश्व भर में जांच प्राधिकारियों द्वारा अनेक मामलों में जांच शुरू करने के बाद किसी विशेष देश के खिलाफ जांच को समाप्त किया गया है।
- (छ) याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए दिनांक 15 फरवरी, 2017 के पत्र में इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि सुरक्षा शुल्क की पुनरीक्षा करने के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था।
- (ज) इस संबंध में टिप्पणियों के उत्तर में यह निवेदन किया गया था कि ऐसा आरोप लगाने का कोई आधार नहीं था कि जबकि महानिदेशक, सुरक्षा ने आंकड़ों की जांच की है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दावों को स्वीकार मात्र किया है।
- (झ) यह कारण मात्र कि घरेलू उद्योग ने आयातों में अचानक आए उछाल को देखते हुए महानिदेशक, सुरक्षा से अनुरोध करने का विकल्प अपनाया है, पाटन के कारण हुई क्षति को दूर करने के लिए बाद में उसे प्राधिकारी से संपर्क करने से प्रतिबाधित नहीं करता है।
- (ञ) इन तर्कों का कोई आधार नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के फलस्वरूप निचले स्तर के उत्पादों के आयात में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त मात्र इस आधार पर कि निचले स्तर के उत्पादों के आयात में वृद्धि होगी, घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण होने वाली क्षति सहने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।
- (ट) इस तर्क के उत्तर में कि वर्ष 2018 में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, यह निवेदन किया गया था कि रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि विश्व भर में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति हुई है। इसके अतिरिक्त ऐसे अनुमानों के आधार पर घरेलू उद्योग को संरक्षण से मना नहीं किया जा सकता है।
- (ठ) इस आरोप का कोई औचित्य नहीं है कि घरेलू उद्योग समय पर अपने आदेशों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। यदि ऐसा होता, तो घरेलू उद्योग की विक्रियों के वृद्धि नहीं हुई होती। फिर भी पाटन-रोधी शुल्क लगाने का प्रयोजन वस्तुओं के पाटन द्वारा निर्यातकों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर करना मात्र है।
- (ड) यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की समर्थता के संबंध में अनिश्चितता, निरंतर चिंता का बनी हुई है, जो कि पाटन-रोधी शुल्क को तात्कालिक आधार पर लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- (ढ) प्राधिकारी को बीएसआर एंड कंपनी से अंतरण कीमत रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित कंपनी के साथ लेन-देन निकटस्थ दूरी के आधार पर किया गया है।

- (ण) जबकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ग्रेड-वार आधार पर लागू किया जाता है, उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना है, न कि पृथक रूप से उत्पाद की किस्मों पर।
- (त) चूंकि गृह बाजार और निर्यात बाजारों में बेचे गए ग्रेडों में अंतर होता है, इसलिए घरेलू बिक्रियों और निर्यात बिक्रियों के बिक्रियों की भारित औसत लागत में अंतर दिखाई देता है। यह आंकड़ों में कोई असंगति नहीं दर्शाता है।
- (थ) असंगतता के आरोपों के उत्तर में ऐसी स्वीकार किया गया था कि घरेलू प्रचालनों के लिए मूल्यह्रास के आंकड़ों को गलती से जोड़ा गया था, जिन्हें आशोधित कर दिया गया है। ऐसे आशोधन के बाद नकदी लाभ दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने नकदी की समस्या का सामना किया है।
- (द) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 में मूल्यह्रास की विधि में परिवर्तन करने की व्यवस्था निहित है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में मूल्यह्रास की राशि अधिक थी। बाद में मूल्यह्रास की राशि में कमी ऐसे परिवर्तन के कारण आई है और न कि आंकड़ों में किसी असंगतता से।
- (ध) ब्याज लागत में कमी होने के बावजूद घरेलू प्रचालनों को देय ब्याज लागत में इस तथ्य के कारण वृद्धि हुई है कि घरेलू और निर्यात बिक्रियों के बीच ब्याज का आबंटन कारोबार के अनुपात में किया गया था। यदि अनुपात निरंतर स्थिर बना रहता है, तो आंकड़े वास्तव में निवेश पर प्रतिलाभ में अत्यधिक गिरावट दर्शायेंगे।
- (न) समायोजित आंकड़ों के संबंध में यह निवेदन किया गया था कि निर्यातकों द्वारा किया गया विश्लेषण सूचीबद्ध आंकड़ों पर आधारित था और इस प्रकार यह गलत था।
- (प) इस संबंध में टिप्पणियों के उत्तर में यह निवेदन किया गया था कि चूंकि निर्धारणीय मूल्य का निर्धारण पहुंच प्रभारों के लिए 1% जोड़ कर किया गया था और पहुंच कीमत में ऐसे अप्रयोगमूलक प्रभार शामिल नहीं होते हैं, निर्धारित की गई पहुंच कीमत निर्धारणीय मूल्य से कम है।
- (फ) आयात के आंकड़ों में अंतर होने के संबंध में निवेदन है कि उल्लिखित अंतर तुच्छ है जो कि याचिकादाता द्वारा कुछ लेन-देन को असामान्य के रूप में मानने के कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई कारण नहीं कि याचिकादाता आयात की मात्राओं को छिपाएगा।
- (ब) याचिकादाता द्वारा व्ययों के आबंटन के आधार सहित प्रस्तुत आंकड़ों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और उन्हें पूरा और सही पाया गया है।
- (भ) इंडोनेशिया सरकार द्वारा लगाया गए निर्यात कर का विशेष उद्देश्य याचिकादाता के इंडोनेशिया के प्रचालनों को गैर-अर्थक्षम बनाना है।
- (म) घरेलू उद्योग ने दिनांक 14 मार्च, 2018 के पत्र द्वारा निवेदन किए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:-
- (1) संबद्ध उत्पाद विनिर्मित करने की प्रक्रिया में उत्पादित कुछ अल्कोहल्स और एसिड, जैसे कि केप्रिक एसिड और केप्रेलिक एसिड को संयुक्त उत्पाद माना जाना चाहिए और न कि उप-उत्पाद।
 - (2) इस मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका का प्रपत्र - "ख" लागू नहीं होना चाहिए, अर्थात् क्षति रहित कीमत, कच्चे माल के बेहतर श्रेष्ठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
 - (3) क्षति रहित कीमत के परिकलन में प्राधिकारी को यह ध्यान में रखते हुए कि क्षति अवधि के कुछ भाग में घरेलू उद्योग ईओयू के अंतर्गत प्रचालन कर रहा था, क्षमताओं के श्रेष्ठ उपयोग पर विचार करना चाहिए।
 - (4) एलसी समर्थित ऋणदाताओं को देय व्यापार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
 - (5) बैंक प्रभारों की प्रकृति के कुछ व्ययों के संबंध में उल्लेखनीय है कि क्षति रहित कीमत के परिकलन में उनकी अनुमति दी गई है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

20. घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों का निदान निम्नानुसार किया गया है:-

- (क) प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेदन करने वाले कुछ पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके बावजूद यह सुनिश्चित करने के विचार से कि मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक निवेदनों पर विचार किया जाए, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में संबद्ध भागों में उन पर विचार किया है और उनका निदान किया है।
- (ख) जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संबद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन होने और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के प्रति संतुष्ट थे। प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए जांच की अवधि में परिवर्तन होना महत्वपूर्ण नहीं है। तथापि, जांच अवधि के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर पाटन और क्षति का निर्धारण किया गया है। पाटन-रोधी नियमावली और पाटन-रोधी करार में यह आवश्यक नहीं है कि जिस अवधि के लिए जांच शुरू की गई है, वह वही जांच अवधि होनी चाहिए, जिस पर जांच की कार्यवाई के दौरान पाटन और क्षति का निर्धारण करने पर विचार किया गया है।
- (ग) इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि जांच शुरू करने के समय जांच अवधि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में विगत में भी जांच शुरू करने के चरण में प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि में परिवर्तन किया गया है। इसलिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई क्रिया-विधि, इस संबंध में प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के समनुरूप है।
- (घ) पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। तथापि, जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ उत्पादन की लागत के संबंध में कोई उचित आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पर तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के अनुसार उपलब्ध श्रेष्ठ सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया गया है। जांच शुरू करने से पहले साक्ष्य की पर्याप्तता और परिशुद्धता के प्रति प्राधिकारी स्वयं विधिवत् संतुष्ट थे।
- (ङ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि सऊदी अरब से आयात, समान वस्तु के कुल आयातों के 3% से कम हैं, इसलिए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 14 (घ) के प्रावधानों के अनुसार इस जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों के दायरे में से सऊदी अरब को बहिष्कृत करने का विकल्प चुना है।
- (च) हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध देशों पर निर्णय जांच शुरू करने के समय लिया जाना चाहिए था, प्राधिकारी यह पाते हैं कि जबकि जांच की शुरुआत कुछ संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में की गई थी, नियम 14 में ऐसा प्रावधान है कि प्राधिकारी किसी संबद्ध देश से आयातों की मात्रा के मामले में यह पाए जाने पर कि ऐसी मात्रा जांच के अनुसरण में निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम है, तो वे ऐसे संबद्ध देश के खिलाफ जांच को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सऊदी अरब के खिलाफ जांच शुरू करना अथवा जांच को समाप्त करना में कोई गैर-कानूनी नहीं है।
- (छ) सुरक्षा शुल्क की पुनरीक्षा से संबंधित तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मुद्दा भिन्न जांच प्राधिकारी से संबंधित है। सुरक्षा शुल्क और पाटन-रोधी शुल्क विभिन्न कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत लगाए जाते हैं और ये विभिन्न स्थितियों का समाधान करने के लिए होते हैं। सुरक्षा शुल्क आयातों में उछाल आने के मामले में लगाया जाता है, जिससे गंभीर क्षति होती है, जबकि पाटन-रोधी शुल्क पाटन की अनुचित व्यापारिक पद्धति और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की रोकथाम करने के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार यह तथ्य मात्र कि सरकार ने सुरक्षा शुल्क लगाया था और सुरक्षा शुल्क की पुनरीक्षा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था, किसी भी तरीके से घरेलू उद्योग को पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के लिए आवेदन देने से बाधित नहीं करता है।
- (ज) यह तर्क यथोचित नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के फलस्वरूप निचले स्तर के उत्पादों के आयातों में वृद्धि होगी और किसी भी स्थिति में यह घरेलू उद्योग को उपचार से वंचित रखने को आधार नहीं हो सकता है।

- (झ) ग्रेड-वार शुल्क लगाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि “विचाराधीन उत्पाद” पर शुल्क लगाने की आवश्यकता है।
- (ज) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में असंगतियां और अंतर होने से संबंधित निवेदनों को नोट कर लिया है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आंकड़ों को विधिवत् सत्यापन और ध्यान पूर्वक संवीक्षा करने के बाद रिकार्ड पर ले लिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा संबंधित पक्षकारों से खरीदी गई आदानों की क्रय कीमत की भी यह पता लगाने के लिए जांच की गई है कि क्या वह निकटस्थ दूरी की कीमतों को दर्शाती है। उठाई गई आपत्तियों और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, किए गए आशोधनों को ध्यान में रखते हुए आयात के आंकड़ों की भी प्रतिपृच्छा जांच की गई है।
- (ट) जब कि निर्यात शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है, यह पाटन मार्जिन निर्धारित करने का संबद्ध प्राचल नहीं है। जहां तक क्षति निर्धारण करने का संबंध है, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को उसकी वास्तविक दशाओं में विचार करने की आवश्यकता होती है। वस्तुतः घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि निर्यात कर लगाए जाने के कारण विदेशी उत्पादकों के कच्चे माल की खपत कीमत को नहीं अपनाया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों दोनों द्वारा बना कर रखे गए रिकार्ड के आधार पर उनके आंकड़ों/सूचना पर विचार किया है।
- (ठ) क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) पर घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच शुरू किए जाने से ले कर लगभग 11 महीनों में अब तक क्षति-रहित कीमत के परिकलन की कार्य-प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का कोई अनुरोध नहीं किया है। यह जांच अब लगभग पूरी होने वाली है और मौखिक सुनवाई के बाद विशेष रूप से जब क्षति-रहित कीमत के कार्य-चालन के ब्यौरों का पहले से ही प्रकटन कर दिया गया है, ऐसे विलंबित चरण में ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- (ड) क्षति-रहित कीमत के कार्य-चालन, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त किए गए प्रमाणित और जांच की कार्रवाई के दौरान जांच दल द्वारा सत्यापित फार्मेट्स पर आधारित हैं।
- (ढ) प्राधिकारी ऐसी आवश्यकता से मुक्त नहीं हो सकते हैं, जब कि पाटन-रोधी नियमावली और अनुबंध-2 में यह अधिदेश है कि प्राधिकारी द्वारा क्षति-रहित कीमत का परिकलन करते समय याचिका में सभी फार्मेट्स सहित सूचना पर विधिवत् विचार किया जाना चाहिए।
- (ण) पाटन-रोधी नियमावली और अनुबंध-3 प्राधिकारी को क्षमताओं के श्रेष्ठ उपयोग पर और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की सामान्य लागत प्राप्त करने के लिए विचार करने के प्रयोजनार्थ क्षति अवधि से एक संपूर्ण वर्ष अथवा किसी भी अवधि की अनदेखी करने का कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त अनुबंध-3 में निर्यात के लिए और घरेलू बिक्रियों के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग के बीच कोई अंतर रखने का प्रावधान नहीं है। घरेलू उद्योग की क्षमता को उसके समग्र रूप में लिया जाना चाहिए और तदनुसार क्षमता उपयोग तय किया जाना चाहिए।
- (त) प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि घरेलू उद्योग ने वर्तमान देयता के रूप में एल.सी. समर्थित ऋणदाताओं से संबंधित राशि को स्वयं माना है, जो कि व्यापार देय का भाग है, इसलिए प्राधिकारी भिन्न मत नहीं अपना सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित वास्तविक लेखा-परीक्षित बहियों के आधार पर विश्वास किया है। क्षति-रहित कीमत के परिकलन के लिए कंपनी के लेखा-परीक्षित लाभ और हानि के लेखा के अनुसार उत्पादन की लागत के रूप में एल.सी. प्रभारों, प्रेषित कवर प्रभारों और बिल में छूट के प्रभारों पर विचार किया गया है।
- (थ) बैंक प्रभारों की प्रकृति के कुछ व्ययों के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और क्षति-रहित कार्यचालन की अनुमति दे दी है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

21. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद निर्यातक देशों को घरेलू बिक्रियों से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी है। इसलिए घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन का अनुमान लगाने के लिए विदेशी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है।
- (ख) निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण ऐसे उत्तरों के आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते कि व्यापक जांच के अनुसार वे संपूर्ण और ठीक पाए जाएं।
- (ग) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों में घोर कमियां हैं और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। उत्पादक और निर्यातक ने केवल निर्यातक की प्रश्नावली के पूरे उत्तर देने में विफल रहे हैं, बल्कि ऐसी भी प्रतीत होता है कि उन्होंने संबद्ध सूचना को छिपाया है और अयथार्थ सूचना दी है। जब कि उत्पादक/निर्यातक द्वारा निर्यातक की प्रश्नावली को पूरा और सही उत्तर नहीं दे दिया जाता है, तब तक प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- (घ) जब कि संबद्ध देशों में अधिकतर उत्पादकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने संबंधित देशों की सरकारों से कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया है, इन देशों की सरकारों ने वास्तव में पहले से ही ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर अनेक लाभ प्रदान किए हुए हैं। इसलिए निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत ऐसे अयथार्थ विवरण पर कठोरता से विचार करना चाहिए और दिए गए उत्तरों को अस्वीकार करना चाहिए।
- (ङ) निर्यातकों का यह उत्तर आश्चर्यजनक है कि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता की जांच के अधिकार क्षेत्र में आती है। जब निर्यातक प्रश्नावली में विशेष रूप से आर्थिक सहायता से संबंधित सूचना मांगी जाती है, तो उत्पादक यह निर्णय नहीं ले सकता है कि वर्तमान जांच के लिए ऐसी सूचना प्रासंगिक नहीं है।
- (च) संबद्ध वस्तुओं के प्रत्येक उत्पादक और निर्यातक के बहुविध संबंधित प्रयोज्यता हैं, जो कि उच्च स्तरीय अथवा निम्न स्तरीय वस्तुओं का विनिर्माण कर रहे हैं। प्रत्येक उत्पादक और निर्यातक के संबंधित पक्षकारों के ब्यौरे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं और उन्हें इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यदि उत्पादक/निर्यातक ने संबंधित पक्षकारों की पहचान नहीं की है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को संबद्ध ब्यौरे छिपाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- (छ) यदि किसी उत्पादक ने कोई कच्चा माल अथवा अन्य इनपुट अथवा सेवा प्राप्त की है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लेन-देन निकटस्थ दूरी की कीमतों पर किया गया था। यदि संबद्ध वस्तुओं की फीडबैक केप्टिवली उत्पादित की जाती है, तो इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या केप्टिवली उत्पादित फीडबैक के कच्चे माल की खरीद संबंधित पक्षकार से की गई है और क्या खरीद निकटस्थ दूरी की कीमतों पर की गई है।
- (ज) इसी प्रकार संबंधित निचले स्तर के प्रयोक्ताओं को बेची गई ऐसी उत्पादित वस्तुओं के मामले में ऐसे लेन-देन को सामान्य व्यापार प्रक्रिया में नहीं किया गया माना जाना चाहिए तथा उसे सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या संबद्ध वस्तुओं के संबंधित क्रेता ने बदले में ऐसी वस्तुओं का भारत में निर्यात किया है।
- (झ) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक उत्पादक और निर्यातक के बारे में विस्तृत निवेदन भी किए गए हैं, जिनमें सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए संबद्ध अन्य पहलुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
- (ञ) मेसर्स एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी ("एफपीजी") और मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर ("पीजीआईओ") द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पीजीआईओ का मेसर्स केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी ("केएलकेओएम")

- के साथ संबद्ध वस्तुओं के फ्रेक्शनलाईजेशन के लिए एक करार है। इसलिए यह आवश्यक है कि केएलकेओएम के रिकार्ड की जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं, निर्यातक की ओर से फैटी अल्कोहल्स में परिवर्तन करने के वेश में पीजीआईओ के माध्यम से भारत को निर्यात की जा रही हैं।
- (ट) केएलकेओएम द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा निवेदन किया गया था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं का निर्यात पीजीआईओ के माध्यम से नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उत्पादक की घरेलू और निर्यात बिक्रियां व्यापार के समान स्तर पर की गई हैं।
- (ठ) मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स ("टीएफए") द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के संबंध में ऐसा आग्रह किया गया था कि चूंकि संबंधित प्रयोज्यता, मेसर्ज एमेरी ओलियोकेमिकल्स (एम) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया एक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में स्वतः लगी हुई है, जिसका प्रकटन नहीं किया गया है, इसलिए उत्पादक को प्रमुख तथ्यों को छिपाने के आधार पर असहयोगी माना जाना चाहिए। साथ ही मेसर्ज एमेरी ओलियोकेमिकल्स (एम) को भी उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए था।
- (ड) इसी प्रकार मेसर्ज पीटी विल्मार नवाटी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ("डब्ल्यूआईएनए") और मेसर्ज विल्मार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, सिंगापुर ("विल्मार ट्रेडिंग") को भी इस कारणवश असहयोगी माना जाना चाहिए कि उनके संबंधित प्रयोज्यता, मेसर्ज नेच्युरल ओलियोकेमिकल्स एसडीएन. बीएचडी. ("नेट ओलियो"), जो कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में लगी हुई है, द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मेसर्ज अडानी विल्मार लिमिटेड जो कि मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए और मेसर्ज विल्मार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की संबंधित प्रयोज्यता है, ने निर्यातक की ओर से बिक्री के क्रियाकलापों को शुरू किया हुआ है। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी की विगत पद्धति को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए भारत में प्रयोज्यता की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ को निर्यात कीमत में से घटाए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, मेसर्ज अडानी विल्मार ने जांच में भाग नहीं लिया है और उसने अपनी बिक्री तथा किए गए सामान्य और प्रशासनिक व्ययों का कोई ब्यौरा भी प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ढ) मेसर्ज म्युजिम मेस होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड ("पीटीएमएम") और मेसर्ज इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट प्राईवेट लिमिटेड ("आईसीओएफ") द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि भारत में दो प्रयोज्यता, नामतः मेसर्ज साउथ इंडिया कृष्णा ऑयल एंड फैट्स और मेसर्ज टवरूर ऑयल्स एंड फैट्स, जो निर्यातक की ओर से विपणन क्रियाकलाप करती हैं। यदि इन प्रयोज्यताओं ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विपणन क्रियाकलाप किए हैं, तो उनके द्वारा किए गए व्ययों और अर्जित लाभ को निर्यात कीमत में से घटा दिया जाना चाहिए।
- (ण) संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल अर्थात् अपरिष्कृत पॉम कर्नल ऑयल, पॉम ऑयल और उसके व्युत्पन्न को जब उन्हें इंडोनेशिया और मलेशिया से निर्यात किया जाता है, तो उन पर निर्यात शुल्क लगता है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू बाजार में कच्चे माल की अत्यधिक आपूर्ति हुई थी और उनकी कीमतों को छिपाया गया था। चूंकि कच्चे माल की कीमत विकृत थी, इसलिए संबद्ध देशों में विशिष्ट बाजार स्थिति थी और लागत उत्पादन के साथ सहयोजित थी और वस्तुओं की बिक्री को पर्याप्त रूप से अधिकार में नहीं लिया गया था। इसलिए रिकार्ड के अनुसार कच्चे माल की लागत पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की उचित लागत निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन किया जाना चाहिए।
- (त) कारखाना-गत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए संबंधित पक्षकार की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ को घटाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार यदि वितरण माध्यम का भाग बनने वाले सभी व्यापारियों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, तो उनके लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

- (थ) इसके अतिरिक्त कुछ निर्यातकों के संबंधित प्रयोज्यता हैं, जो उनकी ओर से विपणन के क्रियाकलाप करते हैं अथवा भंडारण, लदान और संभार-तंत्र के क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। विपणन क्रियाकलाप करने वाले ऐसे किसी भी प्रयोज्यता के व्ययों और लाभ को घटाया जाना चाहिए तथा प्राप्त हुई किसी भी संभार-तंत्र अथवा भंडारण सेवाओं के लिए समायोजन निकटस्थ दूरी के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (द) हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के उत्तर में कि याचिका में सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत पर आधारित नहीं हो सकता है, यह निवेदन किया गया था घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया था।
- (ध) सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर इस शर्त पर किया जा सकता है कि उत्तर सभी पहलुओं पर संपूर्ण हैं और उनकी जांच करने पर उन्हें सही और विश्वसनीय पाया गया है। इसके अतिरिक्त सत्यापन रिपोर्टें, निर्यातकों और उनके पक्षकारों के साथ पत्राचार और उनके उत्तर और वास्तविक पाटन मार्जिन का प्रकटन किया जाए।
- (न) इस संबंध में तर्कों के उत्तर में यह निवेदन किया गया था कि याचिकादाता द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत में किए गए समायोजन श्रेष्ठ अनुमानों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातकों ने ऐसा दावा नहीं किया है कि ऐसे समायोजन अतिरिक्त हैं।
- (प) किसी भी निर्यातक ने ऐसा दावा नहीं किया है कि उसने भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं किया है।
- (फ) इस संबंध में अनुरोध के उत्तर में यह निवेदन किया गया था कि पाटन मार्जिन का निर्धारण केवल तभी मासिक आधार पर किया जा सकता है, यदि निर्यातक उत्पादन, बिक्रियों, कच्चे माल की सूचियों, तैयार माल की सूचियों, प्रत्येक ग्रेड के उत्पादन की लागत और कंपनी के वित्तीय विवरण और मासिक आधार पर उनके वर्गीकरण से संबंधित संबद्ध रिकार्ड प्रस्तुत करने के इच्छुक हों। जब तक ऐसी सूचना प्रदान नहीं कर दी जाती है, तब तक पाटन मार्जिन का परिकलन मासिक आधार पर नहीं किया जा सकता है।

च. 2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

22. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) याचिकादाता ने सामान्य मूल्य का परिकलन उसकी अपनी निजी लागत के आधार पर किया है और प्रत्येक देश के लिए परिकलित किया गया सामान्य मूल्य समान है। इसके फलस्वरूप पाटन मार्जिन के प्राक्कलन टेढे हैं और ऐसा कोई संकेत नहीं देते हैं कि क्या भारत में वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।
- (ख) पाटन मार्जिन का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता रहा है। यदि ऐसा विश्लेषण नहीं किया जाता है, तो यह ऐसे निर्यातकों के प्रतिकूल होगा जिन्होंने जाच अवधि के प्रारंभ में अत्यधिक निर्यात किए हैं।
- (ग) इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रमुख कच्चा माल प्रचुर रूप से उपलब्ध है, जिसके कारण इन देशों में निर्यातकों के उत्पादन की लागत निम्नतर है। इन निर्यातकों को प्राप्त हो रहे तुलनात्मक लागत लाभ को पाटन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
- (घ) याचिकादाता ने निर्यात कीमत के लिए समायोजन करने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ङ) याचिकादाता के आरोपों के उत्तर में यह निवेदन किया गया था कि संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता का प्रकटन, आर्थिक सहायता की जांच के अधिकार-क्षेत्र के भीतर आता है।
- (च) फिर भी प्रश्नावली के उत्तर में उत्पादक द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त हुई आर्थिक सहायता की सूचना देने की आवश्यकता है।

- (छ) याचिकादाता का यह आरोप निराधार है कि टीएफए ने सभी संबंधित प्रयोज्यताओं का प्रकटन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यदि याचिकादाता चाहता है कि उसके सभी संबंधित प्रयोज्यता सूचना प्रस्तुत करें और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में सहभागिता करने के संबंध में स्पष्टीकरण दें, तो उसे अपने निजी हितबद्ध पक्षकारों के संबंध में भी समान स्पष्टीकरण देना चाहिए।
- (ज) इस तर्क के संबंध में कि निर्यात कर लगाने से कच्चे माल की कीमत प्रभावित हुई थी, यह निवेदन किया गया था कि ऐसा कर विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों का पूर्णतया अनुपालन करना था और घरेलू उत्पादकों को कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना मात्र था। आयात शुल्कों के विद्यमान होने से एक विशिष्ट बाजार स्थिति की अर्हता प्राप्त नहीं हो जाती है।
- (झ) इंडोनेशिया की सरकार ने ऐसा कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया है, जिससे निर्यातक देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक लाभान्वित हों।
- (ञ) यूरोपीय यूनियन-बायो डीजल के मामले में अपील निकाय ने यह निर्णय दिया है कि कच्चे माल की अधिप्राप्ति की वास्तविक लागत को इस कारणवश अस्वीकार करना पाटन-रोधी करार के प्रावधानों के अनुरूप था कि कच्चे माल पर निर्यात कर लगता था।
- (ट) इसके अतिरिक्त याचिकादाता ने अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि निर्यात कर नहीं होने की स्थिति में पॉम कर्नल ऑयल की कीमत अत्यधिक होती।
- (ठ) फिर भी यदि उत्पादक थाईलैंड में अवस्थित होते, तो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का कोई अनुप्रयोग नहीं होता।
- (ड) प्राधिकारी को सामान्य मूल्य निर्धारित करने में अनुबंध-2 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है, बशर्ते कि कच्चे माल का लेन-देन निकटस्थ दूरी पर किया गया हो।
- (ढ) याचिकादाता का संयुक्त राज्य अमरीका में जांच प्राधिकारियों के जांच परिणामों पर विश्वास करना अनुचित है, क्योंकि मामलों का कानूनी ढांचा और वास्तविक पृष्ठ भूमि भिन्न है। इसके अतिरिक्त अन्य जांच प्राधिकारियों की पद्धतियां कानूनी न्यायशास्त्र नहीं बनती हैं।
- (ण) संबद्ध वस्तुओं का कारोबार करने वाले प्रत्येक संबंधित प्रयोज्यता के लिए कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि वह निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करे, भले ही भारत के साथ उसके व्यापार होते हों। मूल्य श्रृंखला केवल तभी अपूर्ण है, यदि वस्तुओं का उत्पादन अथवा भारत को निर्यात करने में प्रयोज्यताओं ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी जिन प्रयोज्यताओं ने भारत को निर्यात किए हैं, वे प्रभावी उत्तर देने में इसलिए सक्षम नहीं होंगे क्योंकि वे सामान्य मूल्य अथवा निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए कोई संबद्ध सूचना प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। घरेलू उद्योग को यह अभिज्ञात करना होगा कि सूचना में “आवश्यक सूचना” कैसे गुप्त है। फिर भी यदि प्राधिकारी उत्तर को अधूरा पाते हैं, तो वे सूचना में कमी होने के बारे में पत्र जारी कर सकते हैं।
- (त) इस निवेदन के संबंध में कि मेसर्स नेट ओलियो, मेसर्स डब्ल्यूआईएन को स्वीकृत विशिष्ट शुल्क का उपयोग कर सकता है, यह निवेदन किया गया था कि यदि मलेशिया में उत्पादित किसी वस्तु का निर्यात इंडोनेशिया के माध्यम से किया जाता है, तो उसमें सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के पास उपलब्ध व्यापार के दस्तावेज प्रतिबिंबित होंगे। इस प्रकार शुल्कों की कोई प्रवंचना नहीं हो सकती है।
- (थ) जांच में मेसर्स अडानी विल्मार की सहभागिता के संबंध में निवेदनों के उत्तर में मेसर्स डब्ल्यूआईएनए और मेसर्स विल्मार ट्रेडिंग ने यह तर्क दिया है कि प्रस्तुत किए गए उत्तर में ऐसा उल्लेख है कि मेसर्स विल्मार ट्रेडिंग, मेसर्स अडानी विल्मार को आर्डर प्राप्त करने के लिए कमीशन अदा करता है। इस कमीशन को पहले से ही निर्यात कीमत में से घटा दिया गया है।

- (द) इस आरोप के उत्तर में कि सभी संबंधित प्रयोज्यताओं का प्रकटन नहीं किया जा सकता है, मेसर्स डब्ल्यूआईएनए और मेसर्स विल्मार ट्रेडिंग ने यह तर्क दिया है कि ऐसी सूचना के लिए प्रश्नावली का कोई प्रपत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रयोज्यताओं के नाम पाटन-रोधी जांच में अप्रासंगिक होंगे।
- (ध) जब कि प्रतिवादियों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों की कटौती करने पर कोई आपत्ति नहीं है, निर्यातक के लाभ की कटौती को ऐसे मामलों में नहीं की जा सकती है, जिनमें उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी कारणवश संबंधित उत्पादक और निर्यातक को एक प्रयोज्यता के रूप में माना जाता है।
- (न) मेसर्स पीटीईओ ने मेसर्स ईओएस के द्वारा वितरण का एक सीधा माध्यम बना कर रखा हुआ है और वह भारत में स्वतंत्र उपभोक्ताओं के साथ सीधे संपर्क में रहता है। इसके अतिरिक्त उसने सभी संबंधित पक्षकारों के व्यौर प्रस्तुत किए हैं। मेसर्स पीटीईओ केवल इंडोनेशिया में अवस्थित है और वह बहुराष्ट्रीय नहीं है। इस प्रकार घरेलू उद्योग के आरोप निराधार हैं।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां कर उनको सलाह दी थी कि वे निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से सूचना प्रदान करें। निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

- (क) मेसर्स पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स और मेसर्स इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक)।
- (ख) मेसर्स पीटी म्यूजिम मेस होलिंग प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक)।
- (ग) मेसर्स पीटी विल्मार नवाटी इंडोनेशिया (उत्पादक) और मेसर्स इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक)।
- (घ) मेसर्स एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी और मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर (निर्यातक)।
- (ङ) मेसर्स केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी, मलेशिया।
- (च) मेसर्स थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड।

24. चूंकि उपरोक्त उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, प्राधिकारी का इन कंपनियों के संबंध में विशिष्ट पाटन मार्जिन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इन निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली पहले इसकी जांच करना है कि क्या प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा अपने गृह बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की अनुमति देने के लिए प्रतिनिधिक और अर्थक्षम थी और क्या प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार सामान्य व्यापारिक परिक्षण संतोषजनक था। अन्य मामलों में सामान्य मूल्य प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्यातकों द्वारा दावा किए गए बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय सहित उत्पादन की लागतों को उचित सत्यापन और लाभ के लिए 5% जोड़ने के बाद स्वीकार कर लिया गया है।

25. संबद्ध वस्तुओं के लिए मेसर्स प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए (पीजीआईओ) और मेसर्स केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी, मलेशिया ("केएलकेओएम") के बीच प्रभाजनीकरण करार के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि "केएलकेओएम" पीजीआईओ द्वारा उसे ठोस रूप में प्रदत्त फैटी अल्कोहल्स को द्रव रूप में परिवर्तित करता है। प्राधिकारी ने सभी कंपनियों के उत्तरों की ध्यान पूर्वक जांच की है और वे नोट करते हैं कि इन वस्तुओं का उत्पादक एफपीजी है और द्रव से ठोस रूप में परिवर्तन करने के क्रियाकलाप का बहुत नगण्य मूल्य होता है।

26. मेसर्ज नेशनल ओलियोकेमिकल्स एसडीएन वीएचडी द्वारा उत्तर नहीं प्रस्तुत करने और मेसर्ज अडानी विलमेर लिमिटेड की बिक्री व्यय के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्ज नाटोलियो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है और वह मलेशिया में संबद्ध वस्तुओं की केवल ब्लेंडिंग, फ्लेकिंग और पैकिंग करता है। इसके अतिरिक्त मेसर्ज नाटोलियो ने जांच अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। इसलिए मेसर्ज नाटोलियो को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त मेसर्ज अडानी विलमेर लिमिटेड डब्ल्यूटीआरडी के लिए एक कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करता है। मेसर्ज अडानी विलमेर लिमिटेड भारत में पुनः बिक्री के लिए स्वयं संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं कर रहा है। मेसर्ज अडानी विलमेर लिमिटेड को अदा किए गए कमीशन को निर्यात कीमत में से पहले ही घटा दिया गया है। इसलिए डब्ल्यूआईएनए/डब्ल्यूटीआरडी के लिए कारखाना-गत निर्यात कीमत के परिकलन के लिए मेसर्ज अडानी विलमेर के एसजीए व्यय का समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

27. संबद्ध देशों से अहसयोगी निर्यातकों के मामले में प्राधिकारी का पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

28. प्राधिकारी का संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निम्नानुसार निर्धारण करने का प्रस्ताव है:-

च. 4.1 इंडोनेशिया के मामले में पाटन मार्जिन

1. मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (उत्पादक)

मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (उत्पादक) का सामान्य मूल्य

29. मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स ("इकोग्रीन") द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि "इकोग्रीन" ने जांच अवधि के दौरान ***मी.टन घरेलू बिक्रियां की हैं। इन बिक्रियों में से 97% बिक्रियां गैर-संबंधित पक्षकारों को की गई हैं। भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्रियां की गई हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया से व्यापारिक परीक्षण किया है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू कारोबार का निर्धारण किया जा सके। इस मामले में ग्रेड-वार लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्रियां 80% से कम हैं और तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जित करने वाले घरेलू कारोबार पर विचार किया गया है।

30. मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स ("इकोग्रीन") ने पैकिंग लागतों, अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा, पर्यवेक्षक शुल्क, हैंडलिंग प्रभारों, अन्य प्रभारों और श्रोपट प्रभारों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार "इकोग्रीन" के लिए कारखाना-गत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जो कि ***अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (उत्पादक) और मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

31. मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स ("इकोग्रीन") ने अपनी संबंधित व्यापारी कंपनी मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड ("इकोग्रीन"), सिंगापुर के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जांच अवधि के दौरान "इकोग्रीन" ने केवल इकोग्रीन सिंगापुर के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन निर्यात किए हैं। मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स ("इकोग्रीन") ने इकोग्रीन सिंगापुर को कारखाना-गत शर्तों पर संबद्ध वस्तुओं को बेचा है। इकोग्रीन सिंगापुर ने कमीशन, ब्रूट, अंतरदेशीय भाड़े, बीमा, समुद्री भाड़े, और अन्य प्रभारों का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। प्राधिकारी ने इन निर्यात कारोबार के लिए इकोग्रीन सिंगापुर की लाभप्रदता की भी जांच की है।

32. तदनुसार मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स ("इकोग्रीन") के लिए इकोग्रीन सिंगापुर के माध्यम से निर्यात के लिए भारित औसत कीमत निर्धारित की गई है, जो कि ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

II. मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड (उत्पादक)

मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड (उत्पादक) का सामान्य मूल्य

33. मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड ("एमएमएच") द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमएमएच ने जांच अवधि के दौरान *** मी.टन घरेलू बिक्रिया की हैं। ये सभी बिक्रिया असंबंधित पक्षकारों को की गई हैं। भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्रिया की गई हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया से व्यापारिक परीक्षण किया है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू कारोबार का निर्धारण किया जा सके। इस मामले में केवल एक घरेलू कारोबार किया गया था जो कि घाटे पर बेचा गया था। इसलिए कंपनी के लिए 5% लाभ को जोड़ कर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया गया है।

34. तदनुसार मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड ("एमएमएच") के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड (उत्पादक) और मेसर्ज इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

35. मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड (एमएमएच) ने मेसर्ज इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर ("आईसीओएफ") नामक अपनी संबंधित कंपनी के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जांच अवधि के दौरान एमएमएच ने आईसीओएफ के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन निर्यात किए हैं। आईसीओएफ ने समुद्री परिवहन, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों, स्विच बीएल शुल्कों, प्रशासनिक लागत, बिक्रियों और विपणन सहायता सेवाओं का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। प्राधिकारी ने इन निर्यात कारोबार के लिए इकोग्रीन सिंगापुर की लाभप्रदता की भी जांच की है।

36. तदनुसार आईसीओएफ के माध्यम से किए गए निर्यातों के लिए मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड के लिए भारित औसत कीमत निर्धारित की गई है, जो कि ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

III. मेसर्ज पीटी विल्मार नबाटी, इंडोनेशिया (उत्पादक)

मेसर्ज पीटी विल्मार नबाटी, इंडोनेशिया (उत्पादक) का सामान्य मूल्य

37. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि जांच अवधि के दौरान मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए ने घरेलू बाजार में *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में सभी बिक्रिया असंबंधित पक्षकारों को की गई हैं। भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्रिया की गई हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया से व्यापारिक परीक्षण किया है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू कारोबार का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80% से कम हैं। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में केवल लाभ अर्जित करने वाले कारोबार पर विचार किया है।

38. मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए ने अंतरदेशीय भाड़े और घरेलू बिक्री कीमत से क्रेडिट व्ययों के लिए समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार डब्ल्यूआईएनए के लिए भारित औसत कीमत निर्धारित की गई है, जो कि ***अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

मेसर्ज पीटी विल्मार नबाटी, इंडोनेशिया (उत्पादक) और मेसर्ज विलमेर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

39. मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए ने मेसर्ज विलमेर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड (डब्ल्यूटीआरडी), सिंगापुर नामक अपनी संबंधित कंपनी के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जांच अवधि के दौरान मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए ने केवल मेसर्ज डब्ल्यूटीआरडी के

माध्यम से भारत को *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए ने मेसर्ज डब्ल्यूटीआरडी को एफओबी की शर्तों पर संबद्ध वस्तुएं बेची हैं। मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए ने अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन हैंडलिंग व्ययों और फ्लेक्सी-बैग व्ययों का समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। प्राधिकारी ने मेसर्ज डब्ल्यूटीआरडी द्वारा प्रस्तुत उत्तर की भी जांच की है और यह सुनिश्चित किया है कि मेसर्ज डब्ल्यूटीआरडी के माध्यम से किए गए आयात लाभप्रद थे और सभी उपयुक्त समायोजनों पर विचार किया गया है।

40. तदनुसार मेसर्ज डब्ल्यूटीआरडी के माध्यम से मेसर्ज डब्ल्यूआईएनए को किए गए निर्यात के लिए भारित औसत कीमत निर्धारित की गई है, जो कि ***अमरीकी डालर/ मी.टन है।

IV. इंडोनेशिया से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक

41. इंडोनेशिया से सभी अन्य ऐसे निर्यातकों के मामले में जिन्हें असहयोगी माना गया है, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत क्रमशः ***अमरीकी डालर/मी.टन और ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

च. 4.2 मलेशिया के मामले में पाटन मार्जिन

I. मेसर्ज एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएच बीएचडी (उत्पादक)

मेसर्ज एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएच बीएचडी (उत्पादक) का सामान्य मूल्य

42. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि जांच अवधि के दौरान मेसर्ज एफपीजी ने मेसर्ज प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए (सिंगापुर शाखा) ("पीजीआईओ") नामक अपनी कंपनी के माध्यम से घरेलू बाजार में *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्रियां की गई हैं। पीपीजी और पीजीआईओ के एसजीए के लिए यथा-निर्धारित संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया से व्यापारिक परीक्षण किया है ताकि पीजीआईओ द्वारा असंबंधित ग्राहकों को लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्रियों के कारोबार का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80% से कम हैं। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में केवल लाभ अर्जित करने वाले कारोबार पर विचार किया है। सभी बिक्रियों के कुछ ग्रेड घाटा उठाने वाले थे, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसे ग्रेडों के लिए उत्पादन की लागत, पीजीआईओ के एसजीए और 5% लाभ को शामिल करते हुए सामान्य मूल्य संरचित किया है।

43. कंपनी ने घरेलू बिक्री कीमत से अंतरदेशीय भाड़े और क्रेडिट व्ययों के लिए समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार मेसर्ज एफपीजी के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि ***अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

मेसर्ज एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएच बीएचडी (उत्पादक) और मेसर्ज प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

44. मेसर्ज एफपीजी ने मेसर्ज पीजीआईओ, सिंगापुर नामक अपनी संबंधित व्यापारी कंपनी के साथ प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जांच अवधि के दौरान मेसर्ज एफपीजी ने केवल मेसर्ज पीजीआईओ नामक अपनी कंपनी के माध्यम से भारत को *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। मेसर्ज एफपीजी ने एफसीए शर्तों पर *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। घरेलू बाजार में *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री एफसीए शर्तों पर की है। मेसर्ज पीजीआईओ ने समुद्री भाड़े, पत्तन हैंडलिंग व्ययों और क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों और मेसर्ज पीजीआईओ के एसजीए व्ययों के लिए समायोजन करने का दावा किया है। विधिवत् सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दे दी गई है। तदनुसार मेसर्ज एफपीजी के लिए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो कि ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

II. मेसर्ज केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी (उत्पादक और निर्यातक)

मेसर्ज केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी का सामान्य मूल्य

45. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि जांच अवधि के दौरान मेसर्ज केएलकेओएम ने घरेलू बाजार में *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में समस्त बिक्रियां असंबद्ध पक्षकारों को की गई हैं। भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्रियां की गई हैं। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया से व्यापारिक परीक्षण किया है ताकि लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्रियों के कारोबार का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80% से कम हैं। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में केवल लाभ अर्जित करने वाले कारोबार पर विचार किया है।

46. मेसर्ज केएलकेओएम ने घरेलू बिक्री कीमत से अंतरदेशीय भाड़े और क्रेडिट व्ययों के लिए समायोजन करने का दावा किया है। तदनुसार मेसर्ज केएलकेओएम के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

मेसर्ज केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी की निर्यात कीमत

47. जांच अवधि के दौरान मेसर्ज केएलकेओएम ने भारत में सीधे असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं के *** मी.टन निर्यात किए हैं। मेसर्ज केएलकेओएम ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, पत्तन हैंडलिंग व्ययों, एजेंट की कमीशन, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों का समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार मेसर्ज केएलकेओएम के लिए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो कि ***अमरीकी डालर प्रति मी.टन है।

III. मलेशिया से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक

48. मलेशिया से सभी अन्य ऐसे निर्यातकों के मामले में जिन्हें असहयोगी माना गया है, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत क्रमशः ***अमरीकी डालर/मी.टन और ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

च. 4.3 थाईलैंड के मामले में पाटन मार्जिन

I. मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक)

मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड का सामान्य मूल्य

49. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया था कि मेसर्ज टीएफए ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में समस्त बिक्रियां असंबंधित पक्षकारों को की गई हैं। भारत को किए गए निर्यात की तुलना में घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में बिक्रियां की गई हैं। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया से व्यापारिक परीक्षण किया है ताकि लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्रियों के कारोबार का निर्धारण किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि लाभ अर्जित करने वाले कारोबार 80% से कम हैं। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बाजार में केवल लाभ अर्जित करने वाले कारोबार पर विचार किया है।

50. मेसर्ज टीएफए ने घरेलू बिक्री कीमत से अंतरदेशीय भाड़े, बीमा, भंडारण, बैंक प्रभारों और क्रेडिट व्ययों का समायोजन करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जो कि ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड की निर्यात कीमत

51. मेसर्ज टीएफए ने जांच अवधि के दौरान भारत में सीधे असंबंधित ग्राहकों को *** मी.टन संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए हैं। मेसर्ज टीएफए ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, भंडारण, एजेंट के कमीशन, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभारों का समायोजन

करने का दावा किया है। प्राधिकारी ने विधिवत् सत्यापन के बाद उनकी अनुमति दे दी है। तदनुसार भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है, जो कि ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

II. थाईलैंड से सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक

52. थाईलैंड से सभी अन्य ऐसे निर्यातकों के मामले में जिन्हें असहयोगी माना गया है, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत क्रमशः ***अमरीकी डालर/मी.टन और ***अमरीकी डालर/मी.टन है।

च. 4.5 पाटन मार्जिन का निर्धारण

53. उपरोक्त अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर परिकलित किया गया पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

पाटन मार्जिन तालिका

क्रमांक	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	निबल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन %	सीमा
1.	इंडोनेशिया	मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स	मेसर्ज इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स (सिंगापुर) प्राईवेट लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2.	इंडोनेशिया	मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड	मेसर्ज इंटर-कॉन्टिनेंटल ऑयल एंड फैट प्राईवेट लिमिटेड, सिंगापुर	***	***	***	***	0-10
3.	इंडोनेशिया	मेसर्ज पीटी विल्मार नवाटी	मेसर्ज विल्मार ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, सिंगापुर	***	***	***	***	10-20
4.	इंडोनेशिया	असहयोगी	असहयोगी	***	***	***	***	10-20
5.	मलेशिया	मेसर्ज एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी	मेसर्ज प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर	***	***	***	***	0-10
6.	मलेशिया	मेसर्ज केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी	मेसर्ज केएल-किपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी, मलेशिया	***	***	***	***	10-20
7.	मलेशिया	असहयोगी	असहयोगी	***	***	***	***	15-25
8.	थाईलैंड	मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
9.	थाईलैंड	असहयोगी	असहयोगी	***	***	***	***	5-15

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए आवेदन भारत में समान वस्तु के एक घरेलू उत्पादक मै. वीवीएफ (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के पास भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार याचिकाकर्ता को इस जाँच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना गया है। अतः इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता जो नियम 2(ख) में यथा-परिभाषित घरेलू उद्योग है, की लागत और क्षति संबंधी सूचना की जाँच की गई है।

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

55. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु के भारी पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) के मद्देनजर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभाव का संचयी विश्लेषण किया जा सकता है क्योंकि उसमें निर्धारित शर्तें वर्तमान जांच में पूरी हो रही हैं।
- ख. रक्षोपाय शुल्क लगाये जानेके कारण ही अगस्त 2014 के बाद से आयातों में कमी आई है। तथापि यदि रक्षोपाय शुल्क के बाद के आकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो इससे पता चलेगा कि आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत दोनों की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- ग. कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में कमी 2013-14 में 99.45 प्रतिशत से जाँच अवधि में 98.20 प्रतिशत है जो मामूली है और ऐसी स्थिति में क्षति विश्लेषण के लिए उसकी प्रासंगिकता कम है जहां :
 - i. गंभीर क्षति और वास्तविक क्षति की अवधि के बीच तुलना की जा रही थी।
 - ii. आयात मांग के 44 प्रतिशत पर कब्जा किए हुए हैं।
 - iii. घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमताएं थीं।
- घ. किसी भी तरह 2014-15 में आकड़ों के संदर्भ में तुलना विकृत है क्योंकि आयातों में अचानक वृद्धि से वह अवधि प्रभावित थी। यदि ऐतिहासिक आकड़ों का विश्लेषण किया जाए, इससे पता चलेगा कि आयात 2010-11 में काफी कम स्तर पर रहे थे।
- ङ. जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण प्रासंगिक है क्योंकि क्षति की अवधि के आंकड़े आयात में उछाल से, और परिणामस्वरूप रक्षोपायों की वजह से विकृत हो गये थे।
- च. घरेलू उद्योग कीमत कम करने के लिए लगातार दबाव में रहा है। पूरी क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग को उत्पादन की लागत से काफी कम कीमत पर बिक्री के लिए मजबूर किया गया है। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।
- छ. हालांकि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में कमी की है, कीमतों में गिरावट सकारात्मक रही है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री भी काफी अधिक है।
- ज. 11 जुलाई 2016 तक घरेलू उद्योग ईओयू योजना के तहत काम कर रहा था, जिसके कारण इसके उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, जांच की अवधि में घरेलू बिक्री के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षमता में वृद्धि हुई है।
- झ. यद्यपि घरेलू उद्योग के पास बाजार में पूरी मांग को कवर करने की क्षमता है, तथापि उसकी क्षमता अल्प प्रयुक्त है। घरेलू उद्योग केवल बाजार हिस्सेदारी का 35-45% हिस्सा हासिल करने में सफल रहा है। रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के बाद, घरेलू उद्योग का हिस्सा 15-25% तक कम हो गया है।

- ज. हालांकि जांच अवधि में बिक्री में थोड़ी वृद्धि हुई फिर भी इस अवधि के बाद, घरेलू उद्योग की बिक्री में भारी गिरावट आई है।
- ट. यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री में वृद्धि करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयासों को आयातों द्वारा कुछ हद तक अवरुद्ध किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची बढ़ गई।
- ठ. लागत कम करने के बावजूद, घरेलू उद्योग लागत वापस पाने में सक्षम नहीं रहा और क्षति वास्तव में क्षति की अवधि के दौरान और बढ़ गई।
- ड. नियोजित पूंजी पर आय क्षति अवधि में नकारात्मक रही है, और जांच की अवधि में स्थिति और बिगड़ गई है। इसके अलावा, नकद घाटा क्षति अवधि में और बढ़ गया है।
- ण. व्याज पूर्व लाभ के नकारात्मक होने के कारण, घरेलू उद्योग अपने मौजूदा ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त कमा नहीं पा रहा है। जाहिर है, घरेलू निवेश की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता कम हुई है।
- त. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में रक्षोपायों को लागू होने और ईओयू से हटने के बाद वृद्धि हुई है, तथापि लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय के अन्य मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि नकारात्मक है और क्षति की अवधि के दौरान और कम हो गई है।
- थ. संबद्ध देशों के उद्योगों का इरादा स्पष्ट रूप से भारतीय उद्योग को धीरे-धीरे बाहर करने का रहा है और अंततः इसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया है।
- द. आयातों से न केवल घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, बल्कि गंभीर क्षति होने का खतरा भी बना हुआ है।
- i. जांच के बाद की अवधि में आयात में 50% (वार्षिक आधार पर) की वृद्धि हुई है।
 - ii. वैश्विक बाजार में प्राकृतिक फैटी अल्कोहल की आपूर्ति अधिक है, जिसके कारण संबद्ध देशों में उत्पादकों की क्षमता का अल्प-उपयोग होता है। इसके विपरीत, भारतीय बाजार में अभी भी बहुत अधिक विकास की क्षमता है।
 - iii. आयात ऐसी कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा।
 - iv. संबद्ध वस्तु की अधिक आपूर्ति के परिणामस्वरूप, संबद्ध देशों के उत्पादक अपने उत्पादों को प्रभावी रूप से बाजार में नहीं दे पा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची बढ़ सकती है।
 - v. भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है, क्योंकि भारत में प्रचलित मूल्य दूसरे देशों में प्रचलित दर से अधिक है।
- ध. घरेलू उद्योग को क्षति इस तथ्य के प्रकाश में देखी जानी चाहिए कि क्षति की अवधि की शुरुआत के दौरान घरेलू उद्योग को आयात में अचानक वृद्धि के कारण गंभीर क्षति हो रही थी। यूरोपीय संघ में जांचकर्ता अधिकारियों के एक निष्कर्ष पर भरोसा करते हुए, यह कहा गया कि उद्योग अभी भी क्षति से उबर रहा है, और पाटन की अनुपस्थिति में, और अधिक सार्थक सुधार करने में सक्षम होगा।
- न. किसी भी मामले में, यद्यपि आयात बाजार का 44% हिस्सा है, अन्य घरेलू उत्पादकों का हिस्सा केवल 16% है। स्पष्ट है कि बाजार में आयात प्रमुख चालन शक्ति रहे हैं।
- प. शुल्क लागू होने के परिणामस्वरूप क्षति के कुछ मापदंडों में मामूली सुधार स्वाभाविक था।
- फ. घरेलू उद्योग को क्षति पाटन के अलावा किसी भी अन्य कारण से नहीं हुई थी:
- i. क्षति की अवधि के दौरान, मांग में केवल 4% की कमी आई है, इस प्रकार मांग में कोई संकुचन नहीं है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि की संभावना है क्योंकि डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए बाजार बढ़ रहा है।

- ii. अन्य देशों से आयात की मात्रा नगण्य है।
 - iii. प्रतिस्पर्धा, व्यापार प्रतिबंधात्मक कीमतों, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास या उपभोग प्रवृत्ति में बदलाव की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती हो।
 - iv. अन्य उत्पादों के लिए आकड़ों, और निर्यात बिक्री के आकड़ों को अलग किया गया है। इस प्रकार, विश्लेषण केवल संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री पर आधारित है।
- ब. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की प्रति यूनिट (समायोजित) हानि में वृद्धि हुई है। यह पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को दर्शाता है।
- भ. कानून के अनुसार पाटन को क्षति का एकमात्र कारण होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक है कि पाटन और क्षति के बीच "एक कारणात्मक संबंध" होना चाहिए, न कि कारणात्मक संबंध।
- म. इन तर्कों का जवाब देते हुए कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग में क्षति हुई थी, यह अनुरोध किया गया था कि जब घरेलू उद्योग खुद अपनी बिक्री में वृद्धि करने में सफल रहा है, और इसके बजाय उसे कीमत के संबंध में क्षति हुई है, इसलिए अन्य घरेलू उत्पादकों कि बाजार में हिस्सेदारी की बात करना सार्थक नहीं है।
- य. जैसा कि निष्पन्न ज़ीयन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा माना गया था, घरेलू उद्योग की क्षति पर आदर्श परिस्थितियों के संदर्भ में विचार नहीं किया जाना चाहिए बल्कि घरेलू उद्योग के विशिष्ट परिस्थितियों में माना जाना चाहिए।
- र. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने भारी मात्रा में कच्चे माल को स्थानीय रूप से प्राप्त किया है, और इस प्रकार प्रतिवर्ती शुल्क संरचना और कच्चे माल की उच्च लागत के संबंध में तर्क अप्रासंगिक हैं।
- ल. यद्यपि कृत्रिम फैटी अल्कोहलों ने वैश्विक बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा कब्जा कर लिया है, भारत में इसकी मांग कम है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयात का 97% संबद्ध देशों से आ रहा है, जहां केवल प्राकृतिक फैटी अल्कोहल का उत्पादन होता है।
- व. वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरणों को अन्य हितवद्ध पक्षों द्वारा संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। वास्तव में, ये बयान घरेलू उद्योग की क्षति के इस दावे का समर्थन करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति अधिक है और मांग विश्व स्तर पर सिंथेटिक फैटी अल्कोहल में स्थानांतरित हो गई है। हालांकि, वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण में यह निष्कर्ष नहीं बदल गया है कि वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- श. घरेलू उद्योग ने ईयूओ स्कीम से बाहर होने का कारण घरेलू बाजार पर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना था। इस प्रकार, निर्यात बिक्री में गिरावट केवल इस कारण से हुई है। यद्यपि, पाटन के कारण, घरेलू उद्योग केवल बाजार का एक छोटा सा हिस्सा हासिल करने में सक्षम हुआ जिसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग कम हुआ।
- ष. इसके अलावा, यह बेतुकी बात है कि भारत में प्रतियोगिता की दशाओं को विकृत करने के बाद, संबद्ध देशों के उत्पादकों को ईओयू से बाहर निकलने और घरेलू बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याचिकाकर्ता को दोष देना चाहिए।
- स. उस अवधि के लिए जब घरेलू उद्योग एक ईओयू के रूप में काम कर रहा था, निर्यात के लिए उत्पादन को छोड़ने के बाद इसकी क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए।
- ह. इस तर्क के लिए कोई आधार नहीं है कि क्षति के विश्लेषण के लिए कीमत कटौती प्रासंगिक नहीं है या यह रक्षोपाय शुल्क को शामिल करने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने नियमित रूप से रक्षोपाय शुल्क को छोड़कर पहुंच मूल्य की गणना की है।

- क्ष. इस तर्क का कोई आधार नहीं था कि महानिदेशक, रक्षोपाय ने घरेलू उद्योग की क्षति को आत्म-प्रवृत्त होना, माना था। किसी भी तरह से समीक्षा से इनकार करने वाले पत्र ने यह संकेत नहीं दिया कि सकारात्मक समायोजन की अनुपस्थिति के कारण समीक्षा शुरू नहीं की गई।
- त्र. याचिकाकर्ता ने अपनी समायोजन योजना का पालन किया था और इंडोनेशिया में पाम के तेल के विभाजन के लिए एक संयंत्र स्थापित किया था, क्योंकि प्राथमिक कच्चे माल निर्यात कर के अधीन थे। हालांकि, संयंत्र की स्थापना के बाद, इंडोनेशिया की सरकार ने मध्यवर्ती वस्तु पर भी निर्यात कर लगाया था। स्पष्ट है, संबद्ध देशों के उत्पादकों का इरादा उनकी सरकार के साथ मिलकर काम करके हमेशा भारतीय उद्योग को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए मजबूर करने का रहा है।
- ज्ञ. इस आरोप के जवाब में कि घरेलू उद्योग को क्षति इंडोनेशिया में उसके संयंत्र की वजह से हुई है क्योंकि वह पश्चवर्ती समेकित नहीं था, यह बताया गया कि घरेलू उद्योग एक ऐसे बाजार में बने रहने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है, जहां अनुचित प्रतिस्पर्धा है। ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग में पश्चवर्ती एकीकरण नहीं है, इसलिए इसे बंद करना चाहिए। किसी भी मामले में, इंडोनेशियाई कंपनी मौजूदा जांच की विषय-वस्तु नहीं है।
- कक. इसी तरह, अन्य पक्षों के लिए उपलब्ध कच्चे माल की कीमत वर्तमान जांच की विषय-वस्तु नहीं है।
- खख. यह दलील कि घरेलू उद्योग को अक्षमता की वजह से क्षति हुई है, गलत है। वास्तव में, घरेलू उद्योग कच्चे माल और सुविधाओं के उपयोग में अपनी क्षमताओं में सुधार करने में सक्षम रहा है।
- गग. यद्यपि, क्षति की अवधि में पंधुच कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन यह केवल संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण है। यद्यपि, पंधुच कीमत, लागत की तुलना में बहुत कम बनी हुई है, जिससे घरेलू उद्योग को लाभकारी कीमतें प्रभावित नहीं कर पा रहा है।
- घघ. इस संबंध में टिप्पणियों का जवाब देते हुए, यह स्पष्ट किया गया कि विभिन्न पीसीएन को ध्यान में रखते हुए, भारित औसत आधार पर कीमत का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार, कीमतें तुलनीय होने के बावजूद इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए कीमत कटौती में अंतर है।
- ङङ. क्षति मार्जिन का निर्धारण तीन अवधियों में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित नहीं होना चाहिए:
- विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग विभिन्न कार्बन श्रृंखला लंबाई के कच्चे माल के विनिर्माण के लिए किया जाता है।
 - इसके अलावा, एक ही कार्बन श्रृंखला की लंबाई के फैटी अल्कोहल के उत्पादन के लिए, वैकल्पिक कच्चे माल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
 - इसके अलावा, एक ही कच्चे माल की खपत अलग-अलग प्रकार के फैटी अल्कोहल के लिए अलग है।
- चच. वैकल्पिक रूप से, कच्चे माल के सबसे अच्छे उपयोग का विश्लेषण, कच्चे माल की खपत की समग्रता और विभिन्न प्रकार के फैटी अल्कोहल के उत्पादन की समग्रता को देखते हुए किया जाना चाहिए।
- छछ. चूंकि घरेलू उद्योग जुलाई, 2016 तक एक ईओयू के रूप में काम कर रहा था, इसलिए वह घरेलू स्तर पर अपने उत्पादन का एक हिस्सा ही बेच सकता था। घरेलू उद्योग के ईओयू योजना को छोड़ने के बाद घरेलू बिक्री के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षमता में वृद्धि हो गई। इस प्रकार, क्षमता उपयोग को निर्यात के लिए आशयित उत्पादन और ईओयू के रूप में निर्यात के लिए समर्पित क्षमता को छोड़कर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह प्राधिकारी की पिछली परिपाटी के अनुरूप है।

जज. चूंकि विभिन्न प्रकार के फैटी अल्कोहल एक ही संयंत्र में उत्पादित होते हैं, इसलिए क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग करने पर विचार उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि उपयोग उत्पादित प्रत्येक प्रकार का फैटी अल्कोहल और फैटी अल्कोहल के प्रकार के बीच स्विचओवर की संख्या जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

झझ. वर्ष 2013-14 एक असामान्य वर्ष था, जहां वैश्विक बाजार में आपूर्ति की कमी थी। घरेलू उद्योग ने इस कमी का फायदा उठाया और अधिक निर्यात किया, और रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने में सक्षम रहा। तथापि, जब कोई संयंत्र एक अस्थायी अवधि के लिए काफी ज्यादा श्रुपूट पर अधिक उत्पादन कर सकता है, परंतु वह इस तरह से निरंतर काम नहीं कर सकता। यदि संयंत्र लंबे समय तक अधिक काम करता रहे, तो यह दीर्घकाल में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 को असामान्य माना जाना चाहिए और क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग के निर्धारण में इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

जज. जांच की अवधि के लिए लागत में जांच की अवधि से पहले की अवधि के लिए कोई भी लागत शामिल नहीं है।

टट. बीएसआर एंड कंपनी से ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबंधित इकाई के लेनदेन पास के व्यापार के आधार पर किए गए हैं।

छ 2. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

56. निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. सऊदी अरब के लिए आयात की मात्रा संबद्ध वस्तु के आयात की कुल मात्रा का 1% से कम है, जिसके कारण क्षति का संचयी मूल्यांकन उचित नहीं है।
- ख. संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है।
- ग. संबद्ध देशों से आयात के परिणामस्वरूप कोई नकारात्मक मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयातों में निरंतर ही नहीं, न केवल पूर्ण रूप से, बल्कि भारत में उत्पादन और उपभोग के संबंध में भी गिरावट आई है।
- घ. क्षति की अवधि के दौरान कुल आयात में आयात का हिस्सा कम हो गया है।
- ङ. यदि सऊदी अरब के खिलाफ जांच समाप्त हो जाती है, तो वहां से आयात को क्षति के निर्धारण के लिए बाहर रखा जाना आवश्यक है।
- च. जांच के बाद की अवधि के लिए आकड़ों का विश्लेषण करने का कोई कारण नहीं है। क्षति अवधि और जांच की अवधि जांच शुरूआत के समय निर्धारित होती है और इसके बाद आयात की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है, और इसके विपरीत नहीं। घरेलू उद्योग ने ऐसे किसी भी पूर्व जांच परिणाम को नहीं बताया है, जहां प्राधिकारी ने क्षति के निर्धारण के लिए जांच के बाद की अवधि के आयात की मात्रा पर विचार किया है।
- छ. यदि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को जांच के बाद की अवधि के लिए जानकारी पेश करने का मौका दिया है, तो उसे पाटन के संबंध में निर्यातकों को भी ऐसी ही अनुमति देनी चाहिए।
- ज. घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों से कोई न्यूनकारी या हासकारी प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि बिक्री मूल्य में वृद्धि लागत में वृद्धि से अधिक है।
- झ. कीमत कटौती ऐसी स्थिति में प्रासंगिक नहीं है जहां कीमतों में कोई हास या मंदी नहीं है। यहां तक कि अगर यह प्रासंगिक माना जाता है, तो कीमत वचनबद्धता को निर्धारित किए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ञ. याचिकाकर्ता द्वारा की गई बिक्री प्राप्ति, बाजार की बिक्री प्राप्ति से अधिक है।

- ट. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग की साथ ही अन्य घरेलू उत्पादकों की भी बिक्री और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ गई है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट के लिए केवल घरेलू उद्योग के निर्यात में गिरावट जिम्मेदार हो सकती है।
- ठ. घरेलू उद्योग ईओयू से बाहर जाने के बावजूद, यह मुख्य रूप से निर्यात बाजार पर केंद्रित था। क्षमता को निर्धारित करने में निर्यात को हटाने से ऐसी परिस्थिति होगी जिसके तहत प्राधिकारी घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन में गिरावट की जांच नहीं कर पायेंगे।
- ड. यह दलील नहीं दी जा सकती कि घरेलू उद्योग ने ईओयू से डीटीए यूनिट के रूपांतरण के तुरंत बाद पूरे घरेलू बाजार पर कब्जा कर लेना चाहिए था। किसी भी मामले में, इस तरह के रूपांतरण का मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को निर्यात बिक्री करने से रोक दिया गया था।
- ढ. यद्यपि, घरेलू उद्योग को रक्षोपायों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया था, तथापि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता के आयात और घाटे के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- ण. यद्यपि जांच की अवधि के दौरान रक्षोपाय शुल्क सबसे कम था, तथापि इस अवधि के दौरान आयात में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, रक्षोपायों को समाप्त किया जाना पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए औचित्य नहीं बन सकता है।
- त. महानिदेशक, रक्षोपाय ने संभवतः शुल्क लगाये जाने के दौरान सकारात्मक समायोजन की अनुपस्थिति के कारण समीक्षा करने से इनकार कर दिया हो। प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि एक अन्य अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की क्षति की स्व-प्रवर्तित प्रकृति को स्वीकार किया है।
- थ. 2.5 साल तक रक्षोपाय शुल्क के लागू रहने के बावजूद, घरेलू उद्योग में सुधार नहीं हो पाया है। याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए बुलाया जाना चाहिए कि क्या समायोजन योजना लागू की गई थी और कथित क्षति का समाधान करने के लिए यह पर्याप्त क्यों नहीं सिद्ध हुई।
- द. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि के कारण याचिकाकर्ता को क्षति हुई है।
- ध. मांग में गिरावट और उद्योग में मंदी से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- न. निर्यात, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है, जिसने इसके कार्यनिष्पादन को प्रभावित किया है।
- प. यह स्पष्ट नहीं है कि याचिका में दी गई जानकारी को घरेलू और निर्यात बाजार के लिए अलग किया गया है। इसके अलावा, इस आशय के लिए उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग के लिए समायोजित आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।
- फ. प्रमुख कच्चे माल की मुक्त उपलब्धता के कारण निर्यातक अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों को निर्यात कर सकते हैं। दूसरी ओर, घरेलू उत्पादकों को ऐसे कच्चे माल के आयात पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, इंडोनेशिया से आयातित कच्चा माल निर्यात कर के अधीन है, जिससे यह महंगा हो जाता है।
- ब. प्रतिवर्ती शुल्क संरचना, कच्चे माल की अनुपलब्धता, प्रतिस्थापनों की बिक्री में वृद्धि, ओलेकैमिकल्स की अधिशेष क्षमता और ऋण के संवितरण में देरी के कारण याचिकाकर्ता उद्योग को क्षति हुई है। याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट में भी इसे स्वीकार किया गया है।
- भ. इंडोनेशिया में याचिकाकर्ता का संयंत्र पश्चवर्ती एकीकृत नहीं है, जिसके कारण इसे पाम आयल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति सीमित है। इसके अलावा, संयंत्र कम ऋण योग्यता और उच्च बैंक वित्तपोषण लागत के नुकसान से ग्रस्त है।
- म. याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गए कच्चे माल की लागत की तुलना उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए कच्चे माल की लागत से और प्रसंस्करण के लिए याचिकाकर्ता को दिए गए माल से की जानी चाहिए।

- य. कच्ची सामग्री और दक्षता ने घरेलू उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जैसा कि याचिकाकर्ता के विवरण से स्पष्ट है कि यह सुविधाओं के कुशल उपयोग के कारण लागत को कम करने में सक्षम था।
- र. संबद्ध वस्तुओं के पंधुच मूल्य में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ।
- ल. यद्यपि, मलेशिया और इंडोनेशिया से आयातित माल की कीमत में अंतर केवल 2 रुपये प्रति किलोग्राम है तथापि कीमत कटौती में काफी अधिक अंतर है।
- व. अगर जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए केवल आर्थिक मापदंड प्रासंगिक हैं, तो घरेलू उद्योग को वर्तमान आवेदन वापस ले लेना चाहिए और एक संशोधित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें नई जांच अवधि का प्रस्ताव हो।
- श. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में क्षति का दावा शामिल नहीं था। जांच के बाद घरेलू उद्योग क्षति के खतरे का अतिरिक्त आधार नहीं जोड़ सकता है। किसी भी स्थिति में, क्षति के खतरे के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले आकड़े जांच की अवधि के बाद के हैं, जो मूल जांच में प्रासंगिक नहीं हैं।
- स. क्षति विश्लेषण C8 और C10 को छोड़कर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विश्लेषण भी अलग पीसीएन के लिए अलग से किया जाना चाहिए।
- ह. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है:
- i. एशियाई देशों से संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कम हो गई है।
 - ii. घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास नहीं किया गया है।
 - iii. याचिकाकर्ता ने अपने इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि अन्य बाजारों की तुलना में भारतीय कीमतें आकर्षक हैं। इसके अलावा, यदि भारतीय बाजार में कीमत उच्चतम में से एक है, तो घरेलू उद्योग में क्षति का प्रश्न नहीं उठता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

57. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोधों की प्राधिकारी ने जाँच की है और संगत मापदंडों के अधीन नीचे उनका समाधान किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न विविध अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :

- क. जैसा कि हितबद्ध पक्षों द्वारा बताया गया है, इस तरह के विश्लेषण से सी 8 और सी 10 और मिश्रित C8C10 से आयात को छोड़कर क्षति विश्लेषण करना होगा। अतः प्राधिकारी ने ऐसे उत्पाद प्रकारों को क्षति विश्लेषण से बाहर रखा है जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
- ख. इस अनुरोध में कोई दम नहीं है कि क्षति विश्लेषण पीसीएन के अनुसार किया जाना चाहिए। पीसीएन को परिभाषित करने का उद्देश्य सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के साथ और पंधुच मूल्य और गैर-हानिकारक कीमत के साथ उचित तुलना सुनिश्चित करना है। तथापि, पाटन, क्षति और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी वर्तमान जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि पीसीएन के अनुसार।
- ग. प्राधिकारी की यह संगत स्थिति रही है कि घरेलू उद्योग को क्षति को यथा रूप में देखा जाए और मान्यताओं या आदर्श परिस्थितियों के आधार पर नहीं।
- घ. यह तथ्य कि महानिदेशक, रक्षोपाय ने समीक्षा जांच शुरू करने से इनकार कर दिया, घरेलू उद्योग को क्षति की अनुपस्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता है। रक्षोपाय शुल्क और पाटनरोधी शुल्क अलग-अलग स्थितियों के लिए

होते हैं और भिन्न कानूनों के तहत संचालित होते हैं। सिर्फ इसलिए कि महानिदेशक, रक्षोपायों ने समीक्षा शुरू नहीं की थी, घरेलू उद्योग को प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क के रूप में आवश्यक सुरक्षा हेतु अनुरोध करने से रोक नहीं लग सकती है।

- इ. समायोजन योजना के परिणाम संबंधी अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में इंडोनेशिया में कच्चे माल के मध्यवर्ती वस्तु में प्रसंस्करण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है, क्योंकि कच्चा माल निर्यात कर लगाये जाने के अधीन था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जुलाई 2015 में संयंत्र की स्थापना के बाद, इंडोनेशिया सरकार ने मध्यवर्ती वस्तु के निर्यात पर निर्यात कर और सेवा टैरिफ भी लगाया था। तथापि, किए गए दावे को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, जब घरेलू उद्योग ने समायोजन योजना लागू की, उसे इसका कोई खास लाभ नहीं मिल सका।

झ. संचयी आकलन

58. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II (iii) और विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 में यह प्रावधान है कि यदि कहीं एक देश से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा
- (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध वस्तुएं भारत में संबद्ध देशों से पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. जांच समाप्त करने के बाद, जहां तक सऊदी अरब के संबंधित देशों में से एक होने का संबंध है, शेष देशों में से आयात की मात्रा व्यक्तिगत रूप से आयात की कुल मात्रा का 3% से अधिक है।
- ग. आयात के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों के निर्यात न केवल सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा बेची जा रही वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी आकलन करना उचित समझते हैं।

60. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए घरेलू की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

II. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**क. मांग का आकलन**

61. विभिन्न देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात निम्नानुसार हैं :

निर्यात का देश	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इंडोनेशिया	एमटी	13,218	26,363	11,275	12,132
मलेशिया	एमटी	28,230	31,498	24,865	20,096
थाइलैंड	एमटी	14,115	10,440	7,395	8,361
संबद्ध देश	एमटी	55,563	68,300	43,535	40,589
अन्य देश	एमटी	74	250	1,201	1,211
कुल आयात	एमटी	55,638	68,550	44,736	41,800

62. उक्त आयातों के आधार पर घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्रियां, भारत में मांग या खपत निम्नानुसार निर्धारित की गई है :

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	55,563	68,300	43,535	40,589
अन्य देशों से आयात	एमटी	74	250	1,201	1,211
घरेलू उद्योग की विक्रियां	एमटी	***	***	***	***
अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्रियां	एमटी	***	***	***	***
मांग	एमटी	90,282	92,405	98,573	90,781

63. उपर्युक्त तालिकाओं से, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- पाटित आयातों में जांच अवधि में विगत किसी भी वर्षों की तुलना में समग्र रूप से गिरावट आई है।
- भारत में खपत और उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों में कमी आई है।
- आयात में गिरावट रक्षोपायों को लगाने के कारण और मांग में गिरावट के कारण आई है।

आयातों की मात्रा

64. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात निम्न तालिका से देखे जा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात कम हुए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयात में अचानक वृद्धि के कारण उत्पाद 28 अगस्त, 2014 से रक्षोपायों की लेवी के अधीन रहा है। रक्षोपायों को लगाने से आयात में वृद्धि नियंत्रित हुई है, जिससे क्षति की अवधि के दौरान आयात में गिरावट आई है।

निर्यात का देश	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
इंडोनेशिया	एमटी	13,218	26,363	11,275	12,132
मलेशिया	एमटी	28,230	31,498	24,865	20,096
थाइलैंड	एमटी	14,115	10,440	7,395	8,361
संबद्ध देश	एमटी	55,563	68,300	43,535	40,589

क. भारत में खपत के संबंध में आयात

65. रक्षोपाय शुल्क लागू होने के बाद, भारत में खपत में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में इस अवधि में कमी आई है। इसके अलावा, ऐसे आयातों का हिस्सा काफी अधिक बना हुआ है जो जॉच अवधि में 40 प्रतिशत से अधिक है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मांग	एमटी	90,282	92,405	98,573	90,781
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	62%	74%	44%	44%
अन्य देशों का हिस्सा	%	0.08%	0.27%	1.22%	1.33%
घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	***	***	***	***
अन्य घरेलू उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***

ख. घरेलू उत्पादन के संबंध में आयात

66. नीचे तालिका में दर्शाया गया है कि आयातों का घरेलू उत्पादन में 40 प्रतिशत हिस्सा है जो काफी अधिक है। तथापि, इस अनुपात में 2014-15 से जॉच अवधि तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है जिसका कारण विचाराधीन उत्पाद के आयात में पहले काफी तेजी से वृद्धि होने की वजह से उन पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना था।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	55,563	68,300	43,535	40,589
घरेलू उत्पादकों का उत्पादन	एमटी	1,43,232	1,09,837	94,797	94,949
उत्पादन के संबंध में हिस्सा	%	39%	62%	46%	43%

III. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क. कीमत कटौती

67. कीमत कटौती निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए, निवल बिक्री प्राप्ति की गणना बाह्य माल और करों की कटौती के बाद की गई है। प्राधिकारी इस तथ्य का संज्ञान लेते हैं कि 1% प्रहस्तन प्रभार और संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य के उपर सहित मूल सीमा शुल्क लागू करने के बाद आयात का पंहुच मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। यद्यपि, कीमत कटौती निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ पंहुच मूल्य निर्धारित करने के लिए रक्षोपायशुल्क को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकारी ने पिछले मामलों में, लगातार यह दृष्टिकोण रखा है कि पंहुच कीमत की गणना रक्षोपाय शुल्क को छोड़कर की जाएगी। इसलिए, वर्तमान मामले में भी, कीमत कटौती को रक्षोपाय शुल्क को छोड़कर पंहुच कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।

68. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संबद्ध आयात की पंहुच कीमत की पीसीएन-वार तुलना के अनुसार, यह पाया गया कि ऐसे आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री में अंतर होने का एक कारण विभिन्न निर्यातकों और घरेलू उद्योग के उत्पाद मिश्रण में अंतर हो सकता है।

आक.डे रु./किग्रा. में

विवरण	पंहुच कीमत	बिक्री कीमत	कीमत कटौती	कीमत कटौती %	रेंज %
इंडोनेशिया	133.20	***	***	***	0-10
मलेशिया	129.40	***	***	***	10-20
थाइलैंड	142.90	***	***	***	0-10
संबद्ध देश	133.00	***	***	***	10-15

ख. कम कीमत पर बिक्री

69. कम कीमत पर बिक्री के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के उपबंधों के अनुसार क्षतिरहित कीमत ज्ञात की गई है और पीसीएन-वार संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत के साथ उसकी तुलना की गई है। रक्षोपाय शुल्क को अलग रखकर पंहुच कीमत निर्धारित की गई है। विश्लेषण से पता चलता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से कम कीमत पर बिक्री न केवल सकारात्मक है बल्कि काफी अधिक भी है।

आक.डे रु./किग्रा. में

विवरण	पंहुच कीमत	क्षतिरहित कीमत	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री %	रेंज
इंडोनेशिया	***	***	***	***	0-5
मलेशिया	***	***	***	***	10-20
थाइलैंड	***	***	***	***	0-10
संबद्ध देश	***	***	***	***	0-10

ग. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

70. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों का प्रभाव भारत में समान उत्पादों की कीमत को काफी अधिक कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी उच्च स्तर तक बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री लागत और बिक्री कीमत के विश्लेषण से ऐसा लगता है कि संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत निरंतर लागत से कम रही है। इससे यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री लागत	रु./किग्रा	***	***	***	***
बिक्री लागत	सूचीबद्ध	100	114	95	121
बिक्री कीमत	रु./किग्रा	***	***	***	***
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	108	98	135
पंहुच मूल्य	रु./किग्रा	***	***	***	***
पंहुच मूल्य	सूचीबद्ध	100	103	90	139

IV. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड**क. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग**

71. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति अवधि के दौरान समान बनी रही है जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क्षमता	एमटी	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
उत्पादन	एमटी	93,297	57,307	56,922	56,527
क्षमता उपयोग	%	78%	48%	47%	47%

72. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान कमी आई है। क्षमता उपयोग में ऐसी गिरावट का प्रमुख कारण घरेलू उद्योग के निर्यातों में गिरावट रहा है।

ख. बिक्री मात्रा

73. जैसा नीचे आकड़ों से देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग की बिक्री में 2014-15 के दौरान कमी आई है। उसके बाद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री निरंतर बढ़ रही है। तथापि बिक्री में वृद्धि को रक्षोपाय शुल्क लागू होने के बाद आयातों में कमी से सीधे जोड़ा जा सकता है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	54	124	134
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	68	37	33

ग. मालसूची

74. घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची की प्रवृत्ति से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची क्षति अवधि के दौरान एकत्रित हो गई है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
औसत स्टाक	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	120	112	130

घ. लाभ/हानि

75. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपनी लागतों को वसूल करने में सक्षम नहीं रहा है। रक्षोपायों के संदर्भ में अपनाई गई समायोजन योजना के बाद, घरेलू उद्योग ने उत्पादन की लागत को कम करने के लिए कुछ सुधार किए। इसके फलस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुए घाटों में कमी आई है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु/किग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(142)	(78)	(50)
लाभ/(हानि) कुल	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(86)	(51)	(37)

इ. नकद प्रवाह

76. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थिति पर नकद प्रवाह पर पाटन के प्रभाव की जाँच करने के लिए नकद लाभ की प्रवृत्ति की जाँच की है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रति इकाई नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(119)	(68)	(48)

च. निवेश पर आय

77. चूंकि घरेलू उद्योग अब भी घाटा उठा रहा है इसलिए निवेश पर उसकी आय क्षति अवधि में ऋणात्मक रही है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लाभ/(हानि) कुल	लाख रुपये	***	***	***	***
ब्याज	लाख रुपये	***	***	***	***
पीबीआईटी	लाख रुपये	***	***	***	***
नियोजित पूंजी	लाख रुपये	***	***	***	***
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
निवेश पर आय	सूचीबद्ध	(100)	(163)	(71)	(5)

छ. उत्पादकता

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता, प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	61	61	61
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	56	58	58

छ. रोजगार और मजदूरी

79. इससे यह देखा जाता है कि रोजगार के स्तर में पहले 2014-15 तक वृद्धि हुई और उसके बाद गिरावट आई। तथापि, जाँच अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
रोजगार	सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	106	104
मजदूरी	लाख रुपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	83	101

झ. पाटन की मात्रा

80. पाटन का मार्जिन उस सीमा का संकेतक हो सकता है जिस तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक संबद्ध देश के लिए निर्धारित यथोक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और पर्याप्त है।

ञ. वृद्धि

81. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग में जहां तक घरेलू बिक्रियों का संबंध है रक्षोपाय शुल्क के लागू होने के बाद कुछ सकारात्मक वृद्धि हुई है। लाभ के मामले में, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में, उनमें क्षति अवधि के दौरान सुधार दर्ज हुआ है परंतु ऋणात्मक बने रहे हैं।

विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री मात्रा	सूची	100	54	124	134
लाभ	सूची	(100)	(142)	(78)	(50)
नकद लाभ	सूची	(100)	(119)	(68)	(48)
निवेश पर आय	सूची	(100)	(163)	(71)	(5)

ट. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

82. लाभप्रदता, नकदी प्रवाह नकारात्मक होने से संकेत मिलता है कि यदि समाधान नहीं किया गया तो इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता लगातार पाटन से प्रभावित होगी।

V. क्षति संबंधी अवलोकन

83. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित सारांश तक पहुंचा जा सकता है:

- क. अगस्त, 2014 में रक्षोपायों के लागू होने के कारण, संबद्ध देशों के आयातों में समग्र रूप से गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, भारत में उत्पादन या उपभोग के संबंध में भी आयात कम हो गये हैं।
- ख. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, और कम कीमत पर बिक्री काफी अधिक है। इसके अलावा, आयातों से कीमत वृद्धि को रोकने का प्रभाव पड़ा है, जो अन्यथा बढ़ गई होती। हालांकि, रक्षोपायों के साथ कीमत कटौती नगण्य रही है।
- ग. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2014-15 तक कम हो गई, उसके बाद इसमें सुधार हुआ है।
- घ. घरेलू उद्योग को नकद घाटे का सामना करना पड़ रहा है और निवेश पर आय नकारात्मक है।
- ङ. सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
- च. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- छ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

VI. क्षति मार्जिन

84. भागीदार उत्पादक/निर्यातकों और असहयोगी पक्षों के लिए क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.स.	देश	उत्पादक	निर्यातक	पंहच मूल्य	एनआईपी	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %	रेंज
1.	इंडोनेशिया	मै. पीटी इकोग्रिन ओलियोकैमिकल्स	मै. इकोग्रिन ओलियोकैमिकल्स (सिंगापुर) पीटीई लि.	***	***	***	***	0-(10)
2.	इंडोनेशिया	मै. पीटी सुसिममास होल्लिंग्स पीटीईलि.	मै. इंटर कांटेनेंटल आयल्स एंड फैट्स पीटीई लि., सिंगापुर	***	***	***	***	0-10
3.	इंडोनेशिया	मै. पीटी विल्मर नाबाति	मै. विल्मर ट्रेडिंग पीटीई लि. सिंगापुर	***	***	***	***	0-10
4.	इंडोनेशिया	असहयोगी	असहयोगी	***	***	***	***	0-10
5.	मलेशिया	मै. एफपीजी ओलियोकैमिकल्स	मै. प्राक्टर एंड गैम्बल इंटरनेशनल आपरेशंस एसए, सिंगापुर	***	***	***	***	0-10
6.	मलेशिया	मै. केएल – केपोंग ओलियोमास एसडीएन बीएचडी	मै. केएल – केपोंग ओलियोमास एसडीएन बीएचडी	***	***	***	***	0-(10)
7.	मलेशिया	असहयोगी	असहयोगी	***	***	***	***	0-10
8.	थाइलैंड	मै. थाइ फैटी अल्कोहल्स कं. लि.	मै. थाइ फैटी अल्कोहल्स कं. लि.	***	***	***	***	0-(10)
9.	थाइलैंड	असहयोगी	असहयोगी	***	***	***	***	0-10

ज. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

85. भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार के अधीन सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मापदंडों की यह देखने के लिए जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है जो निम्नानुसार है :

क. संबद्ध देश से इतर देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य - संबद्ध देशों से इतर अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयात मात्रा के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं, जो कुल आयातों का संचयी रूप से 3 प्रतिशत से कम रहे हैं। निःसंदेह ऐसे आयातों घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते हैं।

ख. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन – संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में जाँच अवधि के दौरान थोड़ा संकुचन हुआ है। तथापि, बाजार ने खपत के पैटर्न में भी कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया है।

ग. प्रौद्योगिकी में विकास – किसी भी हितबद्ध पक्ष ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण विकास का ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति के बीच प्रतिस्पर्धा – संबद्ध वस्तु भारत में किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा से प्रभावित नहीं है। इसके अलावा किसी बाजार अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा के अलावा, कोई परस्पर प्रतिस्पर्धा या विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आपूर्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ. निर्यात कार्यनिष्पादन – घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन को संभव सीमा तक घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए अलग-अलग किया गया है। अतः, निर्यात कार्यनिष्पादन में कोई संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

कारणात्मक संबंध के बारे में समुक्तियां

86. कारणात्मक संबंधी के बारे में समुक्तियां निम्नानुसार हैं:

- क. संबद्ध देशों से आयात भारतीय बाजार में पाटित किए जा रहे हैं।
- ख. पाटित आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के की दृष्टि से गिरावट आई है।
- ग. घाटे की कीमतों पर बिक्री की वजह से पाटित आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर होने के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग बिक्री की पूरी कीमत वसूल करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है और परिणामस्वरूप लाभप्रदता कम हुई। इसलिए, यद्यपि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को बनाए रखने में सफल रहा है, लेकिन घाटे के कारण इसे नुकसान हुआ है।
- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।
- ङ. घरेलू उद्योग के निर्यात कार्यनिष्पादन में काफी गिरावट आई है।
- च. पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में गिरावट आई है।
- छ. इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि संबद्ध देशों से किए गए कुछ आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

क्षति रहित कीमत से निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण के बाद किए गए अनुरोध

87. घरेलू उद्योग ने बताया है कि प्राधिकारी ने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया है कि घरेलू उद्योग पहले एक पीओयू था और अब डीटीए है। इस तथ्य का न केवल योग्यता पर सीरधा प्रभाव और परिणाम होता है बल्कि क्षति और क्षति रहित कीमत के निर्धारण पर भी प्रभाव पड़ता है।

88. संबद्ध देशों से प्रत्येक निर्यातक के लिए परिकलित क्षति रहित कीमत या तो ऋणात्मक है या 5% से कम है। परिकलित एनआईपी अनावश्यक रूप से कम है एन आई पी से संबंधित चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है।

89. घरेलू उद्योग ने सुनवाई में बताया कि याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित ग्रेड वार उत्पादन लागत एन आईपी के परिकलन में विचार की जानी चाहिए।

90. सुनवाई में यह भी बताया गया है कि क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि 11 जुलाई, 2016 तक घरेलू उद्योग पी ओ यू स्कीम के अधीन प्रचालन कर रहा था। इस स्कीम के प्रावधानों के अधीन उसके लिए अपने उत्पाद के बड़े हिस्से को निर्यात करना अपेक्षित था और उसके थोड़े हिस्से को ही घरेलू बाजार में बेचा जा सकता था। अतः घरेलू उद्योग में केवल चालू वर्ष के क्षमता उपयोग का प्रयोग करने का अनुरोध किया है। वैकल्पिक रूप से यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्यात के लिए उत्पादन को किसी ईओयू इकाई के रूप में प्रचालित घरेलू उद्योग के उस प्रत्येक वर्ष के लिए क्षमता उपयोग के निर्धारण से बाहर रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने समतुल्य उत्पादन न को रखने का भी अनुरोध किया है क्योंकि पीयूसी के विभिन्न ग्रेडों को याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित किया जाता है।

91. सुनवाई में घरेलू उद्योग ने आगे बताया कि एल सी समर्थित ऋणदाताओं को व्यापार देय का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि घरेलू उद्योग द्वारा उन्हें वर्तमान देयता के रूप में मान्यता दी गई है।
92. घरेलू उद्योग ने फैटी एल्कोहल को मुख्य उत्पाद माना था और सभी अन्य एसिड, गिल्सरीन और अवशिष्ट को याचिका प्रस्तुत करने के समय उप-उत्पाद माना था। अब याचिकाकर्ता ने अंतिम चरण में यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को उक्त उप उत्पादों को संयुक्त उत्पाद मानना चाहिए।
93. कच्ची सामग्री की खपत के सदर्थ में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु की प्रकृति ऐसी है कि विभिन्न कार्बन लंबाई से फैटी एल्कोहलों के विनिर्माण के लिए अलग-अलग प्रकार की कच्ची सामग्री प्रयोग होती है और चूंकि विगत कुछ वर्षों में उत्पाद मिश्रण बदल गया है, इसलिए इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया कि मानक लागत या कच्ची सामग्री पर विचार करना उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अनुचित होगा।
94. पैकिंग खर्चों को स्थिर खर्च माना जाना : घरेलू उद्योग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है कि क्या पैकिंग खर्चों को स्थिर व्यय अथवा परिवर्तनशील व्यय माना जा रहा है।
95. एनआईपी निर्धारण में अपनाए गए कार्पोरेट व्यय जैसे याचिकाकर्ता को वर्किंग शीट में दर्शाए गए थे, कमतर राशि दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग ने स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है।
96. ब्याज कमाने वाले ऋणदाताओं, प्राप्त आय और प्राप्तव्य शुल्क वापसी संबंधी व्यवहार: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ब्याज कमाने वाले ऋणदाताओं को वर्तमान देयता नहीं माना जाना चाहिए और यह कि प्राप्त आय और प्राप्तव्य शुल्क वापसी को वर्तमान परिसंपत्तियों का हिस्सा माना जाना चाहिए था।
97. अनिवार्य तथ्यों अर्थात् संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों, पहुंच कीमत वास्तविक पाटन मार्जिन, दस्तावेज और अनुरोध और क्षति मापदंड तथा कार्यशील पूंजी का निर्धारण और क्षतिरहित कीमत का अपर्याप्त प्रकटन किया गया है।
98. घरेलू उद्योग ने भी यह बताया है कि निर्यातकों के उत्तर बिल्कुल अधूरे हैं और ऐसी कमियों को प्रकटन विवरण में पूरी तरह नहीं दर्शाया गया है। उन्होंने ऐसे कारकों की पुनः जांच का अनुरोध किया है।
99. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण में विश्लेषित संख्या के संबंध में भी दलील दी है। उन्होंने यह दलील भी दी कि प्राधिकारी, यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के समय घरेलू उद्योग के इस दावे को स्वीकार किया था कि उन्हें शुल्क समाप्त होने के बाद भारी क्षति उठानी पड़ सकती है, प्रकटन विवरण में उसकी जांच नहीं की गई है।

निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद के अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जांच

100. घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। क्षति से संबंधित सभी मापदंडों में सकारात्मक रुझान प्रदर्शित हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई कोई भी क्षति पाटन से संबंधित कारकों के कारण नहीं हुई है।
101. कुछ हितबद्ध पक्षों ने यह अनुरोध भी किया है कि घरेलू उद्योग के निवेश संबंधी गलत निर्णय और निर्यात कार्य निष्पादन में गिरावट उन्हें हुई क्षति का एकमात्र कारण है। उन्होंने आगे बताया कि कथित क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
102. यह कि कम कीमत पर बिक्री से संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया गया परिकलन गलत है विशेष रूप से तब जबकि अधिकांश सहयोगी निर्यातकों के अधिकांश आयात नकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शा रहे हैं।
103. कुछ हितबद्ध पक्षों ने एनआईपी और कम कीमत पर बिक्री की गणना की पद्धति के संबंध में आपत्ति उठाई है।
104. एक निर्यातक ने एस जी एंड ए व्ययों के संबंध में किए गए समायोजनों की गणना के बारे में टिप्पणियां की हैं और पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया है।

105. कुछ हितबद्ध पक्षों ने कतिपय प्योर कट को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने के अपने अनुरोध को पुनः दोहराया है।

106. कुछ हितबद्ध पक्षों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से रक्षोपाय महानिदेशक के समक्ष वचनबद्ध समयोजन योजना का कोई लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहा है।

107. कुछ हितबद्ध पक्षों ने बताया है कि पुरानी क्षमता संबंधी अवरोधों के कारण घरेलू उद्योग अपनी वित्तीय स्थिति को अधिकतम करने में सक्षम नहीं रहा है। इसके अलावा, विश्व के अन्य उत्पादक भारी क्षमताओं के कारण पैमाने की किफायतों का लाभ उठाते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच :

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति के हैं और प्रकटन विवरण में उनका पहले ही समाधान कर दिया गया है। उक्त निष्कर्ष घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षों के ऐसे सभी तर्कों से संबंधित हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने नीचे हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों की संगत सीमा तक जांच की है जिनका कहीं और समाधान नहीं किया गया है।

109. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि एनआईपी की गणना सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह 11 जुलाई, 2016 तक एक पीओयू के रूप में कार्य कर रहा था। दूसरे शब्दों में याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अधीन प्रदत्त एनआईपी नियमों को इसलिए लागू नहीं करने का अनुरोध करता है कि घरेलू उद्योग पीओयू के रूप में कार्य कर रहा था। यह बताया गया है कि एनआईपी की गणना याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में प्रदत्त एनआईपी की गणना के सिद्धांतों के अनुसार की गई है। पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-3 एनआईपी के निर्धारण की प्रक्रिया को संहिताबद्ध करता है। प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और केवल इसलिए विहित नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वर्तमान मामले में नियमों को लागू करना अनुचित है। किसी भी तरह से याचिकाकर्ता कंपनी की प्रक्रियाएं समान रहती हैं चाहे वह पीओयू हो अथवा डीटीए। याचिकाकर्ता का समतुल्य उत्पादन का दावा इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि घरेलू उद्योग ने ग्रेडों अथवा समतुल्य उत्पादन के आधार पर निर्धारित की जा रही संयंत्र की क्षमता के अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए घरेलू उद्योग के दावों में कोई तथ्य नहीं है।

110. ग्रेड-वार एनआईपी से संबंधित मुद्दे के बारे में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में प्रपत्र-क में कच्ची सामग्री के ग्रेडवार ब्यौरे प्रदान किए हैं जो विभिन्न ग्रेडों के वर्ष वार निविष्टि-उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाते हैं :

क. घरेलू उद्योग द्वारा यथाप्रदत्त ग्रेड-वार इनपुट आउटपुट :

2016-17

ग्रेड	वी12:14	वी 12:16	वी 12:18	वी 16:18	वी 16:98	वी 18	कुल
इनपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
आउटपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
अनुपात	***	***	***	***	***	***	***

2015-16

ग्रेड	वी12:14	वी 12:16	वी 12:18	वी 16:18	वी 16:98	वी 18	कुल
इनपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
आउटपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
अनुपात	***	***	***	***	***	***	***

2014-15

ग्रेड	वी12:14	वी 12:16	वी 12:18	वी 16:18	वी 16:98	वी 18	कुल
इनपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
आउटपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
अनुपात	***	***	***	***	***	***	***

2013-14

ग्रेड	वी12:14	वी 12:16	वी 12:18	वी 16:18	वी 16:98	वी 18	कुल
इनपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
आउटपुट एमटी	***	***	***	***	***	***	***
अनुपात	***	***	***	***	***	***	***

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रेड वी 16:98 की कच्ची सामग्री की खपत *** एमटी, उत्पादन के लिए शून्य है। इसी प्रकार, वी-17 के *** एमटी उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री की उत्पादन की खपत केवल *** एमटी है। इसी प्रकार अन्य वर्षों में कुछ ग्रेड में उत्पादन इनपुट से अधिक है। उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुछ ग्रेडों का उत्पादन शून्य कच्ची सामग्री से होता है और कुछ ग्रेड ओवरलोडेड हैं।

ख) उप उत्पाद से संबंधित मुद्दे जब घरेलू उद्योग के कानूनी परामर्शदाता द्वारा उठाए गए तो यह स्पष्ट किया गया कि प्रकटन क और ख को उप उत्पाद के समायोजन के बाद तैयार किया गया है। कंपनी ने एक विवरण दिया जो उप उत्पाद के समायोजन के समर्थन साक्ष्य के बिना वर्ष 2016-17 के दौरान पीयूसी में उत्पादित *** एमटी उप उत्पाद को दर्शाता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग ग्रेड-वार उप उत्पाद समायोजन प्रदान करने में विफल रहा है।

ग) याचिकाकर्ता द्वारा कुछ कच्ची सामग्री अपनी संबंधित इकाई में, सीसी वीवीएफ इंडोनेशिया, वीवीएफ सिंगापुर पीटीई लिमिटेड और वीवीएफ लिमिटेड से खरीदी गई थी। वीवीएफ इंडोनेशिया को रसायनों (उदाहरण के लिए कूड पाम केनल आयल को) अर्द्ध निर्मित/ प्रसंस्कृत सामग्री अर्थात् स्प्रिट फैटी एसिड और कच्चे ग्लिसरीन को तरल रूप में प्रसंस्कृत करने और विनिर्मित करने के लिए तथा उसकी बिक्री समूह इकाइयों मुख्यतः वीवीएफ इंडिया को करने के लिए स्थापित किया गया था। इन वस्तुओं को एफओबी आधार पर और परस्पर रूप से सहमत कीमत जिसे उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है, पर आयातित किया गया है। वीवीएफ इंडोनेशिया की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार— “ चूंकि वीवीएफ इंडोनेशिया का एनसीपी (कुल प्रचालन लागत द्वारा विभाजित निवल लाभ) तुलनीय कंपनियों के एनसीपी मार्जिन के अंकगणित माध्यम से कम *** है, इसलिए वीवीएफ इंडोनेशिया से वस्तुओं की खरीद के अंतर्राष्ट्रीय सौदे भारतीय अंतरण कीमत विनियम परिप्रेक्ष्य से नजदीकी मानक से सुसंगत हैं। परंतु, कंपनी संबंधित इकाई से और असंबंधित इकाई से खरीद के बारे में प्रपत्र-क से मिलते जुलते ब्यौरे देने में विफल रही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि फैटी एल्कोहल के किस ग्रेड को याचिकाकर्ता ने संबंधित यूनिट से खरीदी गई कच्ची सामग्री में प्रयोग किया है।

घ) प्रमाणित सीआईआई (मदवार लागत) के अनुसार याचिकाकर्ता ने कारोबार के आधार पर विनिर्माण व्यय, वेतन और मजदूरी, मूल्यहास आदि आवंटित किया है। चूंकि विभिन्न ग्रेडों की प्रति यूनिट बिक्री वसूली में अत्यधिक अंतर व्याप्त है, इसलिए डीजीएडी द्वारा उत्पादन मूल्य (किसी ग्रेड विशेष, उप ग्रेड की X प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति की उत्पादन मात्रा) की पद्धति अपनाई गई थी।

ड.) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दिनांक 2 जून, 2017 के अपने पत्र द्वारा पीसीएन वार आंकड़े प्रदान किए हैं परंतु जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग पीसीएनवार लागत निर्धारित करने में प्रयुक्त विभिन्न आवंटन अनुपातों जैसे असामान्य इनपुट-आउटपुट अनुपात, उप उत्पाद समायोजन, सुविधा और अन्य वास्तविक के रूप में दावा किए गए व्यय, संबंधित पक्षों से खरीदी गई कच्ची सामग्री से पीसीएनवार उत्पादन आदि का कोई औचित्य बताने में विफल रहा है। तत्पश्चात् जब घरेलू उद्योग ने प्रमाणित लागत आंकड़े उपलब्ध कराए तो घरेलू उद्योग ने जांच के अंतिम चरण में अपनी आवंटन पद्धति को पूरी तरह बदल दिया। इसके अलावा, कुल समग्र स्तर पर प्रमाणित लागत आंकड़े पीसीएनवार बिक्री लागतों से मेल नहीं खाते हैं। अतः प्राधिकारी ने सर्वोत्तम संगत पद्धति के अनुसार पीसीएनवार एनआईपी निर्धारित की है जिसे प्राधिकारी ने संगत रूप से अपनाया है। चूंकि सहयोगी निर्यातकों से उत्पादन कील लागत निर्धारित करने के लिए भी यही पद्धति अपनाई गई थी, इसलिए घरेलू उद्योग के दावे में कोई तथ्य नहीं है।

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एलसी समर्थित ऋणदाताओं से संबंधित राशि को व्यापार देयता सहित वर्तमान देयता के रूप में माना है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग तैयार सामान की निर्यात बिक्रियों, घरेलू बिक्री और वस्तुओं के विनिर्माण के लिए इनपुट के आयातों के बीच एलसी प्रभारों का कोई विभाजन प्रस्तुत करने में विफल रहा था। चूंकि घरेलू उद्योग कोई विभाजन प्रस्तुत कराने में विफल रहा है और यह तथ्य कि घरेलू उद्योग स्वयं एल सी प्रभारों को व्यापार देयता मान रहा है, इसलिए प्राधिकारी अलग दृष्टिकोण नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा, डीजीएडी ने कानूनी लेखा परीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित वास्तविक लेखा परीक्षित लेखा बहियों पर भरोसा किया है, इसलिए प्राधिकारी ऐसे लेखा परीक्षित रिकॉर्डों से अलग नहीं जा सकते हैं। प्राधिकारी ने केवल लेखा परीक्षित रिकॉर्डों के अनुसार विविध ऋण धारकों पर विचार किया है यद्यपि घरेलू उद्योग ने बिल को व्यय के रूप में बताया है जिसकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है।

112. कंपनी ने 2 जून, 2017 के अपने पत्र/अद्यतन याचिका में पीओआई के लिए पी-॥ प्रस्तुत किए हैं (विचाराधीन उत्पाद के लिए शीर्षवार लागत दर्शाते हुए)। तथापि, सी-॥ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करते समय लागत आवंटन के आधार को बाद में संशोधित किया गया था। इससे एनआईपी की गणना का आधार निर्मित हुआ, घरेलू उद्योग का सत्यापन 17 और 18 अगस्त, 2017 को किया गया था। इसमें संशोधित आंकड़ों का औचित्य भी सत्यापित किया गया था। इस प्रकार, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ के अनुक्रम में कच्ची सामग्री की खपत के संबंध में प्रदत्त

प्रमाणित सी-॥ और प्रपत्र-क तथा प्रपत्र-ख के आधार पर पीयूसी के लिए एनआईपी परिकलित की थी। पीयूसी के लिए एनआईपी के परिकलन को घरेलू उद्योग को 28.3.2018 और 2.7.2018 को प्रकट किया गया था।

113. याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रकटन विवरण जारी होने के थोड़ी देर पहले दिनांक 14.03.2018 के अपने पत्र द्वारा याचिकाकर्ता के उत्पाद पोर्टफोलियों के गठन में बदलाव करके एनआईपी को संशोधित करने और उप-उत्पादों को संयुक्त उत्पाद मानने का अनुरोध किया था। यह दावा सत्यापन से काफी बाद में और वर्तमान जांच में लगभग 11 महीने बाद किया गया है। इतने नवीकृत आंकड़ों और आधार पर विचार करने के लिए पूर्ण रूप से नई जांच करना और शुरुआत से याचिकाकर्ता के लागत निर्धारण का आकलन करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा, ऐसे विचार करने के लिए आंकड़ों की पूर्णतः पुनः जांच अपेक्षित होगी जिससे एनआईपी के विस्तार से पुनः परिकलन के अलावा सभी संशोधित आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक हो जाएगा। चूंकि पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए इतने अंतिम स्तर पर पुनः जांच करना संभव नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा बार-बार लागत पद्धति में परिवर्तन करने की प्रक्रिया अन्य हितबद्ध पक्षों के लिए उचित नहीं है जो इन मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां भी देना चाहते होंगे।

114. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने याचिका प्रस्तुत करने के दौरान और घरेलू सत्यापन के समय पहले ही यह स्वीकार किया है कि उसने सभी अन्य एसिडों, गिल्सरीन और अवशिष्ट को उप-उत्पाद माना है और न कि संयुक्त उत्पाद। इसलिए, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग से यह व्यवहार न करने का कोई आधार नहीं है। किसी भी मामले में सुसंगतता लागत सिद्धांतों का मूल आधार बनाती है।

115. घरेलू उद्योग ने प्रभावी रूप से दावा किया है कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ के प्रावधानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह अनुरोध किया गया है कि एनआईपी का परिकलन याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-॥ में प्रदत्त एनआईपी की गणना के सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-॥ एनआईपी के निर्धारण की प्रक्रिया को संहिताबद्ध करता है। इसमें पिछले तीन वर्षों की अवधि और जांच अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार करने का प्रावधान है। प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और विहित नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं।

116. पैकिंग खर्चों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उसे परिवर्तनशील व्यय माना गया है। तदनुसार, इसके लिए एनआईपी को उचित ढंग से पुनर्निर्धारित किया गया है।

117. कॉर्पोरेट एयर सेवाओं के लिए किए गए कॉर्पोरेट व्यय को प्राधिकारी की मानक प्रक्रिया के अनुसार कंपनी के सभी कार्यकलापों से अलग किया गया है।

118. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के उनके पत्र द्वारा किए गए दावों के आधार पर उधार पर प्राप्त ब्याज को वर्तमान देयता से अलग रखा गया है। तदनुसार, बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज को भी वर्तमान परिसंपत्तियों से घटाया गया है। अन्य प्राप्त आय के संबंध में प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कंपनी के दावे की अनुमति दी है और उसे वर्तमान परिसंपत्तियों में शामिल किया है। शुल्क वापसी प्राप्तव्य के संबंध में, चूंकि यह निर्यात विक्रियों से संबंधित है इसलिए घरेलू विक्रियों के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों के भाग के रूप में उस पर विचार नहीं किया गया है।

119. निर्यातक के गोपनीय आंकड़ों संबंधी अनुरोधों को याचिकाकर्ताओं या निर्यातक/हितबद्ध पक्षकार विशेष से इतर किसी हितबद्ध पक्ष को पाटनरोधी नियमावली के नियम-7 के अनुसार प्रकट नहीं किए जाने के संबंध में जैसा गोपनीय अंश को पहले ही साझा किया गया है।

120. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि एफपीजी पोलियो कैमिकल/डब्ल्यू आईएनए ने संबंधित पक्ष से कच्ची सामग्री खरीदी है और इसलिए उत्पादन लागत की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी ने एफपीजी/डब्ल्यूआईएनए के संबंधित पक्षों से नजदीकी कीमतों की पहले ही जांच की है और यह पाया कि इनपुट की खरीद उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त साक्ष्य के आधार पर नजदीकी कीमतों पर की गई है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने अपने संबंधित पक्ष से नजदीकी कीमतों पर भी कच्ची सामग्री की खरीद की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर अपने संबंधित पक्ष से अंतरण कीमत को स्वीकार किया है।

121. केएलके और पीजीआईओ के बीच सौदों के संबंध में प्राधिकारी ने इन सौदों की भी जांच की है और नोट किया है कि विभाजन प्रक्रिया में कोई खास मूल्यवर्धन नहीं होता है।

122. संबंधित इकाइयों द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए जाने के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मूल्य श्रृंखला के अधूरे होने के संबंध में अपने दावे को सही ठहराने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है। भारत को निर्यातों की मूल्य श्रृंखला तभी अधूरी हो सकती है यदि कंपनियां जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, भारत को संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का उत्पादन या निर्यात करती हो।

123. इस अनुरोध के संबंध में कि मलेशिया/थाइलैंड/इंडोनेशिया की सरकारों द्वारा अनेक सब्सिडियां दी जाती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भागीदार निर्यातकों द्वारा लिए जाने वाले किसी प्रोत्साहन या सब्सिडी के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

124. इस अनुरोध के संबंध में कि केएलकेओएम ने भी वितरकों के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केएलकेओएम द्वारा की गई सभी बिक्रियां भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे की गई थी।

125. मै. नेट ओलियो द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नेट ओलियो न तो संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल है और न ही पीओआई के दौरान उन्होंने भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

126. मै. अदानी विलमर लि. को सजीए लाभों और खर्चों को घटाने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अदानी सिसमर केवल कमीशन एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और अदानी सिसमर को प्रदत्त कमीशन को पहले ही निर्यात कीमत से घटा दिया गया है।

127. थाई फैटी एल्कोहल लिमिटेड द्वारा एक संबद्ध कंपनी मै.एमरी ओलियो कैमिकल (एम)एसडीएन बीएचडी मलेशिया के प्रकटन नहीं करने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एमरी ओलियो कैमिकल, थाई फैटी एल्कोहल से घनिष्ठता से संबंधित नहीं है और न ही उनका साझा स्वामित्व और नियंत्रण सीधे पीएफए के पास है। इसके अलावा, एमरी ओलियोसे कैमिकल थाइलैंड के बजाए मलेशिया में स्थित हैं इसके कारण संयुक्त पाटन मार्जिन या सामान्य मूल्य परिकलन का प्रश्न नहीं उठता है। यदि प्राधिकारी ने मै. एमरी ओलियो कैमिकल को एक अलग विधिक सत्ता माना होगी तो उन्हें संबद्ध देश के रूप में थाइलैंड के बजाए मलेशिया को स्वीकार किया होता।

128. पीटीएमएमएस के संबंध में इंडोनेशिया में विभिन्न संयंत्रों के बारे में पीटीएमएमएस के अनुरोधों से यह नोट किया जाता है कि इसके बाद संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए इंडोनेशिया में केवल एक संयंत्र है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया है कि भारत में संबद्ध वस्तु के बारे में उनका कोई संबंधित पक्षकार नहीं है। उनकी वेबसाइट पर दर्शाई गई दो कंपनियां खाद्य प्रयोजन के लिए पाम आयल के परिष्करण में शामिल हैं और संबद्ध वस्तु के संबंध में उनका कोई संबंध नहीं है।

129. संबंधित उत्पादक और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के डेस्क सत्यापन और सतयता के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री सहित वित्त और लागत आंकड़ों तथा भारत को निर्यात कीमतों की विस्तार से जांच की है जैसा आम तौर पर मौके पर दौरे में भी किया जाता है। प्राधिकारी ने उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यता की जांच करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से भारत को निर्यातों की भी तुलना की है। इसके अलावा, निर्यातक के परिसर में सत्यापन करना या केवल अध्ययन करना प्राधिकारी के विवेक पर होता है। यदि डेस्क सत्यापन किया जाता है तो प्राधिकारी की विगत परिपाटी में सत्यापन रिपोर्ट जारी करना शामिल नहीं है। इसके अलावा, समस्त सूचना गोपनीय प्रकृति की है और उसका सारांश संभव नहीं है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की सत्यापन रिपोर्ट को अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं करते और न ही इसके विपरीत कार्य करते हैं।

130. क्षति मापदंडों संबंधी आंकड़े घरेलू उद्योग के सीआई में प्रदत्त आंकड़ों से लिए गए हैं।

131. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग का यह दावा स्वीकार किया है कि शुल्क की समाप्ति के बाद भारी क्षति हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के समय क्षति के कारक की विस्तार से जांच नहीं की है और केवल घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे को माना है। दावे को केवल मानने का अर्थ उसे स्वीकार करना नहीं होता है।

132. प्राधिकारी ने एनआईपी के परिकलन की पद्धति और कम कीमत पर बिक्री के परिकलन को प्रकटन विवरण में पहले ही प्रकट कर दिया है।

133. मै. प्रोक्टर एंड गैम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर द्वारा किए गए अनुरोध पर पुनः विचार किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि किए गए समायोजन, उनके द्वारा प्रदत्त वार्षिक आंकड़ों और संगत रूप से अपनाई गई विगत प्रक्रिया पर आधारित हैं।

134. मै. प्रोक्टर एंड गैम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर द्वारा किए गए अनुरोध पर पुनः विचार किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि किए गए समायोजन, उनके द्वारा प्रदत्त वार्षिक आंकड़ों और संगत रूप से अपनाई गई विगत प्रक्रिया पर आधारित हैं।

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय जांच परिणामों और समायोजन योजना के संबंधित मुद्दों का प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है। कारणात्मक संबंध से संबंधित मुद्दों के बारे में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है।

136. घरेलू उद्योग ने क्षतिरहित कीमत, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन और कतिपय सूचना प्रकटन नहीं करने से संबंधित मुद्दों के बारे में माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की रिट याचिका संख्या (एल) 1146 दायर की है। अब घरेलू उद्योग ने अपनी रिट याचिका को वापस ले लिया है।

निष्कर्ष

137. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद उसके सहयोजित सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है। इसके फलस्वरूप उत्पाद का पाटन हुआ है। कुछ आयातों के कारण भी घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हो रही है।

सिफारिशें

138. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और इसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू की गई थी और ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध हो जाने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और परिणामी क्षति के प्रतिकरण के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राधिकारी नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

140. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2905.17, 2995.19,3923.70	“सभी प्रकार के सेच्युरेटिड फैटी अल्कोहल्स जिनमें केप्रियल अल्कोहल (सी8), और डेजिल अल्कोहल (सी10), और सी-8 और सी-10 शामिल हैं”	इंडोनेशिया	सिंगापुर	इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स	मेसर्ज पीटी इकोग्रीन ओलियोकेमिकल्स	शून्य	एमटी	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मेसर्ज पीटी म्यूजिम मेस	मै. इंटर-कॉर्टिनेंटल ऑयल्स एंड फैट्स पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	7.10	एमटी	अम.डॉ.
3	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	सिंगापुर	मेसर्ज पीटी विल्मार नावाती	मेसर्ज विल्मर ट्रेडिंग पीटीई लि., सिंगापुर	52.23	एमटी	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	कोई	इंडोनेशिया	कोई	92.23	एमटी	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	कोई	92.23	एमटी	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	मलेशिया	सिंगापुर	एफपीजी ओलियोकेमिकल्स एसडीएन बीएचडी	मेसर्ज प्रोक्टर एंड गेम्बल इंटरनेशनल ऑपरेशन एसए, सिंगापुर	17.64	एमटी	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया	मेसर्ज केएल-क्रिपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी	मेसर्ज केएल-क्रिपोंग ओलियोमेस एसडीएन बीएचडी	शून्य	एमटी	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	मलेशिया	कोई	कोई	कोई	37.64	एमटी	अम.डॉ.
9	-वही-	-वही-	कोई	मलेशिया	कोई	कोई	37.64	एमटी	अम.डॉ.

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	-वही-	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज थाई फैटी अल्कोहल्स कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	अम.डॉ.
11	-वही-	-वही-	थाइलैंड	कोई	कोई	कोई	22.50	एमटी	अम.डॉ.
12	-वही-	-वही-	कोई	थाइलैंड	कोई	कोई	22.50	एमटी	अम.डॉ.

141. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

142. इस अंतिम जांच परिणाम के कारण उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2018

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Saturated Fatty Alcohols” originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia.

No. 14/51/2016-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Anti Dumping Rules) thereof M/s VVF (India) Limited (hereinafter also referred to as “the petitioner”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) in accordance with the Act and the Anti Dumping Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Saturated Fatty Alcohols” (also referred to as “the subject goods”), originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia and requested for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. Whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, issued a public notice vide Notification No. 14/05/2016-DGAD dated 24th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

3. Petitioner proposed the period from April 2015 to June 2016 as the period of investigation. During this period, the share of imports from Saudi Arabia of subject goods were more than 3 percent. However, the Authority has considered

the POI as 1 April, 2016 to 31 March, 2017(12 Months) so as to undertake dumping and injury analysis on the basis of most recent data .Furthermore, April 2016 to March 2017 corresponds to the time period when the company was a DTA unit and the same is the financial year for accounting purpose for the petitioner. Subsequent to initiation of investigation and during the course of the investigation, it was found that the volume of imports from Saudi Arabia accounted for less than three percent of the total imports of the subject goods during the POI considered by the Authority. Accordingly, Saudi Arabia has been excluded from the subject countries as per rule 14(d) of the AD Rules and the investigation has been conducted only in respect of imports of subject goods originating in or exported from Indonesia, Malaysia and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”).

A. Procedure

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- a. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the petitioner on behalf of the domestic industry, alleging dumping of the Saturated Fatty Alcohols originating in or exported from the subject countries.
- b. Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the petitioner and revised and updated petition was filed by the petitioner. The application was, therefore, considered as duly documented petition while considering initiation.
- c. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
- d. The Authority issued a public notice dated 24th April, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
- e. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers / exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the petitioner and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- f. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- g. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters / producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters were also sent to them along with the names and addresses of the known producers / exporters from the subject countries.
- h. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation has been considered as 1st April, 2016 to 31st March, 2017 (12 Months). The injury investigation period has been considered as the period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation.
- i. The Authority sent Exporter’s Questionnaires to elicit relevant information to the following known producers / exporters in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. M/s Musim Mas, Indonesia
- ii. M/s PT Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
- iii. M/s Emery Oleochemicals, Malaysia
- iv. M/s KKK Oleo, Malaysia
- v. M/s FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia
- vi. M/s Thai Oleochemicals Co. Ltd, Thailand
- vii. M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand
- viii. M/s SABIC Asia Pacific Pte Ltd., Singapore
- ix. M/s Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia
- x. M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia

j. The Authority also allowed extension of time for filing the questionnaire response initially upto 26th June, 2017, and ultimately, vide letter dated 23rd June, 2017, upto 3rd July, 2017.

k. The following producers / exporters filed a response to the Exporter's Questionnaire in the prescribed format:

- i. M/s PT Musim Mas Holdings Pte Ltd, Indonesia
- ii. M/s Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd., Singapore
- iii. M/s PT Ecogreen Oleochemicals, Indonesia
- iv. M/s Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd, Singapore
- v. M/s KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd, Malaysia
- vi. M/s FPG Oleochemicals Sdn Bhd
- vii. M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapore
- viii. M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.
- ix. M/s SABIC Asia Pacific Pte Ltd., Singapore
- x. M/s Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Arabia
- xi. M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
- xii. M/s Wilmar Trading Pte Ltd., Singapore
- xiii. M/s PT Wilmar Nabati Indonesia, Indonesia

As Saudi Arabia has been excluded from the subject countries in this investigation as per the provisions of Rule 14(d) of the Anti-Dumping Rules, the Authority has not considered the exporter questionnaire responses of exporters from Saudi Arabia.

l. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. M/s Galaxy Surfactants Limited, Navi Mumbai
- ii. M/s Viswaat Chemicals Limited, Mumbai
- iii. M/s Rhodia Speciality Chemicals India Ltd, Mumbai
- iv. M/s Indian Glycols Limited, Noida
- v. M/s Sterling Auxiliaries Pvt. Ltd., Mumbai
- vi. M/s Matangi Industries, Ahmedabad
- vii. M/s Venus Ethoxylates Pvt. Ltd, Goa
- viii. M/s Gujarat Chemicals, Surat
- ix. M/s Aarti Industries Limited, Mumbai
- x. M/s Kusa Chemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- xi. M/s Krishna Antioxidants Pvt. Ltd., Mumbai
- xii. M/s Majorhub Oleochemicals Pvt. Ltd., Mumbai
- xiii. M/s Hindustan Unilever Limited (HUL), Mumbai
- xiv. M/s Pan Oleo Enterprise Pvt. Ltd, Mumbai
- xv. M/s Cavinkare Private Limited, Chennai
- xvi. M/s Godrej Industries Limited, Mumbai

m. Importer's questionnaire response have been filed by the following parties in the prescribed format:

- i. M/s Indian Glycols Limited, Noida
- ii. M/s Eternis Fine Chemicals Ltd., Mumbai
- iii. M/s Galaxy Surfactants Limited, Navi Mumbai

n. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

o. The transaction-wise import data from DGCI&S was obtained for the injury period and relied upon for the purpose of the present investigation.

- p. Additional/supplementary information was sought from the petitioner and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters / producers, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present findings.
- q. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- r. In accordance with the provisions of Rule 6(6) of the Anti Dumping Rules, the Authority held an oral hearing on 11th January, 2018 and provided the interested parties an opportunity to present their views orally. All the interested parties who presented their views at the time of hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were also provided an opportunity to offer rejoinder submissions to the submissions made by opposing interested parties.
- s. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, have been considered and wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this findings.
- t. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the available facts.
- u. To ascertain whether anti dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry, the Non-Injurious Price (NIP) was worked out. For this purpose, the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India were calculated, on the basis of the information furnished by the domestic industry, and in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules.
- v. A Disclosure Statement was issued on 26.03.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 04.04.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- w. *** in this findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$ = Rs. 67.95.

B. Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration in the present investigation is " All types of Saturated Fatty Alcohols excluding Capryl Alcohols (C-8) and Decyl Alcohols(C-10) and blends of C8 and C10".

B.1. Submissions by the domestic industry

6. The domestic industry submitted as under with regard to the scope of product under consideration and like article:
- a. Fatty alcohols are aliphatic alcohols and occur in saturated and unsaturated forms. The general chemical formula for the product is $C_nH_{(2n+1)}CH_2OH$, where the value of "n" ranges from 7 to 17. The constituent materials of fatty alcohols are Decan-1-ol, N-Dodecanol, Tetradecanol, Hexadecan-1-ol, Octadecanol, Eicosan-1-ol, Eicosan-1-ol. These alcohols can be grouped according to the number of carbon atoms, and most common lengths are C12, C14 and blends thereof.

- b. Fatty alcohols may be in the form of high boiling liquid or soft colourless solid, depending upon the carbon chain length. It is used mainly as intermediary product, for further processing into fatty alcohol sulphates, fatty alcohol ethoxylates and fatty alcohol ether sulphates, also called surfactants.
- c. Fatty alcohols may be blended or unblended. Unblended fatty alcohols are covered under heading 2905.17 or 2905.19, while the blends are covered under heading 3823.70 of the Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.
- d. Fatty alcohols are sold in the form of flakes, pastilles, and liquids. As stated above, these alcohols can be categorized on the basis of the different carbon chain lengths. On this basis, the product under consideration can be classified into different categories.
- e. As the product can be produced in various grades, depending upon the carbon chain lengths, segregation on the basis of carbon chain type and use of a 4 digit Product Control Number (PCN) was proposed, in order to allow a reasonable and fair comparison between the imported product and domestic product, as well as for comparison of normal value and export price.
- f. The dumped product is similar to the saturated fatty alcohols produced by the petitioner and there are no material differences in the dumped product and the like product manufactured by the petitioner. The subject goods are commercially and technically substitutable to the like products produced by the petitioner. The dumped product and the like article produced by the petitioner are bought and sold by the same consumers / manufacturers of surfactants and other products, for the same or similar applications.
- g. While the petitioner has the capacity to produce pure C8 and C10 form of fatty alcohols, it has no objection to the exclusion of these grades from the scope of product under consideration, as the demand for these goods in India is extremely low.
- h. However, as regards the arguments raised by the other interested parties that C12 and C14 forms of fatty alcohols should also be excluded, it was submitted that such grades cannot be excluded for the reason that the blend C12C14 has the highest demand in India. If these grades are excluded, the importers would import C12 and C14, and carry out the blending into C12C14 in India by a simple physical process. Moreover, these grades are commercially interchangeable with other grades produced, and thus, they cannot be excluded.

B.2 Submissions by the exporters, importers and other interested parties

7. The following submissions were made by the exporters, imports and other interested parties with regard to the scope of product under consideration and like article:
- a. Pure forms of fatty alcohols such as Capryl Alcohol (C8), Decyl Alcohol (C10), Lauryl Alcohol (C12) and Myristyl Alcohol (C14), which are not being produced and commercially supplied by the petitioner, should be excluded from the scope of product under consideration.
 - b. Similarly, blends of carbon chains not specifically produced by the petitioner should also be excluded.
 - c. The domestic industry neither produces pure cuts, nor has the capability to produce them. There is lack of commercial and technological substitutability between the goods produced by the petitioner and pure cuts.
 - d. The information provided by the domestic industry in connection with regard to the product range, capacity and actual production should be disclosed to all parties.
 - e. The producers / exporters were not required to provide the data using the PCN methodology in the questionnaire responses. If the PCN methodology is adopted by the Authority, it should be made available to all the interested parties so that they can offer meaningful comments.

B.3 Examination by the Authority

8. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes as follows:

- a. Having regard to the submissions made by the domestic industry and other interested parties, pure forms of C8 and C10 alcohol, and blended C8C10 alcohol are excluded from the scope of product under consideration. The

product under consideration in the present investigation is, therefore, modified to "Saturated Fatty Alcohols with carbon chain length of C12, C14, C16, and C18 including single, blends and unblended (not including branched isomers) which includes blends of a combination of carbon chain lengths, C12-C14, C12-C16, C12-C18, C-16-18 and C14-C16".

b. By way of abundant precaution, it is clarified that unsaturated fatty alcohols are excluded from the scope of the present investigation.

c. The above mentioned subject goods are aliphatic alcohols and occur in saturated and unsaturated forms. The general chemical formula for the product is $C_nH_{(2n+1)}CH_2OH$, where the value of "n" ranges from 7 to 17. The constituent materials of fatty alcohols are Decan-1-ol, N-Dodecanol, Tetradecanol, Hexadecan- 1-ol, Octadecanol, Eicosan-1-ol, Eicosan-1-ol. These alcohols can be grouped according to the number of carbon atoms, and most common lengths are C12, C14 and blends thereof.

d. The subject goods are sold in the form of flakes, pastilles, and liquids. They are mainly used for the manufacture of surfactants, for personal care, home care, pharmaceutical and agriculture related end applications. They are also used in relation to processing of articles of leather, textile, fur, pulp, paper, petroleum products, fine chemicals, rubber products, plastics and fabricated metal products. Other applications include mining, offshore operations, construction work, as a solvent and for degreasing purposes. Blends of C12-C16 fatty alcohols are additionally used as synthetic intermediate or anti-freeze and as emulsifying agent. It also finds use in the production of paints, lubricants, cosmetics, food preparations, etc.

e. Unblended fatty alcohols are classified under heading 2905.17 or 2905.19, while blended alcohols are classified under heading 3823.70 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. Under the heading 3823.70, they are imported under the following tariff entries:

- i. 3823.70.10
- ii. 3823.70.20
- iii. 3823.70.40
- iv. 3823.70.90

The customs classification above is indicative only and in no way binding on the scope of the product under consideration in this investigation.

f. The exclusion of C8 and C10 form of fatty alcohols is warranted inasmuch as the domestic industry has neither produced the fatty alcohols, nor a product that may be considered as like article to these grades. The other interested parties have made submissions with regard to the lack of commercial interchangeability between C8 / C10 and the goods produced by the domestic industry. These submissions have not been controverted by the domestic industry. In fact, it has been admitted by the domestic industry that these may be excluded. Thus, the Authority takes note of the submissions by various parties, and finds it appropriate to exclude these grades from the scope of product under consideration.

g. As regards exclusion of pure form of C12 and C14 alcohols, the Authority finds force in the argument of the domestic industry that it has produced and sold C12C14 alcohol. In fact, C12C14 has the most demand in India. When the domestic industry has sold the blended form of these alcohols, the pure forms cannot be excluded, as such exclusion would defeat the very purpose of the duty. The Authority also takes note of the final findings of the Director General, Safeguards that these items are interchangeable and originate out of identical raw material by an identical manufacturing process. Thus, there is no warrant for the exclusion of C12 and C14 grades of fatty alcohols.

h. In order to ensure fair comparison for the purpose of determination of dumping margin and injury margin, the Authority has assigned a Product Control Number (PCN) to each grade. It was noted that none of the

interested parties have raised any objections with regard to the PCN methodology suggested by the domestic industry at the stage of petition. Thus, the Authority has opted to use the methodology suggested in the petition.

i. As regards the contention that the PCN methodology should be made available to all interested parties for comments, it is noted that the methodology was defined by the petitioners in the petition itself. Thus, the interested parties had plenty of opportunity to make comments in this regard.

9. In view of the above, the Authority concludes PUC as follows:

“All types of Saturated Fatty Alcohols excluding Capryl Alcohols (C-8) and Decyl Alcohols (C-10) and blends of C8 and C10”.

10. The petitioner has claimed that there are no known material differences between the subject goods exported from the subject countries, and that produced by the domestic industry. The subject goods are commercially and technically substitutable to the products produced by the petitioner; and are bought and sold by the same consumers / manufacturers of surfactants and other products, for the same or similar applications. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority has treated the subject goods produced by the petitioning domestic industry as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

C. Domestic Industry and Standing

11. The present application has been filed by M/s VVF (India) Limited, which is a domestic producer of the product under consideration in India.

C.1 Submissions by the domestic industry

12. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry and standing are as follows:

a. Apart from the petitioner, the subject goods are being produced by M/s Godrej Industries Limited. However, the latter has imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. Therefore, in terms of Rule 2(b), it should be excluded from the purview of domestic industry, and the petitioner should be treated as accounting for 100% of the production of the like article.

b. Even if M/s Godrej Industries Limited is not so excluded, the petitioner shall nevertheless account for a major proportion of the domestic production, to the extent of 65%, and therefore, shall be eligible as domestic industry, in accordance with the provisions of Rule 2(b) of the Rules.

C.2 Submissions by the exporters, importers and other interested parties

13. The interested parties submitted that the imports data for Godrej should be obtained by the Authority in order to analyse whether the quantity imported by Godrej justified its exclusion.

C.3 Examination by the Authority

14. The submissions made by the interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing of the petitioners to file the present petition and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows.

a. Rule 2(b) of the Rules provides that Authority may exclude such producers as are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof. The petitioner alleged that during the period of investigation, M/s Godrej Industries Limited has imported the subject goods from the subject countries, and therefore, in keeping with the aforesaid provisions, it is liable to be excluded from the scope of domestic industry. M/s Godrej Industries Limited have admitted themselves in a correspondence with the Authority that they are regular importer of C12-14 alcohols for use in the manufacture of surfactants and since the petitioner

accounts for 60 % of the total production , they have been excluded from the purview of Domestic Industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping rules

b. In any case, regarding the contention whether the exclusion of M/s Godrej Industries Limited is justified, the Authority notes that even if the producer is treated as eligible domestic industry, production of the petitioner would constitute 60% of the total domestic production. Thus, the issue regarding the eligibility of M/s Godrej Industries Limited would not have any bearing on the eligibility of the petitioner to maintain the petition.

c. As the petitioner accounts for a major proportion of the total domestic production, exceeding the benchmark of 25% as provided in Rule 5(3) of the Anti Dumping Rules, it satisfies the criteria of standing provided for under the Rule.

D. Confidentiality

D.1 Submissions by the domestic industry

15. With regard to the confidentiality, the domestic industry, submitted as follows:

a. The exporters and producers have abused the provisions as to confidentiality and failed to provide even the most basic information. For instance, the product specifications, product coding system, shareholding structure, details of related parties, channels of distribution and other such details have not been provided.

b. In most cases, even a non confidential summary of the information filed has not been provided. For instance, the exporters and producers have also withheld the names of sample documents filed, the indexed information relating to sales and cost of production and the details of price structures in the domestic and foreign market have not been provided.

c. Unless the information provided is business sensitive in nature, such that disclosure thereof would prejudice the interests of the responding party, disclosure of the relevant information must be insisted upon.

d. Rebutting the allegations of the interested parties regarding excessive confidentiality claimed by the domestic industry, it was submitted that the domestic industry has provided non confidential summary of the relevant information.

D.2 Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

16. The exporters and other interested parties submitted that the petitioner had claimed excessive confidentiality and failed to provide appropriate non-confidential summary with regard to the consumption factors used for construction of normal value, calculation of normal value, grade-wise dumping margin and injury margin, inventories, calculation of non-injurious price and costing formats. In particular, the petitioner had failed to give a non-confidential summary of the data contained in Formats B to E. It was further argued as under:

a. It was for the Authority, and not the domestic industry, to examine the claims of confidentiality made by the exporters.

b. In any case, the objections raised by the domestic industry are vague and incorrect.

D.3 Examination by the Authority

17. Submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business related information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

E. Miscellaneous Submissions**E.1 Submissions by the exporters, importers and other interested parties**

18. The following miscellaneous submissions were made by the exporters and the other interested parties:

- a. The Authority is required to examine the existence of dumping and injury for the period of investigation prior to initiation. Since the initiation was done on the basis of data for a different period of investigation, it is in violation of the Authority's obligations under Rule 5 of the Anti Dumping Rules and Article 3.1 of the Anti Dumping Agreement.
- b. The jurisprudence quoted by the petitioner justifying the initiation, namely, the Guatemala Case, was irrelevant, as in that case, the period of investigation for injury was extended whereas in the present case, the period of investigation was completely rejected for the reason that the data was too old and the petitioner was a 100% EOU.
- c. The period of investigation was changed as the petitioner was a 100% EOU earlier. During such period, the petitioner was not eligible to qualify as domestic industry.
- d. Under the provisions of the Act, the normal value cannot be determined on the basis of the cost of production of the domestic industry. Further, the petitioner has not substantiated the adjustments made for calculation of export price. Thus, the petitioner has not provided adequate evidence as to dumping of the subject goods, and has therefore, not met the requirements of Rule 5 of the Anti Dumping Rules.
- e. Since the imports from Saudi Arabia are less than 3% of the total imports of like article, the investigation against Saudi Arabia should be terminated in accordance with the Rule 14(d) of the Anti Dumping Rules.
- f. As per the anti dumping law, the subject countries are required to be determined at the time of initiation of investigation under Rule 5 of Anti Dumping Rules.
- g. The fact that the volume of imports from Saudi Arabia are less than 3% casts doubt on the credibility of the petition, and whether adequacy and accuracy test was carried out prior to initiation.
- h. It was not mentioned in the petition that an application for review had been filed before the Director General, Safeguards. When the Director General, Safeguards rejected the application for review after a proper examination, it was inapt for the Authority to accept the analogous claim of material injury.
- i. The petitioner filed for imposition of anti dumping duties just before the expiry of safeguard duty. The cause of action cannot change from un-competitiveness of petitioner to trade distortion by exporter.
- j. The domestic industry has not been able to meet the requirements of the downstream industries. Furthermore, the downstream industries would become uncompetitive as a result of the imposition of duty. If the duty is imposed for the protection of one local supplier, it would in turn affect hundreds of downstream value added suppliers.
- k. Imposition of duty would open imports of downstream derivatives, as was noticed during the period of levy of safeguard duty.
- l. Reduction in supply of fatty alcohols is likely to push prices higher in 2018.
- m. Owing to scarcity of raw materials, the petitioner's delivery time is significantly longer. Moreover, the ability of the petitioner as going concern is doubtful. The imposition of anti dumping duty would adversely affect the financial health of the downstream industry.
- n. The domestic industry has been unable to meet the requirements of the downstream users on account of poor financial health and high cost technology.
- o. The findings of the Director General, Safeguards with regard to public interest are not relevant to the present investigation.
- p. Duty should be recommended separately for each grade or product code and not on weighted average basis.

- q. It should be verified as to whether the petitioner has purchased raw material from its plant in Indonesia on arm's length basis.
- r. The cost of sales for domestic and export sales vary significantly, which may indicate a discrepancy in the data provided.
- s. There are inconsistencies in the data filed by the petitioner. For instance, while total depreciation and domestic depreciation remained the same, there was wide variation in the total interest and interest attributable to domestic operations.
- t. Another instance of inconsistency in the petition highlighted is that while the net fixed assets have increased by 62%, the depreciation has reduced by 81%.
- u. While the total interest has reduced over the injury period, the interest for domestic operations has increased, which may indicate a discrepancy in the data.
- v. With an increase in selling price by 41%, in response to an increase in cost by 36%, the loss per unit of the petitioner could not have increased by 5%.
- w. For the period of investigation, no adjustment has been made towards utility inefficiency. Nevertheless, the adjusted profit/loss for the period of investigation changed.
- x. The adjusted profits are higher than the actual profits; whereas the adjusted cash profits are lower than actual. The figures call for examination.
- y. The landed value claimed by the petitioner for Malaysia is lower than the assessable value, which is not possible.
- z. The import data given in the petition was not correct. The Authority should not accept the claims of the petitioner at face value without cross-checking its veracity.
- aa. Since the production process of the petitioner involves two stages, that is, in Indonesia and in India, the allocation of expenses should be carefully checked.
- bb. The figures relating to selling price, cost of sales, profitability and return on capital employed do not appear to be correct.

E.2 Submissions by the domestic industry

19. Responding to the various miscellaneous submissions made by the other interested parties, the domestic industry submitted as follows:

- a. The written submissions of parties that have failed to file a response to Questionnaire should not be taken into record.
- b. In the case of Mexico — Anti-Dumping Duties on Steel Pipes and Tubes from Guatemala, the Panel found that it was not unreasonable for investigating authorities to rely on data set terminating even eight months prior to initiation. Moreover, the Authority has, in a number of cases, changed the period of investigation at the time of initiation.
- c. Rule 2(b) does not bar a 100% EOU from being treated as domestic industry. Thus, the petitioner was eligible for filing the petition. This is also in line with the past practice of Authority.
- d. The petitioner has provided all data as was reasonably available to it at the time of filing petition, for estimating the normal value. As held by the Hon'ble CESTAT in the case of Tyre Manufacturer's Association Vs. Designated Authority [2011 (270) E.L.T. 727 (T)], evidence furnished in the petition regarding normal value based on the constructed cost cannot be faulted with and the initiation was not in violation of Rule 5.
- e. If after due investigation, including verification, and reconciliation of exports by the exporters / producers in Saudi Arabia with the data as per DGCIS, it is found that imports therefrom are less than 3%, the domestic industry has no objection to termination of investigation qua Saudi Arabia.

- f. The Anti Dumping Rules provide for termination of investigations qua a country post initiation, under Rule 14. Thus, the proposition that subject countries are required to be determined at the stage of initiation is erroneous. Moreover, termination of investigations qua a particular country post initiation has been done in several cases by the investigating authorities across the globe.
- g. The fact that an application for review was filed for safeguards duty had been highlighted in a letter filed by the petitioning domestic industry, dated 15th February, 2017.
- h. Responding to comments in this regard, it was submitted that there was no basis for alleging that while the Director General, Safeguards examined the data, the Designated Authority merely accepted the claims of the domestic industry.
- i. Merely because the domestic industry opted to approach the Director General, Safeguards in face of sudden surge in imports, it does not preclude it from approaching the Authority later for redressing the injury caused by dumping.
- j. There is no basis for the arguments that the levy of anti dumping duty would lead to an increase in import of downstream products. Moreover, merely on the basis that imports from downstream products may increase, the domestic industry cannot be made to suffer injury on account of dumping of subject goods.
- k. In response to the contention that the prices of the subject goods would increase in 2018, it was submitted that evidence on record indicated that there was global over supply of the subject goods. Further, protection to the domestic industry cannot be denied based on such conjectures.
- l. There is no merit in the allegation that the domestic industry has been unable to fulfill its orders in a timely manner. Had it been so, the sales of the domestic industry would not have increased. In any case, the purpose of anti dumping duty is only to remove unfair advantages gained by the exporters through dumping of goods.
- m. The fact that there is uncertainty regarding the ability of the domestic industry to continue as a going concern only underscores the need for imposition of anti dumping duty on an urgent basis.
- n. A transfer pricing report from BSR & Co. has been provided to the Authority, which clearly highlights that the transactions with the related entity have been carried out on arms' length basis.
- o. While dumping margin and injury margin are imposed on a grade-wise basis, anti dumping duty has to be imposed on a product, and not types of product separately.
- p. Since the grades sold in the home market and export markets vary, the weighted average cost of sales for domestic sales and export sales shows variation. This does not show any discrepancy in the data.
- q. In response to the allegations on inconsistency, it was acknowledged that the figures for depreciation for domestic operations had been linked erroneously, which has been corrected. The cash profits, post such correction, reflect that the domestic industry has been facing a cash crunch.
- r. Since the Companies Act, 2013 provided for a change in the method of depreciation, the amount of depreciation was higher in the financial year 2014-15. The subsequent reduction in the amount of depreciation is on account of such change, and not any discrepancy in the data.
- s. Despite reduction in interest cost, the interest cost attributable to domestic operations has increased, only on account of the fact that the allocation of interest between domestic and export sales was done in the ratio of turnover. If the ratio is held constant, the figures would in fact, reflect more significant deterioration in return on investment.
- t. As regards the adjusted figures, it was submitted that the analysis done by the exporters was based on indexed figures, and thus, was inaccurate.
- u. Responding to comments in this regard, it was submitted that since the assessable value was determined by adding 1% towards landing charges, and the landed price does not include such notional charges, the landed price determined is lower than the assessable value.

- v. As regards difference in import data, the variations highlighted are trivial, which could be on account of the petitioner treating certain transactions as abnormal. Moreover, there is no reason why the petitioner would suppress the import volumes.
- w. The data filed by the petitioner, including the basis of allocation of expenses has been duly verified by the Authority, and found to be complete and accurate.
- x. The export tax levied by the Government of Indonesia was specifically intended to make the Indonesian operations of the petitioner unviable.
- y. Vide letter dated 14th March, 2018, the Domestic Industry submitted as under:
 - i. Certain alcohols and acids that are produced in the process of manufacturing the subject product, such as capric acid and caprylic acid should be treated as joint products and not as by-products.
 - ii. Format B of the petition should not be applied in this case given the peculiar facts of the case i.e. non-injurious price should not be based on best utilisation of raw materials.
 - iii. In computing the non-injurious price, the Authority should consider the best utilisation of capacities keeping in mind that for part of the injury period, the Domestic Industry was operating under the EOU scheme.
 - iv. LC backed creditors should not be treated as part of trade payable.
 - v. With regard to certain expenses in the nature of bank charges, the same have been allowed in computing the NIP.

E.3 Examination by the Authority

20. The various miscellaneous submissions made by the domestic industry and other interested parties, to the extent considered relevant, have been addressed as under:

- a. The Authority notes that some of the parties making submissions have not filed a response to the questionnaire. Nevertheless, with a view to ensure that all relevant submissions pertaining to the case have been considered, the Authority has considered and addressed their submissions under the relevant portions herein.
- b. For the purposes of initiation, the Authority had prima facie satisfied itself regarding the alleged dumping of subject goods and consequent injury to the domestic industry. The change of period of investigation is not material for the purposes of prima facie satisfaction. However, the determinations regarding dumping and injury have been made based on the data furnished by the parties for the period of investigation. The Anti Dumping Rules or Anti Dumping Agreement do not necessitate that the period considering which the initiation is done should be the same as the period of investigation which is considered for determination of dumping margin and consequent injury during the course of the investigation.
- c. There is no substance in the contention that the period of investigation cannot be changed at the time of initiation of the investigation. In fact, the period of investigation has been changed by the Authority, in past cases, at the stage of initiation. The procedure followed by the Authority is therefore, in conformity with the consistent practice of the Authority in this regard.
- d. The normal value has been determined on the basis of the responses filed by the exporters, for the purpose of determination of dumping margin. However, for the purpose of initiation, the constructed normal value based on the best available information with regard to cost of production has been used, in the absence of any other reasonably available data, and as per practice adopted by the Authority in this regard. The Authority had duly satisfied itself of the adequacy and accuracy of the evidence prior to initiation of the investigation.
- e. As stated hereinabove, since the volume of imports from Saudi Arabia is less than 3% of the total imports of the like article, the Authority has chosen to exclude Saudi Arabia from the purview of subject countries for the purpose of this investigation in accordance with the provisions of Rule 14(d) of the Anti Dumping Rules
- f. As regards the argument of the interested parties that the subject countries have to be decided at the time of initiation, the Authority finds that while the investigations are initiated in respect of imports from certain subject

countries, Rule 14 requires Authority to terminate the investigation, in case the volume of imports from any subject country are found to be below de minimis pursuant to investigations. Thus, there is no illegality in the present investigation on account of initiation or termination of investigation qua Saudi Arabia.

g. As regards arguments relating to review of safeguard duty, the Authority notes that the issue concerns a different investigating authority. Safeguard duty and antidumping duty are imposed under different legal provisions and to address different situations. Safeguard duty is invoked in case of surge in imports causing serious injury, whereas anti dumping duty is levied to address unfair trade practice of dumping and consequent injury to the domestic industry. Thus, the mere fact that the Govt. had imposed safeguard duty and the application for review and extension of safeguard duty was rejected, in no way, impedes the domestic industry from applying for imposition of anti dumping duty.

h. The argument that imposition of anti dumping duty may lead to an increase in import of downstream goods lacks luster and, in any case, cannot be a ground for denying remedy to the domestic industry.

i. As regards the imposition of grade-wise duty, the Authority notes that the duty is required to be levied on “product under consideration”.

j. The Authority has taken note of the submissions regarding alleged discrepancies and inconsistencies in the data submitted by the domestic industry. The data for the purpose of injury analysis has been taken on record after due verification and careful scrutiny. The purchase price of the inputs purchased by the domestic industry from related parties has also been examined to ascertain whether the same reflects arms’ length prices. The import data has also been cross-checked having regard to the objections raised, and corrections were made, wherever necessary.

k. While imposition of export tax may have increased the cost of production of the domestic industry, it is not a relevant parameter in determining dumping margin. As far as injury determination is concerned, the Authority is required to consider the domestic industry in its actual conditions. The domestic industry in fact contended that the raw materials consumption price of the foreign producers should not be adopted because of imposition of export tax. The Authority has however considered data / information of both the domestic industry and foreign producers on the basis of the records maintained by these parties.

l. With regard to issues raised by domestic industry on NIP, the Authority notes that the Domestic Industry had not requested any change in the methodology of computing the non-injurious price for almost 11 months from initiation until now. This investigation is almost nearing the end and such a proposal cannot be entertained at this belated stage after oral hearing especially when NIP workings in detail have already been disclosed.

m. NIP workings are based on the certified formats as provided by the domestic industry and verified by the investigating team during the course of the investigation.

n. Authority cannot dispense with such requirement when the AD Rules and Annexure III mandate that information in the petition including all formats should be duly considered by the Authority in computing the non-injurious price.

o. The AD Rules, and specifically Annexure III, do not allow the Authority any discretion in disregarding one full year or any period from the injury period for the purpose of considering best utilisation of capacities, and as a result, for arriving at the normated cost of production. Further, Annexure III does not provide for any distinction between capacity utilisation of Domestic Industry for exports and for domestic sales. The capacity of the Domestic Industry should be taken as a whole and accordingly, the capacity utilisation should be worked out.

p. The Authority notes that the Domestic Industry itself recognises an amount pertaining to LC backed creditors as a current liability that is part of trade payable, the Authority cannot take a different view. Further, Authority has relied on the basis of actual audited books of accounts as certified by Statutory Auditor. LC charges, Forwarding Cover charges and Bill Discounting charges are considered as part of cost of production as per audited Profit and Loss Account of the company for the calculation of NIP. Therefore, the Domestic Industry’s proposal cannot be accepted.

q. With regard to certain expenses in the nature of bank charges, the same have been accepted by the Authority and allowed in NIP workings

F. Normal Value, Export Price and Dumping Margin**F.1 Submissions by the domestic industry**

21. Following submissions made by the domestic industry with regard to determination of normal value and export price:

- a. Despite the best efforts, information relating to domestic sales in the exporting countries could not be obtained. Therefore, the domestic industry constructed the normal value for the producers of the foreign country, in order to estimate the dumping margin.
- b. Considering the responses filed by the exporters, the normal value and export price may be determined based on such responses, provided that they are found to be complete and accurate pursuant to detailed investigation.
- c. The responses filed by the exporters and producers of the subject goods are grossly deficient, and deserve to be rejected. The exporters and producers have not only failed to provide a complete response to the Exporters Questionnaire, but also appear to have suppressed and misrepresented the relevant information. Unless a complete and accurate response to the Exporters Questionnaire is filed by a producer or exporter, the response filed should not be accepted.
- d. While most of the producers in the subject countries have claimed that they have not received any incentives from the governments of their respective countries, the governments of these countries have actually conferred several benefits on the export of such goods. Such misrepresentation by the exporters should be viewed severely and the responses filed should be rejected.
- e. The response of the exporters that disclosure of subsidies falls within the ambit of subsidy investigation is surprising. When the Exporters Questionnaire specifically calls for information relating to subsidies, it is not for the producer to decide that the information is not relevant for the present investigation.
- f. Each of the producer and exporter of the subject goods have multiple related entities engaged in the manufacture of upstream or downstream goods. The details of related parties of each of the producer / exporter, as available in the public domain, were submitted with the request that in case the producer / exporter has not identified the related entities, the response filed should be rejected on the ground of suppression of relevant details.
- g. In case any of the producer has received any raw material or other inputs or service, it should be ensured that the transaction was carried out at arm's length prices. Even in case where the feedstock for the subject goods was produced captively, it should be analyzed as to whether the raw material for such captively produced feedstock were purchased from a related entity, and whether the purchase was at arm's length prices.
- h. Similarly, in case the subject goods produced have been sold to related downstream users, such transactions should be treated as not being in the ordinary course of trade and should not be allowed to influence the determination of normal value and export price. Furthermore, it should be ascertained as to whether the affiliated buyer of the subject goods has, in turn, exported them to India.
- i. Apart from the above, detailed submissions were also made with regard to each producer and exporter, highlighting other aspects relevant for determination of normal value and export price.
- j. Regarding the responses filed by M/s FPG Oleochemicals Sdn Bhd ("FPG") and M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapore ("PGIO"), it was highlighted, inter alia, that PGIO has an agreement with M/s KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd (KLKOM), for fractionalization of the subject goods. It is necessary to scrutinize the records of KLKOM, to ensure that the goods produced by it are not being exported to India through PGIO, under the garb of conversion of fatty alcohols on behalf of the exporter.
- k. As regards the response filed by KLKOM, it was, inter alia, submitted that it should be ensured that the subject goods have not been exported through PGIO. Further, it should be ensured that the comparison between the domestic and export sales of the producer have been made at the same level of trade.
- l. With respect to the response filed by M/s Thai Fatty Alcohols ("TFA"), it was urged that since the details of related entity, M/s Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Malaysia, engaged in the production of the subject goods in one of the subject countries itself were not disclosed, the producer should be treated as non-cooperative on the

grounds of suppression of critical facts. In any case, M/s Emery should have also filed a response to the Exporters Questionnaire.

m. Similarly, M/s PT Wilmar Nabati, Indonesia (“WINA”) and M/s Wilmar Trading Pte Ltd. (“Wilmar Trading”) also deserved to be treated as non-cooperative for the reason that no response has been filed by the affiliated entity, M/s Natural Oleochemicals Sdn Bhd (NatOleo), which is also engaged in the production of the subject goods. Further, M/s Adani Wilmar Limited, a related entity of WINA and Wilmar Trading, has undertaken selling activities on behalf of the exporter. In such a case, in order to determine the export price, the selling, general and administrative expenses and profits of the entity in India were required to be reduced from export price, in keeping with the past practice of the Authority. However, Adani Wilmar has not participated in the investigation, and no details of selling, general and administrative expenses incurred by it have been provided.

n. Regarding the responses filed by M/s PT Musim Mas Holdings Pte Ltd. (“PTMM”) and M/s Inter-Continental Oils and Fats Pte Ltd. (“ICOF”), it was, inter alia, alleged that there were two entities in India namely, M/s South India Krishna Oil & Fats and M/s Tvarur Oils & Fats, which carry out marketing activities on behalf of the exporter. If these entities have carried out marketing activities in relation to the product under consideration, the expenses incurred and profits earned by it should be reduced from export price.

o. The primary raw material for the production of subject goods, that is, crude palm kernel oil, palm oil and its derivatives, are subject to export duty, when exported from Indonesia and Malaysia. As a result, there was a situation of over-supply of the raw materials in the domestic market, and their price were suppressed. Since the price of the raw materials was distorted, there was a particular market situation in the subject countries and the cost associated with the production and sale of the goods was not adequately captured. Therefore, the cost of the raw material as per records should not be relied upon, and an appropriate adjustment should be made to determine the reasonable cost of production of the subject goods.

p. To determine the ex-factory export price, the selling, general and administrative expenses and profits of affiliated trader are required to be reduced. Thus, if all the traders forming part of the distribution channel have not responded, a separate dumping margin cannot be determined.

q. Furthermore, some exporters have related entities carrying out marketing activities on their behalf or engaged in providing services such as storage, shipment and logistics activities. The expenses and profits of any such entity carrying out marketing activities should be deducted, and the adjustment for any logistics or storage services received should be made on arms’ length basis.

r. Responding to the arguments of the interested parties that the normal value in the petition cannot be based on the cost of production of the domestic industry, it was submitted that the normal value was estimated on the basis of the data available to the domestic industry.

s. The normal value may be determined on the basis of the responses filed by the producers / exporters, subject to the condition that the response is complete in all respects, and on verification is found to be accurate and reliable. Additionally, the verification reports, communications with the exporters and their replies and the actual dumping margin may be disclosed.

t. Responding to arguments in this regard, it was submitted that the adjustments to export price claimed by the petitioner are based on the best estimates. Moreover, the exporters have not claimed that such adjustments are excessive.

u. None of the exporters have claimed that they have not dumped the subject goods into India.

v. Responding to a request in this regard, it was submitted that dumping margin can be determined on a monthly basis only if the exporters are willing to produce all relevant records relating to production, sales, inventories of raw materials, inventories of finished goods, cost of production of each grade and financial statements for company and division on a monthly basis. Unless such information is provided, the dumping margin cannot be calculated on a monthly basis.

F.2 Submissions by the exporters, importers and other interested parties

22. The submissions made by the exporters, importers and other interested parties are summarized below:

- a. The petitioner has calculated normal value on the basis of its own cost, and the normal value calculated for each country is the same. As a result, the dumping margin estimates are skewed, and give no indication as to whether the goods are being dumped in India. The Authority should determine the dumping margin based on the questionnaire response filed.
- b. The dumping margin assessment should be done on a monthly basis, as there have been high fluctuations in the prices of raw material. If such an analysis is not carried out, it would prejudice the exporters that have made more exports during the beginning of the period of investigation.
- c. The major raw materials are abundantly available in Indonesia and Malaysia, due to which the cost of production of the exporters in these countries is lower. The comparative cost advantage received by these exporters cannot be categorized as dumping.
- d. The petitioner has not provided any evidence with regard to the adjustments to the export price.
- e. Responding to allegations by the petitioner, it was submitted that disclosure of subsidies by the governments of the subject countries falls within the ambit of subsidy investigation.
- f. In any case, only the subsidies actually received by the producer have to be reported in response to the questionnaire.
- g. The petitioner's allegation that TFA has not disclosed all related entities is baseless. Further, if the petitioner wishes that all related parties provide information and clarity with regard to participation in the production of product under consideration, it should also provide the same clarity with regard to its own interested parties.
- h. Regarding the contention that the price of raw material was affected by the levy of export tax, it was submitted that such a levy was fully compliant with the WTO obligations, and merely ensured adequate supply of raw materials to the domestic producers. The existence of import duties do not qualify as a particular market situation.
- i. The Government of Indonesia has not made any financial contribution that benefits the producers of the subject goods in the exporting country.
- j. The Appellate Body has, in the case of EU – Biodiesel found that rejection of actual cost of procurement of raw material, for the reason that they were subject to export tax, was inconsistent with the provisions of the Anti-Dumping Agreement.
- k. Further, the petitioner has not provided any evidence to substantiate its claim that the price of palm kernel oil would have been higher in the absence of the export tax.
- l. In any case, the argument raised by the domestic industry would not have any application in case of producers located in Thailand.
- m. The Authority is required to adhere to provisions of Annexure II in determining the normal value, provided the raw material transactions are at arms' length.
- n. The petitioner's reliance on the findings of the investigating authorities in the US is misplaced, inasmuch as the legal framework and factual background of the cases are different. Moreover, the practices of other investigating authorities do not constitute legal jurisprudence.
- o. There is no legal requirement for each related entity dealing with the subject goods to file response to the Exporters Questionnaire, regardless of their trade with India. The value chain is only incomplete if the entities involved in the production or export of goods to India have not filed a response. In any case, entities that have not exported to India would not be able to file an effective response, as they cannot provide any relevant information for determination of normal value or export price.
- p. The domestic industry has to identify how the information missing is "necessary information". In any case, if the Authority finds the response to be incomplete, it can issue a deficiency letter.
- q. Regarding the submission that NatOleo may use the individual duty allowed to WINA, it was submitted that if any goods produced in Malaysia are exported through Indonesia, the same would reflect in trade documents available to Customs authorities. Thus, there can be no circumvention of duties.

r. In response to the submissions with regard to Adani Wilmar's participation in the investigations, WINA and Wilmar Trading contended that the response filed provides that Wilmar Trading pays Adani Wilmar a commission for procurement of orders. This commission has already been deducted from export price.

s. Responding to the allegation that all related entities may not have been disclosed, WINA and Wilmar Trading argued that there was no questionnaire format for such information. Further, the names of such entities would be irrelevant to the anti dumping investigation.

t. While the respondents had no objection to deduction of selling, general and administrative expenses, the profits of the exporter cannot be deducted in cases where the producer and exporter are related. This is for the reason that related producer and exporter are treated as one entity.

u. PTEO has maintained a straightforward channel of distribution through EOS and directly to independent customers in India. Further, it has submitted details of all related parties. PTEO is based only in Indonesia, and is not multinational. Thus, the allegations by the domestic industry are baseless.

F.3 Examination by the Authority

23. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following producer and exporters have filed questionnaire responses in prescribed formats:

- a. M/s PT Ecogreen Oleochemicals, Indonesia (Producer) and M/s Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd., Singapore (Exporter)
- b. M/s PT Musim Mas, Indonesia (Producer) and M/s Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore (Exporter)
- c. M/s PT Wilmar Nabati Indonesia (Producer) and M/s Wilmar Trading Pte Ltd., Singapore (Exporter)
- d. M/s FPG Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia (Producer) and M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapore (Exporter)
- e. M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd, Malaysia
- f. M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd., Thailand

24. Since the above mentioned producers / exporters have filed the questionnaire response, the Authority proposes to determine individual dumping margin in respect of these companies. The general methodology adopted by the Authority for determination of normal value for these exporters is to first examine whether the domestic sales of the subject goods by the responding exporters in their home markets were representative and viable for permitting determination of normal value on the basis of domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the respondents. In other cases, the costs of production including selling, general and administrative expenses claimed by the respective exporters is accepted after due verification and after adding 5% towards profit to arrive at the normal value.

25. With regard to the issue of fractionalization agreement between Procter & Gamble International Operations SA (PGIO) and KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd, Malaysia ('KLKOM') for the subject goods, authority notes that KLKOM converts fatty alcohols in liquid form provided to it by PGIO into solid form. The authority has carefully scrutinized the responses of all the companies & notes that the producer of these goods is FPG and this conversion activity from liquid to solid has very insignificant value.

26. With regard to the non-filing of response by Natural Oleochemicals Sdn Bhd (NatOleo) and selling expenses of Adani Wilmar Limited, the Authority notes that Natoleo is not involved in production of subject goods and only involved in blending, flaking and packing of subject goods in Malaysia. Further, Natoleo has not exported the subject goods to India during the period of investigation. Therefore, NatOleo is not required to file the response. Also, Adani Wilmar is only acting as a commission agent to WTRD. Adani Wilmar is not importing the subject goods on its own for reselling the same in India. The commission paid to Adani Wilmar has already been deducted from the export price. Therefore, there is no need for adjustment of SGA expenses of Adani Wilmar for the computation of the ex-factory export price for WINA/ WTRD.

27. In the case of non-cooperating exporters from the subject countries, the Authority proposes to determine the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of Anti Dumping Rules.

28. The Authority proposes to determine the normal value, export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject goods as follows:

F.4.1 Dumping margin in case of Indonesia

I. M/s PT Ecogreen Oleochemicals (Producer)

Normal value of M/s PT Ecogreen Oleochemicals (Producer)

29. From the response filed by M/s PT Ecogreen Oleochemicals (“Ecogreen”), the Authority notes that Ecogreen has made **** MT domestic sales during the period of investigation. About 97% of these sales were to unrelated parties. Sales in domestic market were sufficient in volume when compared with exports to India. To determine Normal Value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic transactions with reference to the cost of production of subject goods. In this case, grade wise profit making domestic sales are less than 80% and accordingly, only profit-making transactions have been considered for determining the normal value.

30. Ecogreen has claimed adjustments on account of packing costs, inland freight, ocean freight, insurance, surveyor fee, handling charges, other charges and throughput charges. The same has been allowed by the authority. Accordingly, the normal value for Ecogreen has been determined at ex-factory level at US\$ **** per MT.

Export price of M/s PT Ecogreen Oleochemicals (Producer) and M/s Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd., Singapore (Exporter)

31. M/s PT Ecogreen Oleochemicals (“Ecogreen”) has filed questionnaire response along with its related trading company, namely, M/s. **Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd.** (“Eco Singapore”). During the POI, Ecogreen has exported **** MT of the subject goods to India only through Eco Singapore. Ecogreen has sold the subject goods to Eco Singapore on ex-factory terms. Eco Singapore has claimed adjustment on account of commission, rebate, inland freight, insurance, ocean freight and other charges. The same have been allowed by the Authority, after due verification. The authority also examined the profitability of Eco Singapore for these export transactions.

32. Accordingly, the weighted average export price has been determined for Ecogreen exported through Eco Singapore as **** US\$/MT.

II. M/s PT Musim Mas. (Producer)

Normal value of M/s PT Musim Mas. (Producer)

33. From the response filed by M/s PT Musim Mas (“MMH”), the Authority notes that MMH made **** MT domestic sales during the period of investigation. All sales were to unrelated parties. Sales in domestic market were sufficient in volume when compared with exports to India. To determine Normal Value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic transactions with reference to the cost of production of subject goods. In this case there was only one domestic transaction which was sold at a loss therefore normal value has been constructed based on Cost of production of the subject goods plus 5% profit for the company.

34. Accordingly, the normal value for MMH has been determined at ex-factory level at US\$ **** MT.

Export price of M/s PT Musim Mas (Producer) and M/s Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore (Exporter)

35. MMH filed questionnaire response along with its related trading company, namely, M/s. Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore (“ICOF”). During the POI, MMH has exported **** MT of the subject goods to India only through ICOF. ICOF has claimed adjustment on account of overseas transportation, overseas insurance, credit cost, bank

charges, switch BL fees, administrative cost, sales and marketing support services. The same have been allowed by the Authority, after due verification. The Authority also examined the profitability of Eco Singapore for these export transactions.

36. Accordingly, the weighted average export price has been determined for MMH exported through ICOF as **** US\$/MT.

III. M/s PT Wilmar Nabati Indonesia (Producer)

Normal value of M/s PT Wilmar Nabati Indonesia (Producer)

37. It was noted by the authority that WINA sold **** MT of the subject goods in the domestic market during the POI. All sales in the domestic market were made to non-affiliated parties during the POI. Sales in domestic market were sufficient in volume when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. It was noted by the authority that profit making transactions were less than 80%, therefore authority has considered only profit-making transactions in the domestic market for the determination of the normal value.

38. WINA claimed adjustments on account of inland freight and credit expenses from the domestic selling price. The authority has allowed the adjustments after due verification. Accordingly, weighted average normal value for WINA has been determined as **** US\$/MT

Export price of M/s PT Wilmar Nabati Indonesia (Producer) and M/s Wilmar Trading Pte Ltd., Singapore (Exporter)

39. M/s WINA has filed questionnaire response along with its related trading company, namely, M/s. Wilmar Trading Pte Ltd (“WTRD”), Singapore. During the POI, WINA has exported **** MT of the subject goods to India only through WTRD. WINA has sold the subject goods to WTRD on FOB terms. WINA has claimed adjustments on account of inland freight, port handling expenses, flexi-bag expenses. The same have been allowed, after due verification. The authority has also examined the response filed by WTRD and ensured that imports made through WTRD were profitable and that all appropriate adjustments have been considered.

40. Accordingly, the weighted average export price has been determined for exports of WINA exported through WTRD as **** US\$/MT

IV. All other Producers/Exporters from Indonesia

41. In respect of all other exporters from Indonesia, who are treated as non-cooperative, the Authority determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value and export price so determined comes to US\$ **** /MT and US\$ **** /MT respectively.

F.4.2 Dumping margin in case of Malaysia

I. M/s FPG Oleochemicals Sdh Bhd (Producer)

Normal value of M/s FPG Oleochemicals Sdh Bhd (Producer)

42. It was noted by the authority that FPG sold **** MT of the subject goods in the domestic market during the POI through its related company, Procter & Gamble International Operations SA (Singapore Branch) (“PGIO”). Sales in domestic market were sufficient in volume when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions to unrelated customers by PGIO with reference to cost of production of subject goods as determined for FPG and SGA of PGIO. It was noted by the authority that profit making transactions are less than 80%, therefore authority has considered only profit-making transactions in the domestic market for the determination of the normal value. In some grades all the sales were loss making; therefore, the Authority constructed the normal value for those grades taking cost of production, SGA of PGIO and 5 % profit.

43. Adjustments on account of inland freight and credit expenses were claimed by the company from the domestic selling price. The authority has allowed the adjustments after due verification. Accordingly, weighted average normal value for FPG has been determined as ***** US\$/MT.

Export price of M/s FPG Oleochemicals Sdh Bhd (Producer) and M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapore (Exporter)

44. M/s FPG has filed questionnaire response along with its related trading company, PGIO, Singapore. During the POI, FPG has exported ***** MT of the subject goods to India only through PGIO. FPG has sold the subject goods to PGIO on FCA terms. PGIO has claimed adjustments on account of ocean freight, port handling expenses, and credit cost, bank charges and SGA expenses of PGIO. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for FPG exported through PGIO as ***** US\$/MT.

II. M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd (Producer and Exporter)

Normal value of M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd

45. It was noted by the authority that KKKOM has sold ***** MT of the subject goods in the domestic market during the POI. All sales in the domestic market were made to non-affiliated parties during the POI. Sales in domestic market were sufficient in volume when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. It was noted by the authority that profit making transactions are less than 80%, therefore authority has considered only profit-making transactions in the domestic market for the determination of the normal value.

46. KKKOM claimed adjustments on account of inland freight and credit expenses from the domestic selling price. The authority has allowed the adjustments after due verification. Accordingly, weighted average normal value for KKKOM has been determined as ***** US\$/MT.

Export price of M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd

47. During the POI, KKKOM has exported ***** MT of the subject goods to India directly to unrelated customers. KKKOM has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, port handling expenses, agent commission, credit cost and bank charges. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for KKKOM as ***** US\$/MT.

III. All other Producers/Exporters from Malaysia

48. In respect of all other exporters from Malaysia, who are treated as non-cooperative, the Authority determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value and export price so determined comes to US\$ ***** /MT and US\$ ***** /MT respectively.

F.4.3 Dumping margin in case of Thailand

I. M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd. (Producer and Exporter)

Normal value of M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.

49. It was noted by the authority that TFA has sold ***** MT of the subject goods in the domestic market during the POI. All sales in the domestic market were made to non-affiliated parties during the POI. Sales in domestic market were sufficient in volume when compared with exports to India. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. It was noted by the authority that profit making transactions are less than 80%, therefore authority has considered only profit-making transactions in the domestic market for the determination of the normal value.

50. TFA claimed adjustments on account of inland freight, insurance, storage, bank charges and credit expenses from the domestic selling price. The authority has allowed the adjustments after due verification. Accordingly, weighted average normal value for TFA has been determined as ***** US\$/MT.

Export price of M/s. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.

51. During the POI, TFA has exported ***** MT of the subject goods to India directly to unrelated customers. TFA has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance, storage, agent commission, and credit cost and bank charges. The same have been allowed, after due verification. Accordingly, the weighted average export price has been determined for TFA as ***** US\$/MT.

II. All other Producers/Exporters from Thailand

52. In respect of all other exporters from Thailand, who are treated as non-cooperative, the Authority determined normal value and export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value and export price so determined comes to US\$ ***** /MT and US\$ ***** /MT respectively.

F.4.5 Determination of Dumping Margin

53. On the basis of the normal value and export price determined as above, the dumping margin has been calculated as under:

Dumping Margin Table

<u>S.No.</u>	<u>Country</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Normal Value</u>	<u>Net Export Price</u>	<u>Dumping Margin</u>	<u>Dumping Margin %</u>	<u>Range</u>
1.	Indonesia	M/s. PT Ecogreen Oleochemicals	M/s. Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd.	*****	*****	*****	*****	0-10
2.	Indonesia	M/s. PT Musim Mas	M/s Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore	*****	*****	*****	*****	0-10
3.	Indonesia	M/s. PT Wilmar Nabati	M/s. Wilmar Trading Pte Ltd., Singapore	*****	*****	*****	*****	10-20
4.	Indonesia	Non-Cooperative	Non-Cooperative	*****	*****	*****	*****	10-20
5.	Malaysia	M/s. FPG Oleochemicals Sdh Bhd	M/s. Procter & Gamble International Operations SA, Singapore	*****	*****	*****	*****	0-10
6.	Malaysia	M/s. KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	M/s. KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	*****	*****	*****	*****	10-20
7.	Malaysia	Non - Cooperative	Non-Cooperative	*****	*****	*****	*****	15-25
8.	Thailand	M/s. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	M/s. Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	*****	*****	*****	*****	0-10
9.	Thailand	Non-Cooperative	Non - Cooperative	*****	*****	*****	*****	5-15

G. Determination of Injury and Causal Link

54. The Authority notes that the application for imposition of anti dumping duty has been filed by M/s. VVF (India) Limited, a domestic producer of the like article in India. The petitioner commands a major proportion of total production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the petitioner has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination, the cost and injury information of the petitioner, which constitutes the domestic industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

G.1 Submissions by the domestic industry

55. The following submissions with regard to injury and causal link have been made by the domestic industry:

- a. The domestic industry has suffered material injury due to the severe dumping of the subject goods by the exporters in subject countries. The injurious effect of the dumped imports may be analyzed on a cumulative basis for the subject countries, in view of Para (iii) of Annexure II of the Rules, as the conditions laid down in same are being met in the present investigation.
- b. The imports have reduced post August, 2014 only in response to the imposition of safeguard duty. However, if the data post expiry of safeguard duty is analyzed, it would show that the imports have increased both in absolute terms, and in relation to production and consumption in India.
- c. A reduction in share of subject imports in total imports from 99.45% in 2013-14 to 98.20% in the period of investigation is marginal and has little relevance in the injury analysis in a situation where:
 - i. A comparison was being drawn between a period of serious injury and material injury;
 - ii. Imports were capturing 44% of the demand;
 - iii. The domestic industry had idle capacities.
- d. In any case, the comparison with reference to figures in 2014-15 is distorted, as the period was affected by surge in the imports. If the historical data is analyzed, it would reveal that that the imports were at much lower levels in 2010-11.
- e. The analysis of the figures for the post period of investigation is relevant as the data for the injury period was distorted by surge in imports, and consequent imposition of safeguard duty.
- f. The domestic industry has been under constant strain to reduce its prices. Over the entire injury period, the domestic industry has been forced to sell much below its cost of production. Thus, the imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- g. Even though the domestic industry reduced its prices, the price undercutting continues to be positive. Moreover, price underselling is also significant.
- h. Upto July 11, 2016, the domestic industry was operating under EOU scheme, due to which it was required to export a significant share of its production. Thus, the effective capacity available for domestic sales has increased in the period of investigation.
- i. Although the domestic industry has the capacity to cover the entire demand in the market, its capacity is underutilized. The domestic industry has been able to gain only 35-45% of the market share. Post expiry of safeguard duty, the share of the domestic industry has reduced to 15-25%.
- j. While sales increased to an extent in the period of investigation, post this period, there has been a steep fall in the sales of the domestic industry.
- k. Although the domestic industry attempted to increase its sales, the efforts were somewhat impeded by the imports, resulting in higher inventories.
- l. Despite reducing costs, the domestic industry has not been able to break even, and the losses have in fact intensified over the injury period.
- m. The return on capital employed has remained negative over the injury period, and the situation has deteriorated in the period of investigation. Further, the cash losses have aggravated over the injury period.

- n. The profit before interest being negative, the domestic industry is unable to earn enough to meet its existing debt obligations. Clearly, the ability of the domestic industry to raise capital investments is impaired.
- o. While the sales of the domestic industry have shown a growth post imposition of safeguard duty and its exit from EOU, the growth in terms of other parameters of profit / loss, cash profits and return on investment is negative, and has deteriorated over the injury period.
- p. The industry in the subject countries has clearly shown an intent to gradually drain out the Indian industry and to ultimately force it out of competition.
- q. Not only are the imports causing injury to the domestic industry, but are also threatening to cause aggravated injury.
 - i. The imports have increased by 50% (on an annualized basis) in the post period of investigation.
 - ii. There is an over-supply of natural fatty alcohols in the global market, due to which the capacities of the producers in the subject countries are under-utilized. By contrast, the Indian market still has huge growth potential.
 - iii. The imports are entering at prices which would have significant suppressing effect on the prices of the domestic industry.
 - iv. As a result of over-supply of subject goods, the producers in the subject countries are unable to effectively market their products, resulting in accumulation of inventories.
 - v. India is a price attractive market, inasmuch as the prices prevailing in India are higher than that prevailing in other countries.
- r. The injury to the domestic industry should be seen in light of the fact that during the earlier part of the injury period, the domestic industry was suffering serious injury on account of the surge in imports. Relying on a finding of the investigating authorities in the European Union, it was submitted that the industry was still recovering from the injury so suffered, and in the absence of dumping, would have been able to generate much more substantial improvement.
- s. In any case, while the imports account for 44% of the market, the share of the other domestic producers is merely 16%. Clearly, the imports have been the major driving force in the market.
- t. The slight improvement in some of the injury parameters, consequent to the imposition of duty, was natural.
- u. Injury to the domestic industry was not caused by any factor other than dumping:
 - i. Over the injury period, the demand has reduced by merely 4%, thus there is no contraction in demand. Further, the demand for the subject goods has huge growth potential as the market for downstream products is a growing one.
 - ii. The volume of imports from other countries is insignificant.
 - iii. There are no conditions of competition, trade restrictive prices, developments in technology or changes in the pattern of consumption, which could have caused injury to the domestic industry.
 - iv. The data for other products, and for export sales has been segregated. Thus, the analysis is based only on the domestic sales of the subject goods.
- v. The losses per unit (adjusted) of the domestic industry have increased over the injury period. This demonstrates the causal link between dumping and injury.
- w. The law does not require dumping to be the sole cause of injury, as it requires that there should be “a causal link” between dumping and injury and not “the” causal link.
- x. Responding to the arguments that the injury to the domestic industry was caused due to internal competition, it was submitted that when the domestic industry has itself been able to increase its sales, and has instead suffered injury on the price front, any reference to market share of other domestic producers is meaningless.

- y. As held by the Tribunal in the case of Nippon Zeon Co. Ltd. Vs. Designated Authority, injury to the domestic industry should not be considered in the context of ideal conditions but in the specific circumstances of the domestic industry.
- z. During the period of investigation, the domestic industry has sourced bulk of the raw material locally, and thus the arguments with regard to inverted duty structure and high cost of raw material are irrelevant.
- aa. While synthetic fatty alcohols have captured significant share of global market, the demand thereof in India is minimal. This is evident from the fact that 97% of the imports are coming in from the subject countries, where only natural fatty alcohols are produced.
- bb. The statements in the annual report have been taken out of context by the other interested parties. In fact, these statements support the claim of injury by the domestic industry, that there is global over-supply of the subject goods and the demand has shifted to synthetic fatty alcohols globally. However, statements in the annual report do not alter the conclusion that dumping of the goods has contributed to injury to the domestic industry.
- cc. The reason the domestic industry exited the EOU scheme was to focus its energies on the domestic market. Thus, the decline in export sales is only for this reason. However, owing to the dumping, the domestic industry was able to garner only a small market share, resulting in low capacity utilization.
- dd. Furthermore, it is absurd that after distorting the conditions of competition in India, the producers in the subject countries should blame the petitioner for exiting the EOU and focusing on the domestic markets.
- ee. For the period when the domestic industry was operating as an EOU, its capacity should be considered after excluding the production meant for exports.
- ff. There is no basis for the contention that price undercutting is not relevant for injury analysis or that it should be determined after including safeguard duty. The Authority has regularly calculated landed price as excluding safeguard duty.
- gg. There was no basis for the argument that the Director General, Safeguards had considered the injury of the domestic industry to be self-inflicted. The letter declining review in no way suggested that the review was not initiated due to absence of positive adjustment.
- hh. The petitioner had followed up on its adjustment plan and had set up a plant in Indonesia for splitting up of palm kernel oil, as the primary raw materials were subject to export tax. However, post the setting up of plant, the Government of Indonesia imposed an export tax on the intermediate as well. Evidently, the intent of the producers in the subject countries, working in tandem with their Government, has always been to force the Indian industry out of competition.
- ii. In response to the allegation that injury to the domestic industry was caused due to its plant in Indonesia not being backwards integrated, it was submitted that the domestic industry has been making the best efforts to sustain in a market, where there is unfair competition. It cannot be said that because the domestic industry does not have backwards integration, it should close down. In any case, the Indonesian entity is not the subject matter of the present investigation.
- jj. Similarly, the prices of raw material as available to other parties are not the subject matter of the present investigation.
- kk. The contention that the domestic industry suffered injury due to inefficiency is incorrect. In fact, the domestic industry has been able to improve its efficiency in utilization of raw material and utilities.
- ll. Although the landed price has increased over the injury period, it is only on account of increase in cost of production of the subject goods. However, the landed price continues to be much lower than the cost, preventing the domestic industry from charging remunerative prices.
- mm. Responding to comments in this regard, it was explained that the price undercutting has been determined on a weighted average basis, having regard to different PCNs. Thus, the price undercutting for Indonesia and Malaysia vary, despite the prices being comparable.
- nn. The determination of injury margin should not be based on the best utilization of raw materials over the three periods:

- i. Different types of raw materials are utilized for manufacturing raw materials of different carbon chain lengths.
- ii. Further, even for producing fatty alcohols of the same carbon chain lengths, alternative raw materials may be used.
- iii. Also, the consumption of the same raw material differs for different types of fatty alcohols.
- oo. Alternatively, the best utilization of raw material should be analyzed considering the totality of raw materials consumed and totality of production of various kinds of fatty alcohols.
- pp. Since the domestic industry was operating as an EOU upto July, 2016, it could only sell a part of its production domestically. The effective capacity available for domestic sales increased after the domestic industry left the EOU scheme. Thus, the capacity utilization should be determined after excluding the production meant for export and the capacity dedicated to exports as an EOU. This is consistent with the past practice of the Authority.
- qq. Since different types of fatty alcohols are produced at the same plant, consideration of best utilization of capacity is not appropriate. This is because the utilization is affected by factors such as the volume of each type of fatty alcohols produced and number of switchovers between types of fatty alcohols.
- rr. The year 2013-14 was an abnormal year, where there was a shortage of supply in the global market. The domestic industry took advantage of this shortage to export more, and was able to achieve record production. However, while a plant may over-perform on a significantly higher throughput for a temporary period of time, it cannot operate in such a manner continuously. If the plant is over-worked for a long period, it would be adversely impacted in the long term. Thus, the year 2013-14 should be considered as abnormal and should not be considered in determination of best utilization of capacities.
- ss. The cost for the period of investigation does not include any cost for period prior to the period of investigation.
- tt. A transfer pricing report from BSR & Co. has been provided to the Authority, which clearly highlights that the transactions with the related entity have been carried out on arms' length basis.

G.2 Submissions by the exporters, importers and other interested parties

56. The exporters and other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
- a. The volume of imports for Saudi Arabia is less than 1% of the total volume of imports of the subject goods, due to which the cumulative assessment of injury is not appropriate.
 - b. There is no injury suffered by the petitioner as a result of the alleged dumping of the subject goods.
 - c. There is no negative volume effect as a result of imports from the subject countries, as the imports from subject countries have declined steadily, not only in absolute terms, but also in relation to production and consumption in India.
 - d. The share of imports in total imports has reduced over the injury period.
 - e. If the investigations against Saudi Arabia are terminated, the imports therefrom are required to be excluded for determination of injury.
 - f. There is no reason for analyzing the data for the post period of investigation. The injury period and period of investigation are determined at the time of initiation and thereafter volume of imports analyzed, and not vice-versa. The domestic industry has not identified any previous findings where the Authority has considered the volume of imports post period of investigation to determine injury.
 - g. If the Authority has allowed domestic industry the opportunity to present information for post period of investigation, it should allow the exporters to as well, with regard to dumping.
 - h. The imports have not had any suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry, as the increase in selling price is greater than the increase in cost.

- i. Price undercutting is not relevant in a situation where there is no suppression or depression in prices. Even if it is considered relevant, the price undertaking should be determined taking into account the safeguard duty applicable.
- j. The sales realization experienced by the petitioner is higher than the sales realization of the market.
- k. The economic parameters of the domestic industry reflect a positive trend. The sales and market share of the domestic industry have increased, as also that of the other domestic producers. The decline in production and capacity utilization can be attributed only to decline in exports of the domestic industry.
- l. Regardless of the domestic industry moving out of EOU, it was primarily focused on the export market. Removing export in determining capacity would result in a situation wherein the Authority would not examine decline in export performance of the domestic industry.
- m. It cannot be contended that the domestic industry should have captured the entire domestic market immediately on conversion from EOU to DTA unit. In any case, such conversion does not mean that the domestic industry was barred from making export sales.
- n. Even though the domestic industry was afforded protection under safeguard measures, its profitability of the domestic industry declined. There is no correlation between the imports and losses to the petitioner.
- o. Although the safeguard duty was lowest during the period of investigation, the imports have not increased during this period. Therefore, termination of safeguard duty cannot become a ground for justifying imposition of anti-dumping duty.
- p. The Director General, Safeguards may have refused to conduct a review on account of absence of positive adjustment during the levy of duty. The Authority should consider the fact that another quasi-judicial authority has implicitly acknowledged the self-inflicted nature of the petitioner's injury.
- q. Despite imposition of safeguard duty for 2.5 years, the domestic industry has not been able to recover. The petitioner should be called upon to explain if the adjustment plan was implemented and why it did not prove sufficient to remedy the alleged injury.
- r. The injury to the petitioner has been caused on account of increase in sales of other domestic producers.
- s. Decrease in demand and downturn in the industry has led to injury to the domestic industry.
- t. The profitability of the domestic industry is affected due to the decline in exports, capacity utilization and productivity, which have impacted its performance.
- u. It is not clear as to what information provided in the petition has been segregated for domestic and export market. Further, the adjusted figures for production, capacity and capacity utilization on this account, have not been provided.
- v. The exporters are able to export the products at more competitive prices, due to the free availability of key raw material. On the other hand, the domestic producers are forced to rely on imports of such raw material, leading to higher production costs. Moreover, the raw material imported from Indonesia is subject to export tax, which makes it costlier.
- w. The petitioner industry has suffered injury due to inverted duty structure, non-availability of raw materials, increase in sale of substitutes, surplus capacity of oleochemicals and delay in disbursement of loans. The same has also been acknowledged in the annual report of the petitioner.
- x. The petitioner's plant in Indonesia is not backwards integrated, due to which it requires supply of palm kernel oil, the supply of which is constrained. Moreover, the plant suffers from disadvantages of low credit worthiness and high bank financing cost.
- y. The cost of raw material purchased by the petitioner should be compared with the cost of raw material purchased by consumers and supplied to the petitioner for processing.
- z. Raw material and efficiency impacted the domestic industry negatively, as evident from the petitioner's statement that it was able to reduce costs on account of efficient utilization of utilities.

- aa. Despite increase in landed price of the subject goods, the performance of the domestic industry did not show any improvement.
- bb. Although the difference in the landed price of goods imported from Malaysia and Indonesia is merely Rs. **** per kg, the price undercutting varies significantly.
- cc. If only the economic parameters for the period after the period of investigation are relevant, then the domestic industry should withdraw the present application and file a revised application proposing a new period of investigation.
- dd. Petition filed by the domestic industry did not include a claim for injury. The domestic industry cannot add additional ground of threat of injury after investigation. In any case, the data used for threat of injury is for post period of investigation, which is not relevant in an original investigation.
- ee. The injury analysis should be done excluding C8 and C10. Further, the analysis also be conducted separately for different PCNs.
- ff. There is no threat of material injury to the domestic industry:
 - i. The supply of the subject goods from Asian countries have reduced.
 - ii. The prices of the domestic industry have not been suppressed.
 - iii. The petitioner has provided no evidence to substantiate its claims that India is price attractive as compared to other markets. Moreover, if the price in Indian market is one of the highest, then the question of injury to the domestic industry does not arise.

G.3 Examination of the Authority

57. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed below under the relevant parameters. Further, the Authority notes as follows with regard to various misc. submissions made by the interested parties with regard to injury to the domestic industry:

- a. As pointed out by the interested parties, the injury analysis would have to be carried out after excluding the imports from C8 and C10 and blended C8 C10 from such analysis. The authority has therefore excluded those product types from injury analysis which have been excluded from the scope of the product under consideration.
- b. There is no force in the submission that injury analysis has to be carried out PCN-wise. The purpose of defining PCNs is to ensure fair comparison for normal value with export price; and landed price with non-injurious price. However, existence of dumping, injury and causal link between dumping and injury is required to be determined for the product under consideration as defined in the present investigation and not PCN wise.
- c. It has been consistent position of the authority that injury to the domestic industry has to be seen as it exists, and not on the basis of assumptions or ideal conditions.
- d. The fact that Director General, Safeguards refused to initiate review investigations cannot be read as absence of injury to the domestic industry. Safeguard duty and antidumping duty are meant for different situations and operate under different laws. Merely because the Director General, Safeguards did not initiate a review does not preclude the domestic industry from approaching the Authority for warranted protection in the form of anti-dumping duty.
- e. Regarding the submissions on outcome of adjustment plan, the Authority notes that the petitioner has indeed set up a plant in Indonesia for processing of raw material into intermediate, as the raw material was subject to levy of export tax. The petitioner has stated that post setting up of the plant, in July, 2015, the Government of Indonesia levied export tax and service tariffs on the export of the intermediate as well. Thus, while the domestic industry implemented the adjustment plan, it was not able to reap much benefits out of it.

I. Cumulative assessment

58. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the Anti Dumping Rules provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article.
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

59. The Authority notes that:

- a. The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
- b. Post termination of investigation insofar as it relates to Saudi Arabia as one of the subject countries, the volume of imports from each of the remaining subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
- c. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

In view of the above, the Authority considers it appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

60. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

II. Volume effect of the dumped imports on the domestic industry**a. Assessment of demand**

61. The imports of the product under consideration from various countries are as follows:

Country of Export	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Indonesia	MT	13,218	26,363	11,275	12,132
Malaysia	MT	28,230	31,498	24,865	20,096
Thailand	MT	14,115	10,440	7,395	8,361
Subject countries	MT	55,563	68,300	43,535	40,589
Other countries	MT	74	250	1,201	1,211
Total Imports	MT	55,638	68,550	44,736	41,800

62. On the basis of the above imports, the sales of the domestic industry, and that of other domestic producers, the demand or consumption in India has been determined as under:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Subject imports	MT	55,563	68,300	43,535	40,589
Other imports	MT	74	250	1,201	1,211
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Sales of other domestic producers	MT	***	***	***	***
Demand	MT	90,282	92,405	98,573	90,781

63. From the above tables, the Authority notes the following:

- The dumped imports have fallen in absolute terms in the POI as compared to any of the preceding years.
- The dumped imports has decreased in relation to consumption and production in India.
- The fall in imports is due to levy of safeguard duty and due to fall in demand.

Volume of imports

64. The imports from subject countries over the injury period can be seen from the table below. It is evident that the dumped imports from the subject countries have fallen. The Authority notes that the product has been subject to the levy of safeguard duty since 28th August, 2014 due to surge in imports of the subject goods. The imposition of safeguard duty seems to have arrested the surge in imports, leading to decline in imports over the injury period.

Country of Export	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Indonesia	MT	13,218	26,363	11,275	12,132
Malaysia	MT	28,230	31,498	24,865	20,096
Thailand	MT	14,115	10,440	7,395	8,361
Subject countries	MT	55,563	68,300	43,535	40,589

a. Imports in relation to consumption in India

65. With the imposition of safeguard duty, the share of imports from subject countries in consumption in India has reduced over the period. Further, the share of such imports continues to be significant, being over 40% in the period of investigation.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Demand	MT	90,282	92,405	98,573	90,781
Share of subject countries	%	62%	74%	44%	44%
Share of other countries	%	0.08%	0.27%	1.22%	1.33%
Share of domestic industry	%	***	***	***	***
Share of other domestic producers	%	***	***	***	***

b. Imports in relation to domestic production

66. The table below shows that the imports account for 40% of the domestic production, which is quite significant. However, the ratio has shown a declining trend, from the period 2014-15 to the period of investigation, for the reason

that the imports of the product under consideration had earlier shown a significant surge to such extent that the same led to imposition of safeguard duty.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Imports from subject countries	MT	55,563	68,300	43,535	40,589
Production of domestic producers	MT	1,43,232	1,09,837	94,797	94,949
Share in relation to production	%	39%	62%	46%	43%

III. Price effect of the dumped imports on the domestic industry

a. Price Undercutting

67. For the purpose of determining price undercutting, net sales realization has been calculated after deducting outward freight and taxes. The Authority takes cognizance of the fact that the landed price of imports should be determined after adding 1% handling charge and applicable basic customs duty including cess to the CIF value of subject imports. However, there is no justification for adding safeguard duty to determine the landed price for the purpose of determining price undercutting. The Authority has, in past cases, consistently taken the view that landed price shall be calculated excluding safeguard duty. Therefore, in the present case as well, the price undercutting has been determined considering landed price excluding safeguard duty.

68. On a PCN wise comparison of the landed price of subject imports with net sales realization of the domestic industry, it was found that such imports are undercutting the prices of the domestic industry. One of the reason for differences in undercutting and underselling could be due to difference in product mix of different exporters and the domestic industry.

Figures in Rs. / Kg

Particulars	Landed Price	Selling Price	Price Undercutting	Price Undercutting %	Range%
Indonesia	133.2	***	***	***	0-10
Malaysia	129.4	***	***	***	10-20
Thailand	142.9	***	***	***	0-10
Subject Countries	133.0	***	***	***	10-15

b. Price Underselling

69. For analysis of price underselling, the non-injurious price has been worked out in accordance with the provisions of Annexure III of the Anti Dumping Rules, and compared to the landed price of the subject imports PCN wise. The landed price has been determined excluding safeguards duty. The analysis shows that the price underselling for each of the subject countries is not only positive, but also significant.

Figures in Rs. / kg

Particulars	Landed Price	Non-Injurious Price	Price Underselling	Price Underselling %	Range
Indonesia	133.2	****	****	****	0-5
Malaysia	129.4	****	****	****	10-20
Thailand	142.9	****	****	****	0-10
Subject Countries	133.0	****	****	****	0-10

c. Price suppression/depression

70. The Authority examined whether the effect of the dumped imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increases which would have otherwise occurred. From an analysis of the overall cost of sales and selling price of the domestic industry, it is seen that the selling prices of the subject goods have been consistently below the costs. This itself is sufficient to demonstrate that the imports have suppressed the prices of the domestic industry.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Cost of Sales	Rs. / kg	****	****	****	****
Cost of Sales	Indexed	100	114	95	121
Selling Price	Rs. / kg	****	****	****	****
Selling Price	Indexed	100	108	98	135
Landed Value	Rs. / kg	96	99	87	133
Landed Value	Indexed	100	103	90	139

IV. Economic parameters relating to the domestic industry**a. Capacity, production and capacity utilization**

71. Capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period as shown in the table below:

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Capacity	MT	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
Production	MT	93,297	57,307	56,922	56,527
Capacity Utilization	%	78%	48%	47%	47%

72. The capacity utilization of the domestic industry has decreased over the injury period. The major reason for fall in such capacity utilisation is fall in exports of the domestic industry.

b. Sales volume

73. As can be seen from the data below, the sales of the domestic industry dipped during the year 2014-15. Thereafter, the domestic sales of the domestic industry have been consistently increasing.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	54	124	134
Export Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	68	37	33

c. Inventories

74. From the trends of average inventories with the domestic industry, it is visible that the inventories of the domestic industry have accumulated over the injury period.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Average Stock	MT	****	****	****	****
	Indexed	100	120	112	130

d. Profit / Loss

75. It is seen that the domestic industry has not been able to recover its costs over the entire injury period. Following the adjustment plan adopted in terms of the safeguard measures, the domestic industry made certain improvements, to

reduce the cost of production. This has resulted in reduction in losses suffered by the domestic industry during POI when compared with the previous years.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Profit/(Loss) per unit	Rs. /kg	****	****	****	****
	Indexed	(100)	(142)	(78)	(50)
Profit/(Loss) total	Rs. Lacs	****	****	****	****
	Indexed	(100)	(86)	(51)	(37)

e. Cash Flow

76. The Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table. It is observed that the situation of cash profits of the domestic industry has improved over the injury period .

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Cash Profits per unit	Rs. lacs	****	****	****	****
	Indexed	(100)	(119)	(68)	(48)

f. Return on Investment

77. As the domestic industry has continued to make losses, the return on investment thereof has remained negative over the injury period. However, there is substantial reduction in the losses suffered by the domestic industry during POI as compared to previous years.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Profit/(Loss) total	Rs. Lacs	****	****	****	****
Interest	Rs. Lacs	****	****	****	****
PBIT	Rs. Lacs	****	****	****	****
Capital Employed	Rs. Lacs	****	****	****	****
Return on Investment	%	****	****	****	****
Return on Investment	Indexed	(100)	(163)	(71)	(5)

g. Productivity

78. The Authority notes that productivity of the domestic industry, productivity per day as well as per employee declined as compared to base year.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Indexed	100	61	61	61
Productivity per employee	MT/Nos	****	****	****	****
	Indexed	100	56	58	58

h. Employment and Wages

79. It is seen from that the level of employment first increased upto 2014-15 and then declined thereafter. However, the wages have increased in the period of investigation.

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Employment	Nos	****	****	****	****
	Indexed	100	110	106	104
Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****
	Indexed	100	86	83	101

i. Magnitude of Dumping

80. The margin of dumping may be an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The dumping margin determined for each of the subject country, as above, is above de-minimis and significant.

j. Growth

81. It is observed that the domestic industry has recorded a some positive growth with imposition of safeguard duty as far as domestic sales are concerned. In case of profits, cash profits and ROI are concerned, they have recorded improvement over the injury period .

Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Sales Volume	Index	100	54	124	134
Profits	Index	(100)	(142)	(78)	(50)
Cash Profits	Index	(100)	(119)	(68)	(48)
Return on Investment	Index	(100)	(163)	(71)	(5)

k. Ability to raise capital investment

82. The profitability, cash flows are showing improvement indicating that the ability of the domestic industry to raise capital investment for the sector may not be impacted.

V. Observation on injury

83. On the basis of the above analysis, the following can be summarized:

- a. Due to the imposition of safeguard duty in August, 2014, the imports from the subject countries have shown a decline in absolute terms. As a result, the imports have also declined in relation to production or consumption in India.
- b. The imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price underselling is positive. Further, the imports have also had the effect of preventing price increases, which otherwise would have occurred. However, price undercutting with Safeguard duty is not significant.
- c. The profitability of the domestic industry has deteriorated upto 2014-15 thereafter it improved.
- d. In case of profits, cash profits and ROI are concerned, they have recorded improvement over the injury period.

- e. The dumping margin for all the exporters is positive.
- f. The domestic sales of the domestic industry has increased.
- g. The market share of the domestic industry has also increased.

VI. Injury Margin

84. The injury margin for the participating producer/exporters and non-cooperative parties is as under:

Injury Margin Table

<u>S.No</u>	<u>Country</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Landed Value (US\$/MT)</u>	<u>NIP</u>	<u>Injury Margin</u>	<u>Injury Margin %</u>	<u>Range</u>
1.	Indonesia	M/s PT Ecogreen Oleochemicals	M/s Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd.	****	****	****	****	0-(10)
2.	Indonesia	M/s PT Musim Mas	M/s Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore	****	****	****	****	0-10
3.	Indonesia	M/s PT Wilmar Nabati	M/s Wilmar Trading Pte Ltd., Singapore	****	****	****	****	0-10
4.	Indonesia	Any other	Any other	****	****	****	****	0-10
5.	Malaysia	M/s FPG Oleochemicals Sdh Bhd	M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapore	****	****	****	****	0-10
6.	Malaysia	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	****	****	****	****	0-(10)
7.	Malaysia	Any other	Any other	****	****	****	****	0-10
8.	Thailand	M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	****	****	****	****	0-(10)
9.	Thailand	Any other	Any other	****	****	****	****	0-10

H. Causal Link and Other Factors

85. Other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry are examined as under:-

- a. Volume and value of imports from countries other than the Subject Countries - Imports from countries other than the subject countries are not significant in volumes, being cumulatively less than 3% of the total imports. Indisputably, such imports could not have caused any injury to the domestic industry.
- b. Contraction of demand or changes in the pattern of consumption – The demand for the subject goods has contracted during the POI. However, the market has not demonstrated any change in the pattern of consumption as well.

- c. Development in Technology - None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.
- d. Trade restrictive practices and competition between supply from various sources - The subject goods are not subjected to any trade restrictive practices in India. Moreover, apart from the competition that is obvious in any market economy, no inter se competition or competition between supplies from various domestic and international sources exhibit any such impact that could be construed as injurious to the domestic industry.
- e. Export performance - Performance of the domestic industry has been segregated for domestic and export market, to the extent possible.

Observations on causal link:-

86. The observation on Causal Link is as under:
- a. Imports from the subject countries are being dumped in the Indian market.
 - b. There has been a decline in dumped imports in absolute terms and relative to production and consumption in India.
 - c. As a result of being forced to compete with dumped imports by offering loss making prices, the domestic industry has been unable to increase its prices so as to recover its full cost of sales. However, the profitability and ROCE of the domestic industry has improved during POI as compared to previous years.
 - d. There has been an increase in the domestic sales of the domestic industry.
 - e. There has been a significant fall in the export performance of the domestic industry.
 - f. There has been a fall in demand of the subject goods during the POI.
 - g. It was also observed that some of the imports made from subject countries are causing injury to the Domestic Industry.

Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry regarding determination of NIP

- 87. The Domestic Industry has stated that the Authority has not taken cognizance of the fact that the domestic industry was earlier an EOU and now a DTA. The fact has direct impact and consequences not only on standing but also on the injury and determination of non-injurious price.
- 88. The injury margin calculated for each of the exporters from the subject countries is either negative or below 5%. The NIP calculated is unduly low. The concerns for NIP have remained unaddressed.
- 89. Domestic Industry stated in the hearing that Grade wise cost of production calculated by the Petitioner/Domestic Industry should be consider for NIP calculation.
- 90. In the hearing it is also stated that regarding best utilisation of capacity, the domestic industry has stated that upto July 11, 2016, the domestic industry was operating under the EOU scheme. Under the provisions of the scheme, it was required to export a significant share of its production, and only a part of it could be sold in the domestic market. Therefore, the domestic industry has requested to use capacity utilisation of the current year only. Alternatively, it is proposed that the production for exports should be excluded for determination of capacity utilization for each year that the domestic industry operated as an EOU unit. The petitioner also requested to take equivalent production since different grades of PUC are produced by the petitioner.
- 91. In the hearing Domestic Industry further stated that LC backed creditors should not be treated as part of trade payable even though the same is recognised by the Domestic Industry as a current liability.

92. The domestic industry had treated fatty alcohols as the main product and all other acids, Glycerine and residue as by-product at the time of submission of Petition. Now, the Petitioner has pleaded at the final stages that the Authority should consider the said by-products as joint products.
93. With reference to consumption of raw materials, the domestic industry has submitted that the nature of the subject goods is such that different type of raw materials are used to manufacture fatty alcohols of different carbon lengths and since Product mix has changed over the year, different raw materials have been used by the domestic industry over the period. The domestic industry further stated that the consideration of normated cost or raw material would be highly inappropriate, having regard to the above facts.
94. Packing expenses treatment as fixed expenses: Domestic Industry has requested for clarification regarding whether the packing expenses are being treated as fixed expense or variable expenses.
95. The corporate expenses adopted in NIP fixation, as shown in the working sheet disclosed to the petitioner shows a lower amount. Domestic Industry has requested for clarification.
96. Treatment of interest bearing creditors, accrued income & duty drawback receivable: Petitioner has claimed that interest bearing creditors should not be considered in current liabilities and that accrued income and duty drawback receivable should have been considered as part of current assets.
97. That inadequate disclosure of essential facts viz. import data, landed price, actual dumping margin, documents and submissions filed by the exporters of subject countries and injury parameters and determination of working capital and non-injurious price.
98. Domestic Industry has also indicated the responses of the exporters are highly deficient and such deficiencies are not fully reflected in the disclosure statement. They requested re-examination of all such factors.
99. The domestic industry has also contended on the numbers analyzed in the disclosure statement. They also contended that the Designated Authority had, at the time of initiation, acknowledged the claim of the domestic industry that it may suffer intensified injury post expiry of duty; the same has not been examined in the Disclosure Statement.

Post Disclosure Statement submissions by the Exporters and other interested parties and Examination by the Authority.

100. That the Domestic Industry is not suffering injury. All the parameters are relating to injury are showing positive trend. They further submitted that any injury suffered by the Domestic Industry is on account of factors not relating to dumping.
101. Some of the interested parties also submitted that bad investment decision of the Domestic Industry and decline in export performance are the only reason for any injury suffered by them.. They further submitted that there is no causal link between the alleged injury and imports from subject countries.
102. That the calculation made by the Authority in relation to price underselling is incorrect, particularly when most of the cooperating exporters accounting for majority of the imports are having negative injury margin.
103. Some of the interested parties raised objections on the methodology of computation of the NIP and price underselling.
104. One of the exporter has made comments on the calculation relating to adjustments carried out in relation to SG&A expenses and made request for its reconsideration.
105. Some of the interested parties again reiterated their request of exclusion of certain pure cuts from the scope of the PUC.

106. Some of the interested parties has submitted that the Domestic Industry has not been able to reap any benefits out of the adjustment plan promised before the Director General of Safeguards in order to become competitive.
107. Some of the interested parties stated that due to the obsolete capacity constraints Domestic Industry is not able to maximize its financial condition. Further, other producers in the world enjoy economies of scale due to large capacities.

Examination of the Authority:

108. The Authority notes that most of the submissions by parties are of repetitive nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above deals with all such arguments of the interested parties including Domestic Industry. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.
109. The Domestic Industry has requested that computation of NIP should not be based on best utilisation because it was operating as an EOU upto July 11, 2016. In other words, petitioner requests for non-application of the NIP rules provided under the Annexure III of the Anti-dumping rules merely because Domestic Industry was operating as an EOU. It is submitted that computation of NIP was done on the basis of the data provided by the petitioner company and in accordance with the principles of computation of NIP provide in Annexure III of the Anti-dumping Rules. Annexure III of the Anti-dumping Rules codifies the procedure the determination of NIP. Authority cannot exercise discretion and act contrary to the prescribed rules merely because Domestic Industry claims that application of rules is inappropriate in the present case. In any case, the processes of the Petitioner company remain the same, whether it is an EOU or in the DTA. The petitioner's claim for equivalent production is not acceptable on the ground that the domestic industry has not furnished any documentary evidence in support of its claim of plant capacity being determined on the basis of grades or equivalent production. Therefore, there is no merit in the claims of the domestic industry.
110. In relation to the issue regarding grade-wise NIP, it is noted that the Domestic Industry had provided grade wise raw material consumption details in Format-A which shows year wise input output details of various grade as under:

a.

2016-17

Grade	V12:14	V12:16	V12:18	V16:18	V16:98	V18	Total
Input MT	****	****	****	****	****	****	****
Output MT	****	****	****	****	****	****	****
Ratio	****	****	****	****	****	****	****

2015-16

Grade	V12:14	V12:16	V12:18	V16:18	V16:98	V18	Total
Input MT	****	****	****	****	****	****	****
Output MT	****	****	****	****	****	****	****
Ratio	****	****	****	****	****	****	****

2014-15

[illegible]

2013-14

Grade	V12:14	V12:16	V12:18	V16:18	V16:98	V18	Total
Input MT	****	****	****	****	****	****	****
Output MT	****	****	****	****	****	****	****
Ratio	****	****	****	****	****	****	****

From the above table, it may be seen that during the year 2016-17 raw material consumption for Grade V16:98 is NIL for a production of ***MT, similarly for the production of ***MT of V18 raw consumption is *** MT only. Similarly in other years in some of the grade output is more than input. From the above table it is clear that some of the grades are produced with Zero raw material and some of the grades are over loaded.

b) The legal consultant of the domestic industry claimed after verification that Format A and B has been prepared after adjustment of by-product. However no supporting evidence substantiating the same was produced by the domestic industry in support of its claim.

c) Some of the raw materials are procured by the petitioner from its related unit M/s PT VVF Indonesia, VVF Singapore Pte Ltd. and VVF Limited. VVF Indonesia was established for the purpose of manufacturing and processing of chemicals (example crude palm kernel oil) into semi-finished / process materials i.e. split fatty acids and crude glycerine in liquid form and selling the same to Group entities, mainly to VVF India. The company clarified that these Goods are imported on a FOB basis and at a mutually agreed price which is determined on the basis of cost of production. As per the audit report of VVF Indonesia – “since the NCP (net profit divided by total operating cost) of VVF Indonesia 0.21%, is below the arithmetic mean of the NCP margin of the comparable companies, the international transaction of purchase of goods from VVF Indonesia is consistent with the arm’s length standard from Indian transfer pricing regulations perspective”. But the company failed to provide detailed reconciliation of Format A with purchases from related unit and purchases from unrelated unit. It was also not clear in which grade of fatty alcohol petitioner used the raw materials procured from related unit.

d) As per the certified CII (items wise cost) the petitioner allocated manufacturing expenses, salary & wages, depreciation etc. based on turnover. Since the per unit sales realization of different grades vary significantly, the production value (Production quantity of a particular grade X per unit sales realisation of that grade.) method was adopted by DGAD.

e) The Authority also notes that domestic industry has provided PCN wise data vide its letter dated 2 June, 2017 but during the course of investigation domestic industry failed to provide the justification of various allocation ratios used to determine PCN wise cost such as abnormal input – output ratio, by- product adjustment, utility and other expenses claimed as actual, PCN wise production from the raw material procured from the related party etc. . Subsequently, when domestic industry provided certified costing data, domestic industry completely changed its allocation methodology at the fag end of the investigation. Further, the certified costing data at total levels is not matching with the PCN wise cost of sales. Therefore, the Authority has determined PCN wise NIP as per the best possible method which is consistently followed by the Authority. Since similar method was also adopted to determine the cost of production of cooperating exporters, there is no merit in the claims of the domestic industry.

111. The Authority notes that the Domestic Industry itself recognises the amount pertaining to LC backed creditors as a current liability, included in trade payable. Further, Domestic Industry was also failed to provide any bifurcation of LC charges between exports sales of finished goods, domestic sales and imports of inputs for manufacturing goods. Since the Domestic Industry failed to provide any bifurcation, and the fact that Domestic Industry, itself treating LC charges under trade payables, the Authority cannot take a different view. Further, DGAD has relied on the basis of actual audited books of accounts as certified by Statutory Auditor. Therefore, the Authority cannot deviate from such audited records. The Authority also considered Sundry Debtors as per audited records only even though the Domestic Industry claimed bill discounting as expenses which is allowed by the Authority.

112. The company vide its letter/updated petition dated 2nd June 2017 submitted C-II (indicating head wise cost for the product under consideration) for the POI. However the basis for allocation of costs was subsequently modified while submitting the certified copy of C-II. This formed the basis of NIP computation. Verification of Domestic

Industry was also done on 17th and 18th August 2017 wherein the reasonability of the revised data was also verified. Thus, the Authority had computed NIP for the PUC based on certified C-II and Format A & Format B provided by the petitioner company regarding consumption of raw material in line with Annexure III of the AD Rules.

113. The Petitioner company, vide letter dated 14.03.2018, shortly before the issuance of the Disclosure Statement requested for revising the NIP by changing the composition of the petitioner's product portfolio and treating by-products as joint products. Such a claim has been raised well after verification and about 11 months into the present investigation. Consideration of such renewed data and basis would require, essentially, to conduct the entire investigation afresh and assess the Petitioner's costing from the beginning. Moreover, such consideration would require complete re-examination of data which would necessitate verification of all the revised figures besides re-working of detailed NIP. Since anti-dumping investigation are time bound proceedings, such re-examination may not be possible at such belated stage. Further, the practice of Domestic Industry to repeatedly change cost methodology may not be fair to other interested parties, who may like to have their comments also on the issues.
114. Moreover, the Domestic Industry has already admitted during the submission of petition and domestic verification that it has considered all other acids, glycerine and residue as 'by-product' and not joint product. Therefore, there is no basis for the Authority to deviate from this treatment of the Domestic Industry. In any case, consistency always forms the very basis of costing principles.
115. Domestic Industry has effectively claimed that the Authority should disregard the application of the provisions of Annexure III of the Anti-dumping Rules in the present case. It is submitted that computation of NIP was done on the basis of the data provided by the petitioner company and in accordance with the principles of computation of NIP provide in Annexure III of the Anti-dumping Rules. Annexure III of the Anti-dumping Rules codifies the procedure the determination of NIP. It provides for consideration of best utilization of raw materials over the past three years period and the POI. The Authority cannot exercise discretion and act contrary to the prescribed rules.
116. With respect to packing expense, it is clarified that it has now been considered as variable expense. Accordingly, NIP has been appropriately re-determined to that extent.
117. Corporate expenses incurred towards corporate share services have been apportioned to all the activities of the company as per standard practice of the Authority.
118. Based on the claim made by the petitioner *vide* letter dated 3rd April, 2018 interest accrued on borrowing has been disallowed from the current liability. Accordingly, interest receivable on bank deposit has also been reduced from current assets. Regarding other accrued income, the Authority has allowed the claim of the petition company and included the same in the current assets. Regarding duty drawback receivable, since it is related to exports sales, it has not been considered as part of current assets for domestic sales.
119. In relation to the submissions regarding exporters confidential data cannot be disclosed to the Petitioners or any interested party other than that particular exporter/interested party as per Rule 7 of Anti-Dumping Rules. Non confidential part has already been shared.
120. With regard to submission of Domestic Industry that FPG Oleochemicals/WINA has purchased raw materials from a related party and therefore the cost of production should be carefully examined, Authority has already examined the arm's length prices from related parties of FPG/WINA and found that inputs have been purchased at arm's length prices based on the evidence provided by the producers/exporters. In fact, domestic industry has also procured the raw materials from its related party at arm's length and Authority has accepted such transfer prices from its related party based on reports submitted by the domestic industry.
121. With regard to transactions between KLK and PGIO the Authority has also examined these transactions and notes that there is no significant value addition in the fractionalization process.

122. With regard to issue of filing of response by related entities the Authority notes that domestic industry has not provided any reason to substantiate its claim regarding incompleteness of value chain. Value chain for exports to India can be incomplete only if entities involved in the production or export of subject goods in subject countries to India have not filed questionnaire response.
123. With regard to the submission that there are a lot of subsidies given by Government of Malaysia./Thailand/Indonesia, the Authority notes that domestic industry has not given any evidence about any incentive or subsidy availed by the participating exporter.
124. With regard to the submission that KKKOM has also exported the subject goods through distributors, the Authority notes that all the sales by KKKOM were directly to Indian customers.
125. With regard to non-filing of response by M/s Nat Oleo , the Authority notes that Nat Oleo is neither involved in the manufacture of subject goods nor have they exported the subject goods to India during the POI.
126. With regard to the deduction of SGA expenses and profits of M/s Adani Wilmar Ltd, the Authority notes that Adani Wilmar is acting as a mere commission agent and the commission paid to Adani Wilmar has already been deducted from the export price.
127. With regard to the non-disclosure of an affiliated entity M/s Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd Malaysia by Thai fatty Alcohol Ltd., the Authority notes that Emery Oleochemicals is not closely related to Thai Fatty Alcohol and nor does it share direct common ownership and control with TFA. Moreover, Emery Oleochemicals is situated in Malaysia and not in Thailand due to which there is no question of combined dumping margin or normal value calculation. Had the Authority considered M/s Emery Oleochemicals as a separate legal entity, it would have treated it with Malaysia as a subject country and not Thailand.
128. With regard to PTMAS the submission regarding various plants in Indonesia, it is noted from the submissions of the PT MMAS that they have only one plant in Indonesia for production of subject goods. Further, they have also submitted that they do not have any related party in India relating to subject goods. Two entities reflected on their website, are engaged in refining palm oil for food purpose and they have no connection whatsoever with subject goods.
129. With regard to the issue of Desk verification and accuracy of the information submitted by the concerned producer and exporters, the Authority has done thorough and detailed checking of the finance and cost data including domestic sales and exports invoices to India. The Authority has also corroborated the exports to India from the DGCIS data to check the veracity of the information supplied by the producers and exporters. Moreover, it is the discretion of the Authority to conduct verification at the premises of the exporters or do table study. There is no past practice of the Authority to issue verification report in case desk verification is carried out. Further, all this information is confidential in nature and not amenable to summarization. The Authority does not disclose the verification reports of domestic industry to other interested parties and vice-versa.
130. Injury parameters data are taken from the data provided in CI of the Domestic Industry.
131. With regard to the submission of the DI that the Authority has acknowledged the claim of domestic industry that it may suffer intensified injury post expiry of duty, the Authority notes that authority has not examined any injury factor in detail at the time of initiation and merely acknowledged the claim made by the domestic industry. A mere acknowledgement of claim does not tantamount to its acceptance.
132. The Authority has already disclosed the methodology of computation of NIP and calculation of price underselling in the disclosure statement.
133. Request made by M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapore has been relooked. The Authority noted that the adjustments made are based on the actual data provided by them and on the basis of the consistent practice followed consistently.

134. The Authority notes that the issues relating to safeguard findings and adjustment plan had already been addressed in the disclosure statement.
135. In relation to issues relating to causal link, it is noted that Domestic Industry is suffering injury due to dumped imports subject countries.
136. Domestic Industry had filed Writ Petition bearing (L) No.1146 of 2018 before the Hon'ble Bombay High Court regarding issues relating to non-injurious price, breach of natural justice and non-disclosure of certain information. The Domestic Industry has now withdrawn their writ petition.

Conclusions

137. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that the product under consideration exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the product. Some of the imports are also causing material injury to the domestic industry.

Recommendations

138. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
139. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive antidumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from subject countries in the form and manner described hereunder.
140. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from subject countries.

Duty Table

<u>S.No</u>	<u>Heading/ Sub Heading</u>	<u>Description of Goods</u>	<u>Country of origin</u>	<u>Country of exports</u>	<u>Producer</u>	<u>Exporter</u>	<u>Amount</u>	<u>Unit</u>	<u>Currency</u>
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2905.17, 2905.19, 3823.70	"All types of Saturated Fatty Alcohols excluding Capryl Alcohols (C-8) and Decyl Alcohols (C-10) and blends of C8 and C10".	Indonesia	Singapore	M/s PT Ecogreen Oleochemicals	M/s Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd.	NIL	MT	USD

2	-do-	-do-	Indonesia	Singapore	M/s PT Musim Mas	M/s Inter-Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore	7.10	MT	USD
3	-do-	-do-	Indonesia	Singapore	M/s PT Wilmar Nabati	M/s Wilmar Trading Pte Ltd., Singapore	52.23	MT	USD
4	-do-	-do-	Indonesia	Any	Any	Any	92.23	MT	USD
5	-do-	-do-	Any	Indonesia	Any	Any	92.23	MT	USD
6	-do-	-do-	Malaysia	Singapore	M/s FPG Oleochemicals Sdh Bhd	M/s Procter & Gamble International Operations SA, Singapore	17.64	MT	USD
7	-do-	-do-	Malaysia	Malaysia	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	M/s KL - Kepong Oleomas Sdn Bhd	Nil	MT	USD
8	-do-	-do-	Malaysia	Any	Any	Any	37.64	MT	USD
9	-do-	-do-	Any	Malaysia	Any	Any	37.64	MT	USD
10	-do-	-do-	Thailand	Thailand	M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	M/s Thai Fatty Alcohols Co. Ltd.	NIL	MT	USD
11	-do-	-do-	Thailand	Any	Any	Any	22.50	MT	USD
12	-do-	-do-	Any	Thailand	Any	Any	22.50	MT	USD

141. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
142. An appeal against the order of the Central Government arising out of this finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority